हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 08 मार्च, 2017 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

08.03.2017/1100/जेके/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 3351

श्री महेन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आपने सूचना सभा पटल पर रखने की बात कही है वह सूचना तो हमारे पास अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमने आपको अनेकों चार्जशीटें वर्तमान सरकार जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, I stand to correct. इनके प्रश्न का ज़वाब यह है, सूचना अभी भी एकत्रित की जा रही है।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, आज तक क्या-क्या इन्क्वायरी की गई है और क्या उसमें कार्रवाई की गई है? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक चार्जशीट वर्ष 1998 में पंडित सुख राम जी ने आपके खिलाफ दी थी क्या उस चार्जशीट पर जो आरोप पंडित सुख राम जी ने लगाए थे क्या अब आपका और पंडित सुख राम जी का आपस में समझौता हो गया है, क्योंकि उनके बेटे को आपने अपने मंत्रिमण्डल में शामिल किया है?

दूसरे, हमने एक चार्जशीट वर्ष 2007 में दी है और एक चार्जशीट हमने वर्ष 2014 में दी है।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर है कि सूचना अभी भी एकत्रित की जा रही है। दूसरा प्रश्न भी इन्हीं का है।

श्री महेन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी हमारा क्या कसूर है? ये सच्चाई को छिपाना चाहते हैं, क्योंकि जो इनके पास सूचना आई हुई है और इन्होंने पहले उत्तर दिया उस उत्तर में था कि इन्होंने उसकी इन्क्वायरी की हुई है। सच्चाई इन्होंने सामने लाई है अब उस सच्चाई के माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तीन-चार सीटों पर आपका एक ही कार्यकाल नहीं बल्कि दूसरा कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है लेकिन अभी तक

इस हाऊस को, इस प्रदेश की जनता को कोई ऐसा पता नहीं चला कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो गम्भीर आरोप वर्तमान

08.03.2017/1100/जेके/डीसी/2

सरकार के खिलाफ विभिन्न विभागों व विभागों के मंत्रियों के ऊपर लगाए गए थे उन पर आपने आज तक क्या-क्या कार्रवाई की है?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इनका जो प्रश्न 3351 है इसका ज़वाब है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। इनका जो दूसरा प्रश्न था मैंने उसका उत्तर दे दिया। हम किसी से डरते नहीं है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

08.03.2017/1105/SS-DC/1

प्रश्न संख्याः 3351 क्रमागत

मुख्य मंत्री क्रमागतः

जो भी जवाब होगा आपके सामने रखा जायेगा। हमारी कोशिश होगी कि जल्दी-से-जल्दी सारे कागज़ात देखकर आपको उत्तर दिया जाए।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से प्रदेश की जनता को आश्वस्त करवायेंगे कि आज तक जो हमने चार्जशीट्स दी हैं क्या इसी बजट सत्र के दौरान उन सारी चार्जशीट्स की इंवैस्टीगेशन करके उसमें जो मामले सत्य पाये जायेंगे उनमें ऐक्शन ले करके इस माननीय सदन में रिप्लाई देने के लिए तैयार हैं? क्या यह आश्वासन माननीय मुख्य मंत्री जी देंगे?

मुख्य मंत्रीः जब भी उत्तर बनेगा, हाउस में रखा जायेगा।

08.03.2017/1105/SS-DC/2

प्रश्न संख्याः 3624 (स्थगित)

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, पहले तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्री जी काफी कंफ्यूजड हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक तो जो मैंने प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का उत्तर जैसे-जैसे मैंने पूछा था वैसे-वैसे नहीं दिया गया है।

दूसरा, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके उत्तर में आया है कि इस प्रदेश के अंदर लोक निर्माण विभाग ने चाहे वह नेशनल हाईवे है या स्टेट सैक्टर है, 38400.69 रनिंग मीटर क्रैश बैरियर लगाये हैं। मुख्य मंत्री जी, इसी हाउस के बीच में क्रैश बैरियर को लेकर एक प्रश्न माननीय महेश्वर सिंह जी का लगा था। वह प्रश्न संख्या 2016 दिनांक 7.4.2015 को लगा और उसमें आपने उत्तर में लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो क्रैश बैरियर लगे उनकी कुल लम्बाई 1,25,029.00 रनिंग मीटर है। जो 2015 का उत्तर है उसमें आप कह रहे हैं कि 1,25,029.00 रनिंग मीटर लम्बाई है लेकिन आज प्रश्न के उत्तर में आ रहा है कि कुल लम्बाई 38400.69 रनिंग मीटर है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब इस माननीय सदन के माध्यम से किसी विभाग से प्रश्न का उत्तर पूछा जाता है तो विभाग क्यों इतनी लापरवाही से इस माननीय सदन को उत्तर देता है? आपने कहा कि आपने 11 करोड़ 49 लाख 17 हजार के क्रैश बैरियर लगाये हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को अवगत करवाना चाहता हूं कि 2015 तक आपने 42 करोड़ 50 लाख के क्रैश बैरियर लगाए हैं। अब हम आपके किस उत्तर को ठीक समझें? जो आज का उत्तर है इसको ठीक समझें या 2015 के उत्तर को ठीक समझें? --(व्यवधान)-- मुख्य मंत्री जी बैठेंगे, मेरी बात को सुनेंगे तभी मैं बोलूंगा। नहीं तो ये फिर कहेंगे कि मैंने सुना नहीं है। तो दोबारा फिर वही बात होगी।

मुख्य मंत्रीः मैंने आपकी बात को सुन लिया है।

जारी श्रीमती के0एस0

08.03.2017/1110/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 3624 जारी---

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके विभाग का एक उत्तर इस हाऊस में आया कि हमने 07.04.2015 तक कुल लम्बाई 1,25,29 रनिंग मीटर के क्रश बैरियर लगाए जिसके ऊपर हमने 42 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च किए। आज आप उत्तर दे रहे हैं कि हमने केवल 38,400 रनिंग मीटर क्रैश बैरियर लगाए और उनके हमने 11 करोड़ 49 लाख 17 हजार की पेमैंट की। माननीय मुख्य मंत्री जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या वह पहले वाले प्रश्न का उत्तर सही है या आज का उत्तर सही है? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो क्रश बैरियर हिमाचल प्रदेश की सड़कों के किनारे लगाए जा रहे हैं उनमें तीन पाट्र्स लगते हैं। आज हिमाचल प्रदेश की सड़कों के अंदर अनेकों ऐसे क्रैश बैरियर हैं जिनमें तीन की जगह दो पाट्र्स लगाए गए हैं। क्या जहां कम पार्ट लगाए गए हैं, पूरी पेमैंट दी गई है, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी आप पूरे प्रदेश के अन्दर विभिन्न मण्डलों में, सब-डिविज़नों में, सैक्शन्ज़ में क्या इसकी छानबीन के आदेश करेंगें? मैं यह भी जानना चाहता हूं।

मुख्य मंत्रीः माननीय सदस्य, बैठ जाईए। अगला प्रश्न बाद में पूछना। अगर आप एक ही बारी में 10 चीजें बता देंगें तो मुझे कैसे याद रहेगा? एक बात पूछो उसका जवाब आने दो उसके बाद अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस तरह से बोल रहे हैं जैसे इन्होंने बहुत ही रहस्यमयी बात कर ली हो। जो क्रैश बैरियर के बारे में हमने पहले कहा था वह नेशनल हाईवेज़ में जो लगे हैं उसका है और कितने लगे हैं उसके बारे में हमने बताया है। उसकी पेमैंट नैशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा की जाती है। जहां तक इन्होंने 38,400 रनिंग मीटर

क्रैश बैरियर की बात की, यह स्टेट पी.डब्ल्यू.डी. ने परचेज़ किए हैं। यह फर्क है। इसमें रहस्य की कोई बात नहीं है।

08.03.2017/1110/केएस/एजी/2

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या पी.डब्ल्यू.डी. विभाग का ही एक विंग नेशनल हाईवे है या नेशनल हाईवे पी.डब्ल्यू.डी. से अलग है? मैंने तो लोक निर्माण विभाग का प्रश्न पूछा है। मैंने स्टेट सैक्टर का प्रश्न नहीं पूछा है। लोक निर्माण विभाग के अंदर आपका नेशनल हाईवे का विंग भी है, क्वालिटी कंट्रोल का विंग भी है और आपके सारे लोक निर्माण विभाग के जितने भी चार जोन हैं, वे भी इसमें शामिल है। जब मेरा प्रश्न ही पूरे लोक निर्माण विभाग का है, आपको अधिकारी मिसलीड कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलत रिप्लाई दिया हुआ है। अध्यक्ष जी, अब मैं स्टील के बारे में कहना चाहता हूं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पहले मैं आपके रिमार्क के बारे में बोलता हूं क्योंकि जो आपने बोला the remark has been recorded. इसका उत्तर देना मेरा फर्ज़ है फिर आप पूछिए। जहां तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी का प्रश्न है, the work is done on behalf of National Highway. Either they give it to some contractor or they give it to the State PWD. तो जो-जो हमने पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया था, वह था जो क्रैश बैरियर्ज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के काम में सड़कों पर लगा। अगर आप प्रश्न में यह कहते कि नेशनल हाईवे का काम यदि आपने किया है उसमें कितने क्रैश बैरियर्ज़ लगे हैं तो उसका उत्तर हो सकता था। दूसरा प्रश्न आपका बिल्कुल अलग है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि be specific. पी.डब्ल्यू.डी. अलग है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी अलग है। कई दफा नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम भी पी.डब्ल्यू.डी. लेती है और उसका सारा लेखा जोखा नेशनल हाईवे को दिया जाता है।

श्री महेन्द्र सिंह जी अ0व0 की बारी में-

8.3.2017/1115/av/aG/1

प्रश्न संख्या : 3624 ---------- क्रमागत

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाई वे लोक निर्माण विभाग का एक विंग है न कि नेशनल हाई वे ऑथोरिटी लोक निर्माण विभाग से अलग है। आपने पूरे प्रदेश में जो सरिया क्रय किया हुआ है उसके बारे में आपने उत्तर में लिखा है कि वर्ष 2013-14 में (व्यवधान-) अध्यक्ष जी, अब मैं किससे प्रश्न पूछुं। (मुख्य मंत्री जी द्वारा सम्बंधित विभाग के अधिकारियों के साथ वार्तालाप करने पर कहा गया।)

अध्यक्ष : आप बोलते जाइए। माननीय मुख्य मंत्री जी आपकी बात सुन रहे हैं।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, कहां सुन रहे हैं? फिर मुख्य मंत्री जी दोबारा बोलेंगे कि मुझे प्रश्न का पता नहीं चला।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, फिर आप दोबारा बोल देना।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, फिर आप मुझे बोलने का समय नहीं देंगे। फिर आप बोलेंगे कि बहुत हो गया। मुख्य मंत्री जी को यहां आने दो। जब माननीय मुख्य मंत्री जी हमारी बात सीट पर बैठकर सुनेंगे ही नहीं तो जवाब कैसे दे पायेंगे? अब ये मेरी बात सुनेंगे या अधिकारियों की ब्रीफिंग सुनेंगे? अधिकारियों को ब्रीफिंग इनके चैम्बर में करनी चाहिए थी।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको जवाब दे दिया है और आप बार-बार प्रश्न कर रहे हैं।

श्री महेन्द्र सिंह : मुख्य मंत्री जी, प्रश्न करना हमारा अधिकार है।

मुख्य मंत्री : मैं जानता हूं कि प्रश्न पूछना आपका अधिकार है। मगर यह अधिकार केवल आपका ही नहीं है। यहां पर जिन अन्य माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछे हैं उन्हें भी उत्तर पाने का अधिकार है। You monopolize all the time. Be brief and to the point.

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, मैं स्टील के बारे में पूछ रहा था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछ रहा था कि आपने उत्तर में वर्ष 2013-14 में शिमला जोन में 4253 मीट्रिक टन स्टील क्रय किया जिसके लिए आपने 16,91,5000/- रुपये की राशि अदा की है। इसी तरह आपने शिमला जोन में ही वर्ष 2014-15 में 10614.43 मीट्रिक टन सरिया खरीदा। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि जब आप 4253 मीट्रिक टन सरिया खरीदते हैं तो 16.91 करोड़ रुपये की पेमैंट करते हैं। जब आप 10614 मीट्रिक टन सरिया खरीदते हैं तो आप 14.90 करोड़ रुपये की राशि अदा करते हैं। 4253 मीट्रिक टन सरिया की कीमती 16.91 और 10614 मीट्रिक टन सरिया की 14.90 करोड़ रुपये है; यह कौन सा पैमाना है? लोक निर्माण विभाग ने पहले इतनी महंगी दरों पर सरिया क्यों खरीदा जबकि आपके विभाग को इतनी सस्ती दरों पर सरिया मिल रहा था। इसी संदर्भ में वर्ष 2015-16 में कांगड़ा जोन में (---व्यवधान---) मुख्य मंत्री जी सीट से उठकर फिर चले गये तो मेरा क्या कसूर है?

अध्यक्ष : आप बोलते जाइए, मुख्य मंत्री जी आपको सुन लेंगे। He replies his way.

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा क्या कसूर है? अभी तक एक ही सप्लीमैंटरी पूरी नहीं हुई है। अभी तो चार सप्लीमैंटरी और है।

Speaker: I can't allow more than three supplementaries. यह गलत बात है।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, अगर विभाग और सरकार जवाब दे तब तो हम सीट पर बैठकर सैटिसफाई हो जाएं।

अध्यक्ष : आप लिखित में दिए गए जवाब को पढ़ लीजिए।

श्री महेन्द्र सिंह : यह तो मुख्य मंत्री या किसी भी मंत्री का काम है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले वह तैयारी करके आए। वहां चैम्बर में सचिव या विभाग के अधिकारियों

को बुलाए। यह काम हमारा नहीं है। हमारा काम सप्लीमैंटरी पूछना है। मुख्य मंत्री जी बार-बार अपनी सीट से उठकर अधिकारियों के पास जा रहे हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अनलिमिटिड सप्लीमैंटरी नहीं की जा सकती।

8.3.2017/1115/av/aG/3

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, अनलिमिटिड सप्लीमैंटरी नहीं है बल्कि मुख्य मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

अध्यक्ष : जवाब तो दे रहे हैं। He is consulting the figures.

Chief Minister: Speaker, Sir, I am replying to all the queries. माननीय सदस्य 'बाल की खाल उतारना' चाह रहे हैं। मैंने कह दिया है कि what I had to say, I have already said it. मगर मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो नेशनल हाई वे ऑथोरिटी का काम होता है और जो स्टेट का भी काम होता है उसके लिए जो स्टील है ,

English by AS . . .

08/03/2017/1120/टी0सी0वी0/ए0एस0/1
प्रश्न संः 3624 क्रमागत

Hon'ble Chief Minister contd--

It is invariably bought from the Steel Authority of India उनके रेट कांट्रेक्ट होते है, उसके मुताबि़क स्टील लिया जाता है। जहां तक बिच्चुमन की बात है, उसमें भी यही प्रक्रिया होती है, जो नेशनल कंपनीज़ हैं, उनका टेंडर होता है, उसके मुताबिक बिच्चुमन लिया जाता है, वह कभी घटता है और कभी वह बढ़ जाता है। एक सड़क में जो काम होता है It was on behalf of the National Highway Authority of India. We were only working for them. दूसरा जो है that was constructed by the P.W.D itself.

श्री महेन्द्र सिंहः माननीय मुख्य मंत्री जी आपका कसूर नहीं है, आप साईड में चले गये थे। मेरा प्रश्न है कि जब आप थोड़ा-सा सरिया खरीदते हैं, जैसे आपने 4253 मिट्रिक टन सरिया खरीदा तो आपने 16 करोड़ दिए, लेकिन जब आपने 10614 मिट्रिक टन सरिया खरीदा तो आपने 14 करोड़ दिए। ये गैप किस कारण से हैं? मैं माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि यह जो इतना बड़ा गैप है और जो क्रय की प्रक्रिया है, इस क्रय की प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठ रहे हैं या फिर जो सूचना दी गई है, वह सूचना ही गलत है।

मुख्य मंत्रीः सुनिये, यदि मैं स्पीकर होता, तो मैं कहता कि reject it. आप इतनी बेहुदा सूचना मांगते हैं। It is wastage of papers. अगर मैं प्रश्न करूं कि 5 साल की उम्र से लेकर आज तक माननीय सदस्य (श्री महेन्द्र सिंह) ने कितना खाना खाया है, कितने कपड़े पहने हैं, कितने उसने घर बनाये हैं, कितनी उसने सम्पत्ति इकट्ठी की है, is it valid?

Shri Mahender Singh: Yes, it is valid.

Chief Minister: Next time I will ask this Question about you. अध्यक्ष महोदय, पूरा voluminous रिप्लाई इसके अन्दर दिया गया है। कृपा करके बैठकर पढ़ने की कोशिश करें और उसके बाद भी किसी बात से आप संतुष्ट न हों, तब जाकर आप प्रश्न पूछिए। पहले इसको पढ़कर देखो।

08/03/2017/1120/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

प्रश्न संख्याः 3751

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पहले तो मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, इन्होंने काफी फण्डज़ इस बिल्डिंग को बनाने के दिए और इन्होंने 2-3 बार विजिट भी किया। मगर मंत्री महोदय, आप जानते हैं कि हिमुडा बार -बार डेट्स दे रहा है। इन्होंने अगस्त, 2016 में इसको कंप्लीट करने के लिए कहा था, फिर 31 दिसम्बर, 2016 को इसका कार्य कंप्लीट करने के लिए कहा गया था और अब 30

अप्रैल, 2017 को कह रहे हैं। मुझे ये भी व्यावहारिक नहीं लगता है कि ये इसको 30 अप्रैल तक भी कर पाएंगे। ये काम समय के अन्दर कंप्लीट हो, इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? दूसरा, मैं जानना चाहूंगी कि आपने पोलीटैक्निक में पानी की स्कीम के लिए पैसा जमा करवाया था, मेरी जानकारी के मुताबिक उस पैसे का अभी तक कोई उपयोग नहीं हुआ है। उसके टेंडर भी नहीं लगे हैं, काम अगर अवार्ड ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा? जब ये बिल्डिंग बनेगी तो इसमें पानी की असुविधा रहेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि जो पैसा आपने आई0पी0एच0 विभाग को स्कीम बनाने के लिए दिया है, ये सबस्टांशियल अमांऊट है। उनको एडिशनल अमाऊंट चाहिए, तो वे आपसे मांग सकते हैं, लेकिन जो सबस्टांशियल अमाऊंट दिया है, वे पहले उसको उपयोग तो कर लें। क्या आप इन दोनों विभाग को एनश्योर करेंगे कि ये जो डेट इस बार इन्होंने दी है, इसको ये एक्सिड न करें।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, ये काम 2007 में पहली बार अवॉर्ड हुआ था, इसमें 2011 तक कोई भी काम नहीं हुआ।

श्रीमती एन0एस0 ... द्वारा जारी।

08/03/2017/1125/ एन0एस0/डी0सी0 /1

प्रश्न संख्याः 3751 -- क्रमागत

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ----जारी

जब माननीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार आई उसके बाद मैं अपने आप तीन-चार बार वहां जा चुका हूं। हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुझे उसकी पहले कट आउट डेट दी थी और अब उन्होंने 30 अप्रैल कहा है।। will ensure it. मैं 30 अप्रैल की बजाए 30 जून लेकर चल रहा हूं। 30 जून से पहले-पहले हम बिल्डिंग को तैयार कर देंगे। मैंने डायरैक्टर (टैक्निकल ऐजुकेशन) को कहा है कि वे मुझे हर 10 दिन के बाद वहां कितना काम हुआ उसका वट्स ऐप वीडियो भेजते हैं। हम लोग इसको प्रोपरली फॉलो-अप कर रहे हैं। जहां तक पानी की बात है जब मैं वहां गया था तो मैंने अधिकारी भी बुलाए थे और उनको कहकर भी आया था कि इस स्कीम को जल्दी चालू करें। क्योंकि पानी के बिना वहां कॉलेज

चल ही नहीं पायेगा। मैं इसके लिए विभाग को भी बोलूंगा। सेक्रेटरी (आई0पी0एच0) यहीं पर मौजूद हैं, वह इसे नोट कर लें और अन्य अधिकारी भी इसे नोट कर लें। इसको हम 30 जून से पहले-पहले इम्पलीमैंट कर देंगे।

08/03/2017/1125/ एन0एस0/डी0सी0 /2

प्रश्न संख्या : 3752

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : (अनुपस्थित)

08/03/2017/1125/ एन0एस0/डी0सी0 /3

प्रश्न संख्या : 3753

श्री गोविन्द राम शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है। उसके बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैंने जो प्रश्न किया था उसमें पहला प्वाईंट यह था कि सरकार कन्दर से वैरल के लिए बस कब तक चलाएगी? वह सड़क आज से पांच साल पहले पास हो चुकी थी। उसके बाद यह 16 किलोमीटर सड़क पक्की भी हो चुकी है। यह एक इन्टीरियर पंचायत है लेकिन इसमें वैरल का ज़िक्र नहीं हुआ है। केवल यह ज़िक्र हुआ कि यह बस कन्दर तक चलती है। दूसरा, मैंने वागा से कौल तक बस के लिए बात की थी। उसमें आपने कहा कि यह रोड पास नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार यह रोड पास हो चुका है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि कन्दर से वैरल जो कि मेरे क्षेत्र की सबसे इन्टीरियर पंचायत है और उसकी लम्बाई 16 किलोमीटर है तथा उसका रोड पक्का हो चुका है आप इसमें कब तक बस चलायेंगे? तीसरा, शीलघाट से कौल-सनोग के लिए भी मैंने बस का निवेदन किया था। उसमें आपने कहा कि एक साल पहले बस चलाई गई थी। उसमें सवारियां कम थीं लेकिन यह पंचायत बहुत इनटीरियर है। इसके लिए नई बस लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक बस जो अर्की से भराड़ीघाट और भराड़ीघाट से

मटेरनी, जालग होती हुई बलेरा जाती है उस बस को अगर आप नम्होल से कौल-सनोग कर दें तो वहां की जनता को उसका लाभ मिल सकता है। अभी-अभी एक महीना पहले मेरे क्षेत्र में ही नालागढ़ से रामशहर, रामशहर से बाया चमधार, दिग्गल और वापिस वह बस नालागढ़ जाती थी। उस बस को नालागढ़ से बाया चमधार दिग्गल से साई होते हुए कर दिया गया। जो मेरी सात पंचायतें वहां की है उन लोगों को नालागढ़ जाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। उस बस में कर्मचारी, मरीज़ और अन्य लोग भी जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि क्या आप उस बस को पुनः जैसे थी वैसे लगाने का प्रयास करेंगे?

माननीय मंत्री श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

प्रश्न समाप्त---।

08/03/2017/1130/RKS/DC/1

प्रश्न संख्याः 3753...जारी

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सड़क पक्की हो गई है और वह क्षेत्र इंटिरियर भी है। लेकिन उस रूट से इनकम कम आई है। इसमें कर्मिशयल वायबलिटी कैसे आएगी उसके लिए मैं एक छोटी बस या कोई अन्य वाहन को चालू कर दूंगा। दूसरी समस्या जो आपने नालागढ़ की बताई उसके बारे में आप मेरे साथ अलग से बात कर लेना, उसके लिए हम कोई हल निकालेंग

श्री गोविन्द राम शर्माः आदणीय मंत्री जी, जो आपने कन्दर से बैरल के लिए बस चलाने का आश्वासन दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे निवेदन है कि जो बस अर्की से भराड़ीघाट वाया ब्रह्मपुखर, मटेरनी **से जय नगर** होकर बलेरा जाती है उस बस को अगर आप कौल-सनोग के लिए लगा दें, जोकि नम्होल से ऊपर का एरिया है

और उसमें आगे जाकर कसारना पंचायत कवर होती है। उसमें खर्चे की भी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, नालागढ़ से रामशहर वाया चम्बधार, दिग्गल वाली जो मैंने बात कही, उसमें 7 पंचायतें आती हैं और सातों पंचायतों के लोगों के लिए हौस्पिटल, एस.डी.एम. ऑफिस और अन्य ऑफिस भी नालागढ़ में ही है। बहुत से लोग वहां सर्विस करते हैं और उनके बच्चे भी वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे आपने साई के लिए बस उपलब्ध की है और उसकी सुविधा हो सकता है कि दून विधान सभा क्षेत्र वाले लोगों के लिए हो परन्तु जो 7 पंचायतें शेष बचती हैं, इन पंचायतों के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए आप दूसरी बस उपलब्ध करवाने की कृपा करें। क्या मंत्री जी जैसे इस रूट में पहले बस चलती थी, उस बस को दोबारा से चलाने का प्रयास करेंगे?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय सदस्य को पहले ही कहा है कि आप मेरे ऑफिस में आ जाएं। मैं अधिकारियों को बुला लूंगा। कौन से गांव से होकर किधर को बस जाएगी, इसके लिए रूट लेना पड़ता है, यह सब कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है। इसके बारे में हम कंडक्टरों की कमी पूरी होने के बाद सोचेंगे।

08/03/2017/1130/RKS/DC/2

<u>प्रश्न संख्याः 3754</u>

बलबीर सिंह वर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है उसके लिए मैं चौपाल निर्वाचन क्षेत्र और अपनी तरफ से मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा चार वर्ष के कार्यकाल में 300 करोड़ रुपये के करीब-करीब चौपाल निर्वाचन क्षेत्र को नाबार्ड और पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत पैसा मिला है। मैं चौपाल निर्वाचन क्षेत्र और अपनी तरफ से मुख्य मंत्री जी का

इसके लिए धन्यवाद करता हूं। मानीनय मुख्य मंत्री जी मेरा कुछ एरिया स्नो बाउंड एरिया है। मैटलिंग और टारिंग की स्पेस्फिकेशन है। मैटलिंग और टारिंग चाहे आप कांगड़ा में करें या हिल एरिया में करें जहां 5-6 फुट बर्फ पड़ती है, वह एक ही है। जहां ज्यादा बर्फ पड़ती है वहां की टारिंग की थिकनैस ज्यादा होनी चाहिए तभी बर्फ वाले एरिया में वह टारिंग टिकेगी। साथ ही मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि पी.डब्ल्यू.डी. डिवीज़न चौपाल में 8 जे.ई. की पोस्टें खाली हैं। पैसा बहुत आया है। अगर वहां टैक्निकल स्टाफ भी उपलब्ध हो तभी काम में गुणवत्ता रहेगी। यदि टैक्निकल स्टाफ उपलब्ध न हो तो काम की गुणवत्ता नहीं रह सकती क्योंकि रोड़ों में फिर सुपरवाइजर ही इन कामों को करवाते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां 5-5, 6-6 फुट बर्फ गिरती है। सड़कों से बर्फ को हटाने के लिए बुलडोज़र के सिवाय और कोई चारा नहीं है। अगर इस क्षेत्र में स्नो कटर भी उपलब्ध हो तो हमारी मैटलिंग नहीं उखड़ेगी।

मुख्य मंत्री श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

08.03.2017/1135/SLS-DC-1

प्रश्न संख्या : 3754 ...क्रमागत

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि चौपाल, जो किसी समय सड़कों के मामले में, शिक्षा के मामले और दूसरे विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, आज सरकार की कोशिश से और विधायक द्वारा उठाए गए कदमों के कारण, इन सबको मिलाकर, चौपाल आज तरक्की में बहुत आगे बढ़ा है। यह नहीं कि सभी काम हो गए हैं, लेकिन पहले के मुकाबले में स्थिति कहीं बेहतर है। जो इन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां अधिक बर्फ़ पड़ती है वहां मैटलिंग की थिकनैस ज्यादा होनी चाहिए, यह बात मैंने लोक निर्माण विभाग को कई दफ़ा बताई है। दूसरे क्षेत्रों में जहां मैदानी इलाका भी है या कम पहाड़ी इलाका है, गर्म इलाका है, जब हम वहां के लिए जाते

हैं तो चौपाल की ही तरह वहां के लिए भी बर्फीले इलाके से गुज़रना पड़ सकता है। इसलिए वहां पर भी मैटलिंग काफी थिक होनी चाहिए ताकि वह बर्फ़ से खराब न हो पाए। लोक निर्माण विभाग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चौपाल की ही बात नहीं है, हर उस जगह पर जहां ज्यादा वर्षा होती है या ज्यादा बर्फ़ गिरती है, वहां पर मैटलिंग करते यह ध्यान रखना चाहिए कि वहां की जो थिकनैस है, वह इस तरह की होनी चाहिए कि वर्षा या बर्फ़ से उसको नुकसान न हो। **इन्होंने यह भी कहा है कि इनके यहां जे.ईज. की कमी है। हमारे लोक निर्माण विभाग के सचिव यहां पर बैठे हुए हैं, वह इस बात को नोट करेंगे कि जितने जे.ईज. की वहां कमी है, उनको तुरंत वहां पर नियुक्त किया जाए।**

श्री बलबीर सिंह वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में बर्फ़ बहुत ज्यादा गिरती है। अगर हमें वहां पर स्नो कटर उपलब्ध हो जाएं तो अच्छा होगा अन्यथा हमें बर्फ़ को हटाने के लिए डी-5 बुलडोजर लगाने पड़ते हैं जिनसे मैटल की हुई सड़क उखड़ जाती है। जे.सी.बी. से 5, 6-6 फुट बर्फ़ नहीं हट सकती। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि मेरी कम-से-कम 27-28 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें 5-5 फुट से ऊपर बर्फ़

08.03.2017/1135/SLS-DC-2

गिरती है। इन पंचायतों को हम डी-50 बुलडोजर लगाकर ही खोल पाते हैं। अगर हमें स्नो कटर उपलब्ध हो जाएं तो हमारी मैटल हो चुकी सड़कें उखड़ेगी नहीं।

मुख्य मंत्री : यह एक अच्छा सुझाव है और मैं समझता हूं कि लोक निर्माण विभाग को स्नो कटर रखने चाहिए। खासकर उस क्षेत्र के लिए जहां पर बर्फ़ ज्यादा गिरती है और जहां सर्दियों में बर्फ़ को हटाने का काम होता है। Government will look into the matter.

08.03.2017/1135/SLS-DC-3

प्रश्न संख्या : 3755

श्री रवि ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि my Question's answer have been total denial. मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हम जो प्रश्न करते हैं, उसकी समीक्षा प्रश्न करने से पहले हम किससे करें? मैंने किसानों से पूछा जो कि लाहौल स्पिति की 95 प्रतिशत आबादी है। उसके बाद मैंने अधिकारियों से भी पूछा और जो शिमला में वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे भी बात हुई। उन्होंने यही कहा कि जो पॉवर टिलर है, इसमें भारत सरकार की नीति है कि यह 12-1/2 बीघा से कम को नहीं दिया जा सकता; 12-1/2 बीघा से ज्यादा ज़मीन वाले को ही दिया जा सकता है। मेरा प्रश्न यह है कि जो वहां पर छोटे बागवान और छोटे किसान हैं, जिनकी ज़मीन या लैंड होल्डिंग बहुत कम है, 5 बीघा तक की लैंड होल्डिंग वाले किसानों को भी इसे खरीदने की इज़ाज़त दी जाए। किसान भी यही रोना रो रहे हैं और वहां के पंचायती राज के लोग भी मुझसे बार-बार यही गुज़ारिश कर रहे हैं कि इसको एग्जंप्ट किया जाए।

जारी ...गर्ग जी

08/03/2017/1140/RG/AG/1

प्रश्न सं. 3755--क्रमागत

श्री रवि ठाकुर----क्रमागत

और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जो शिमला में हैं उन्होंने भी मुझे यह बताया कि इसको बहुत जल्द स्वीकृत कर दिया जाएगा। इसलिए माननीय मंत्री इसका उत्तर दें और क्या इसकी समीक्षा करके कृपया मुझे बताएं?

बहुउद्देश्यीय परियोजना एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए जमीन की एक इंच की लिमिट भी नहीं रखी गई है। किसान के पास जमीन है या नहीं, वह आवेदन करे और

वह पॉवर ट्रिलर ले सकता है। यह पॉवर ट्रिलर का मसला है जिसकी कीमत लगभग डेढ़ लाख रुपये है और इसमें हम 50% सब्सिडी देते हैं जो लगभग 75,00,000/-रुपये बनती है।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि प्रश्नकर्ता ने नीतिगत प्रश्न पूछा है और मंत्री जी ने अब जवाब दिया कि यह सभी के लिए खुला है और इसमें किसी भी किसान को कोई रोक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसी सन्दर्भ में कल मैंने एक अतारांकित प्रश्न संख्या 1588 पूछा था जिसमें यह पूछा गया था कि कितने किसानों को यह सब्सिडी की राशि गत तीन वर्षों से लेकर देय है जिसका भुगतान सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। तो केवल पांच जिलों की मेरे पास डिटेल आई जिसमें सिरमौर, कुल्लू, सोलन, शिमला और किन्नौर है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक वर्ष 2013-14 की भी पैण्डेंसी है और शिमला जिला की तो वर्ष 2011-12 से लेकर पैण्डेंसी है। जो कुल राशि देय है यदि मैं सारी डिटेल पढ़ूंगा, तो ज्यादा समय लगेगा। यह कुल देय राशि 14,48,00,000/-रुपये है और 9,092 इस प्रकार के बागवान हैं जो रोज इनके विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको सब्सिडी अमाउन्ट नहीं मिल रहा है। इस सारे के अवलोकन से आपको भी लगेगा कि इसमें पिक एण्ड चूज होता है। अन्यथा वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2011-12 की आज तक पैण्डेंसी कैसे है? इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे और जो इतनी पैण्डेंसी है इसको समाप्त करने के लिए एक मुश्त बजट का प्रावधान करके इस प्रकार के किसानों को दे दी जाए और भविष्य के लिए एक नीति बनाएं ताकि पैण्डेंसी न रहे?

08/03/2017/1140/RG/AG/2

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो सिर्फ लाहौल-स्पीति का है, लेकिन इन्होंने इसमें पूरा हिमाचल प्रदेश ही ले लिया। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि आप मेरे पास यह सारा रिकॉर्ड दे देना फिर मैं इसको स्टडी करके आपको जवाब दे दूंगा।

Shri Maheshwar Singh: This is not the question. इन्होंने कहा कि यह सब्सिडी सबके लिए खुली है और मेरा प्रश्न बिल्कुल इससे ही संबंधित है। कल माननीय मंत्री जी ने इसका जवाब दिया है। जब मैं इनके ध्यान में ला रहा हूं कि 14,48,00,000/-रुपये की राशि देय है, तो प्रश्न तो सिर्फ इतना है। इसके अलावा मुझे और क्या कहना है? क्या मंत्री महोदय ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो यह राशि 9,092 किसानों को देय है इनकी पैण्डेंसी खत्म हो और भविष्य के लिए क्या कोई ऐसी नीति बनाएंगे कि जैसे ही वह यह क्रय करता है कम-से-कम उसी वर्ष में उसे यह पैसा मिलना चाहिए?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह पता करुंगा कि पोजीशन क्या है?

08/03/2017/1140/RG/AG/3

प्रश्न सं. 3756

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना यहां सभा पटल पर रखी गई है और 'क' भाग के प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि पी.टी.ए. अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. संख्या फलाना-फलाना लंबित है जिसके अन्तरिम आदेश दिनांक 13-02-2017 की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। यह परिशिष्ट 'क' इसमें दिया गया है और उच्चतम न्यायालय ने जो अन्तरिम आदेश किए हैं उसमें उन्होंने कहा है, मैं अन्त का पढ़ता हूं :- Leave granted. In the meanwhile, it is open to the State of Himachal Pradesh to make any appointment by following the competitive method/procedure by giving equal opportunity to all the eligible candidates.

एम.एस. द्वारा जारी

08/03/2017/1145/MS/AG/1

प्रश्न संख्या: 3756 क्रमागत---

श्री रविन्द्र सिंह जारी--------

क्या सारे प्रदेश में जो योग्य कण्डीडेट हैं, इस नीति के अंतर्गत, पी0टी0ए0 के माध्यम से आपने कोई एप्लीकेशन्ज प्रदेश स्तर पर कॉल की? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगाई है। आपने केवल-मात्र पिक एण्ड चूज किया। जो आपके चहेते वहां आवेदक थे उनको लगा दिया। जो 33 और 35 प्रतिशत नम्बर वाले थे उनको लगा दिया और आपने रोस्टर भी फोलो नहीं किया। जो रिजर्वेशन पी0टी0ए0 के मामले में इस नीति के अंतर्गत मिलनी चाहिए थी आपने उसको भी पूरे प्रदेश में फोलो नहीं किया। प्रश्न के "ख" भाग में जो हमने आपसे पूछना चाहा था कि सरकार प्रदेश में कार्यरत्त पी0टी0ए0, पैट और एस0एम0सी0 योजनाओं के अंतर्गत नियुक्त अध्यापकों को कब तक नियमित कर देगी? आपने लिखित उत्तर में न्यायालय की डायरैक्शन का जो हवाला दिया है वह पी0टी0ए0 पर दिया है। पैट और एस0एम0सी0 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला या इंटेरिम ऑर्डर नहीं किए हैं। क्या आप बताएंगे कि पी0टी0ए0, पैट और एस0एम0सी0 की योजना के अंतर्गत कितनी संख्या इन अध्यापकों की है? मैं जानना चाहूंगा कि पी0टी0ए0, पैट और एस0एम0सी0 के कितने अध्यापक आपने नियुक्त किए हैं? मुख्य मंत्री जी इन बेचारे पढ़े-लिखे बेरोजगारों के साथ जो आप घोर अन्याय कर रहे हैं उनके भविष्य के बारे में सोचिए। आपने पी0टी0ए0, पैट और एस0एम0सी0 किसी की भी नीति नहीं बनाई है और न ही इन तीनों के अंतर्गत आपने रोस्टर फोलो किया है। क्या आप ये सारी योजनाएं बनाने से पहले इस नीति को बनाएंगे? इस केस में 10 वकील वहां पर 17 फरवरी को हाजिर हुए। प्रदेश के खजाने से वहां पर कितना पैसा लगा, मुख्य मंत्री महोदय आप ये सारी जानकारी क्या यहां पर उपलब्ध करवाएंगे?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको याद होगा कि पी0टी0ए0 वही लोग हैं जिनके ऊपर जब आपकी सरकार थी तो घोड़े दौड़ाए गए, उनको पीटा गया, उन पर अत्याचार किए गए और उनको पीड़ित किया गया। बजाए उनकी समस्याओं के समाधान के आपने

उनको उत्पीड़ित किया। चाहे पी0टी0ए0, पैट, एस0एम0सी0 या कोई भी कैटेगरी हो क्योंकि पिछले लम्बे समय से ये प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं इसलिए हमारी सरकार चाहती है कि ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे सभी लोग चाहे वे प्रदेश में इस कैटेगरी में कहीं भी हों, उनकी सर्विसिज नियमित की जा सके। यह हमारी नीति है और इस नीति को हम कोर्ट की डायरैक्शन और अपने तौर पर कोई और रास्ता निकालकर लागू करेंगे।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, मेरा मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी विषय को इधर-उधर भटकाने की कोशिश मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने घोड़े दौड़ाए, उत्तेजित किया, पीटा या ऐसा-वैसा किया, आपको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता है।

Chief Minister: It is a fact of history. आज आप उनके लिए आंसू बहा रहे हैं। यह मैं आपमें बड़ा परिवर्तन पा रहा हूं।

श्री रविन्द्र सिंहः मुख्य मंत्री महोदय, हम कोई आंसू नहीं बहा रहे हैं। आपने कोई नीति नहीं बनाई है। हम उस नीति की बात कर रहे हैं। आपने पी0टी0ए0, पैट और एस0एम0सी0 वालों से वोट भी लिए हैं लेकिन आपने आज तक किसी की कोई नीति नहीं बनाई है। हम उसकी बात कर रहे हैं। ये जो ज्यादा हरी टोपियां आपके उस वर्ग के लोग लगाते हैं क्या इनके वर्ग के लिए आपने पी0टी0ए0, पैट और एस0एम0सी0 के लिए कोई रोस्टर लागू किया है? हम आपसे यह पूछना चाहते हैं? इस प्रदेश में 18 प्रतिशत ओ0बी0सी0, 26 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 9 प्रतिशत से ऊपर अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। क्या इस नीति को बनाने के लिए आपने उन लोगों की चिन्ता की? हमारी वह चिन्ता है। हमने घोड़े दौड़ाए हैं या नहीं, यह हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं। मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं कि आपने यहां एक और नीति ऑउट-सोर्सिंग की लागू कर दी है।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

08.03.2017/1150/जेके/एएस/1

प्रश्न संख्याः 3756ः-------जारी-------

श्री रविन्द्र सिंहः-----जारी-----

आऊट सोर्सिंग के लिए आपने एक नया मैटर खड़ा कर दिया। क्या उसकी कोई आपने नीति बनाई है या शुरू ही की है? कम से कम आप उसकी तो नीति बना लो। आप सुप्रीम कोर्ट में फिर जाएंगे और प्रदेश के खजाने का करोड़ों रूपया वेस्ट करेंगे।

मुख्य मंत्रीः आप बजट का इन्तजार कीजिए आपको उत्तर मिल जाएगा।

श्री रविन्द्र सिंहः अब इन्तजार क्या करना है अब तो आपका वक्त हो गया है?

मुख्य मंत्रीः बजट अभी आना है। वह कल या परसों की बात है, सिर्फ एक-दो दिन की बात है। मगर किसी भी केटैगरी की बात है, we are committed for their welfare. We can't exploit the people. जिन्दगी भर हम उनको ठेके पर रखें। जिन्दगी भर उनका जो उचित अधिकार है, उससे हम वंचित रखें। This amounts to exploitation of their work. We are against that. हम देखेंगे, चाहे किसी भी सरकार के समय में भर्ती हुए हों ऐसे लोगों को हम इन्साफ देने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्षः श्री हंस राज जी। इनका भी प्रश्न है। Let him ask the question. मैं यह कह रहा हूं कि इनका भी प्रश्न साथ में है। मुख्य मंत्री जी ने ज़वाब दे दिया है। श्री रविन्द्र सिंह जी।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्य मंत्री जी ने रोस्टर फॉलो किया? क्या प्रदेश के शिक्षा विभाग ने पैट के अन्तर्गत, पी0टी0ए0 के अन्तर्गत,एस0एम0सी0 के अन्तर्गत और अब आने वाले आऊट सोर्सिंग के अन्तर्गत कोई नीति आपने रोस्टर लागू करने की बनाई है? हमारा प्रश्न यह है। इसके बारे में मुख्य मंत्री जी गोल-मोल ज़वाब दे रहे हैं। इसके बारे में मुख्य मंत्री जी आगे चलने से पहले बताएं कि रोस्टर लागू किया या नहीं किया? अगर नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? उस वर्ग को रिजर्वेशन देते हैं या नहीं ?

देते हैं सर एस0सी0 केटेगरी केवल वोट लेने के लिए ही चाहिए, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछ रहा हूं आप इसके बारे में बताएं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सरकार कायदे-कानून के मुताबिक ही काम करती है। Every action of the Government is challengeable. अगर हम गलत काम करेंगे तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है जो उसकी दरूस्ती करता है। जो भी काम होगा वह कानून के दायरे के अन्दर होगा और साथ में मैं आपको यह बताना चाहता हूं जिनके साथ इतने लम्बे अर्से से गैर इंसाफी होती रही है, उनको काम भी देते हैं और उनको आगे बढ़ने का मौका भी नहीं देते हैं, मैं इस नीति के हक में नहीं हूं। People who have served for such a long time must get fair reward. ….(interruption)..

अध्यक्षः श्री हंस राज जी .....(व्यवधान)..... प्लीज, हंस राज जी आप बोलिए।

श्री हंस राजः माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विषय तो पी0टी0ए0, पैट और एस0एम0सी0 .....(व्यवधान)..... माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी जिस तरह से माननीय सदन में ज़वाब दे रहे हैं, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जैसे कि कल किशोरी लाल जी गला फाड़-फाड़ के कह रहे थे।

अध्यक्षः माननीय सदस्य जी, आप केवल अपनी बात रखें।

श्री हंस राजः अध्यक्ष महोदय, बात ही रख रहा हूं। .....(व्यवधान)..... इसमें ऐसा है पी0टी0ए0, एस0एम0सी0 और पैट, पी0टी0ए0 वाले अभी तक 18-18 साल लगा चुके हैं, पैट वाले 14 साल लगा चुके हैं और एस0एम0सी0 वाले वर्ष 2012 से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें मेरा प्रश्न सिर्फ इतना ही है। रिजर्वेशन और रोस्टर की उम्मीद तो हमें इस सरकार से नहीं है। उस बारे में मैं नहीं बालूंगा।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

08.03.2017/1155/SS-AS/1

प्रश्न संख्याः 3756 क्रमागत

श्री हंस राज क्रमागतः

उसकी मैं उम्मीद भी नहीं रखता हूं परन्तु मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि जो पढ़े-लिखे लोग इतने सालों से इस प्रदेश को सर्व कर रहे हैं --(व्यवधान)--

अध्यक्षः उसके बारे में इन्होंने कह दिया है कि पॉलिसी बन रही है।

श्री हंस राजः अध्यक्ष महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं। मेरा क्वैश्चन तो पूरा होने दो। इसमें सिर्फ मेरा पूछने का मात्र इतना उद्देश्य है कि जिन लोगों ने पैट के माध्यम से 14 साल नौकरी में लगा दिए, पी0टी0ए0 वालों ने 18 साल लगा दिए, एस0एम0सी0 वालों ने कई साल लगा दिए, आप ऐसी पॉलिसियों बनाते ही क्यों हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चली जाती हैं? आपके लॉ के ऑफिसर और उससे ज़ड़े हुए व्यक्ति क्यों एप्वाइंट किये हुए हैं, वे क्या करते हैं? ऐसी जाली पॉलिसियां आप लोग लाते क्यों हैं? सफ़र कौन होता है? वहां का स्कूल, वहां के बच्चे और जो युवा 14-14, 18-18 सालों से काम कर रहे हैं वे बेचारे सफ़र होते हैं। अब जो मानीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं, मैं इनसे यह एंश्योर करवाना चाहता हूं कि क्या इसमें रोस्टर को फोलो किया जायेगा? अगर फोलो नहीं होता है तो क्या जो माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, वह इसीलिए कह रहा है क्योंकि आपने अपनी पॉलिसी में फेल्योर रखे हुए हैं तो आप माननीय सदन को बताने की कृपा करेंगे कि जो एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सीज़0 और अदर एक्स-सर्विसमैन का कोटा है उनको इसमें पूरी तवज्जो दी जायेगी, अगर कोई पॉलिसी भविष्य में बनती है? इसमें रोस्टर देंगे या नहीं देंगे? यह मेरा प्रश्न है।

मुख्य मंत्रीः देखिये, मैं यह जनरली कह रहा हूं कि रोस्टर में अगर कोई कमी हो तो हम बैकलॉग को भर के उसको पूरा कर देंगे।

रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, हम बड़ा स्पैसिफिक प्रश्न पूछे रहे हैं कि पी0टी0ए0, पैट, एस0एम0सी0 और आउटसोर्स के अन्तर्गत जो आपने भर्तियां की हैं क्या उसमें रोस्टर फोलो किया या नहीं किया? अगर फोलो नहीं किया तो क्यों नहीं किया?

08.03.2017/1155/SS-AS/2

मुख्य मंत्रीः अभी तो हमने फैसला ही नहीं किया। You are jumping the gun. अभी फैसला हुआ नहीं है और आप शोर मचा रहे हैं।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, एप्वाइंटमैंटस दे दी गई हैं और सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। हमें जवाब नहीं मिल रहा है। ----(व्यवधान)---

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।)

उद्योग मंत्रीः आप लोग पी0टी0ए0, पैट और एस0एम0सी0 के खिलाफ हैं। जो प्रदेश के लोगों को नौकरियां मिली हैं आप उनके खिलाफ हैं। --(व्यवधान)-- जो 2005 से लोग लगे हैं अगर उनको न्याय मिल रहा है तो ये उनके खिलाफ हैं। ये पी0टी0ए0 विरोधी हैं। पैट विरोधी हैं। एस0एम0सी0 विरोधी हैं। नौकरी विरोधी और कर्मचारी विरोधी हैं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो कई किस्म की अनियमितताएं कीं। इन्होंने विद्या उपासक नाम के जो मैट्रिकुलेट थे, सिर्फ दसवीं पास थे उनको प्राईमरी टीचर रखा और इनकी सरकार चली गई। जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो हमने उनको पांच साल तक रखा और पांच साल के बाद उनको जे0बी0टी0 पद पर लगाया on the basis of their teaching in the Government schools. और उनको रेगुलराईज़ कर दिया। यह हमारा रवैया है और इनका रवैया यह है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पी0टी0ए0 रखना आवश्यक है क्योंकि दूर-दराज के इलाकों में टीचर नहीं जाते। बिना टीचर के स्कूल खाली रहे। इसलिए यह पी0टी0ए0 (Parent Teacher Association) की स्कीम बनाई गई और मैं कहना चाहता हूं कि the Government is committed to accommodate these people.

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर पुनः वापिस आए।)

प्रश्न काल समाप्त

जारी श्रीमती के0एस0

08.03.2017/1200/केएस/डीसी/1

<u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

अध्यक्षः अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों से बचाव और नियन्त्रण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 27) की धारा 43 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों से बचाव और नियन्त्रण (पड़ताल चौकी और करंतीन कैम्प, निरीक्षण की रीति) नियम, 2016जोकि अधिसूचना संख्याःएएचवाई-एफ(5)-5/99-पार्ट-IV-Loose दिनांक 17.03.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.04.2016 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

08.03.2017/1200/केएस/डीसी/2

<u>राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारणः</u>

अध्यक्षः अब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर।

अध्यक्षः अब क्या? किस बात पर प्वाइंट ऑफ ऑर्डर? क्या चीज़ है? ---(interruption)--- you can't raise this point. ---(interruption)---. What is your point?

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यह मैम्बर्ज़ के अधिकारों से सम्बन्धित बात है जिसके बारे में मैं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद जो धन्यवाद प्रस्ताव यहां प्रस्तुत हुआ है, उसमें चर्चा में भाग लेते हुए हमारे माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने मण्डी पुलिस के बारे में एक मुद्दा उठाया था। ए.एस.आई. का मुद्दा था जिसने रिज़ाईन कर दिया था क्योंकि उसके ऊपर सरकार का प्रैशर पड़ रहा था और यहां पर भी उसी वक्त धमकियां दी जा रही थी लेकिन यहां पर वह मामला विधायक महोदय ने उठाया और उसके तुरन्त बाद उस ए.एस.आई. रामलाल को विक्टिमाइज़ कर दिया।

अध्यक्षः यह बात तो हो गई है। यह नोटिस में आ गया है। This is wrong. This is not allowed.

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं कह चुका हूं कि इस मामले में न्यायिक जांच की जा रही है।। have already said that, don't jump to the conclusion. ___(interruption)-___

अध्यक्षः ऐसा है कि गवर्नमैंट के ध्यान में यह बात आ गई है। आज इसको उठाने की जरूरत नहीं है। Not to be recorded. This is wrong. ___(interruption)-___

मुख्य मंत्री : इसकी न्यायिक जांच की जा रही है, आप जांच की रिपोर्ट का इंतज़ार कीजिए।

08.03.2017/1200/केएस/डीसी/3

Speaker: This thing has come into the notice of the Government and Government is taking action. मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि वे उस पर ऐक्शन ले रहे हैं। आज इस बात को उठाने का मतलब ही नहीं है।

अब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण होगा। मेरा माननीय सदन से यह निवेदन रहेगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कुछ और लोग यहां बोलना चाहते हैं। उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी उसका उत्तर देंगें। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जो लोग बोलने वाले हैं वे संक्षेप में बोलें क्योंकि तीन दिन बहुत सारे प्वाइंट्स पर बोल चुके हैं। आज संक्षेप में बोलकर आप समय बचाएंगें और माननीय मुख्य मंत्री जी उसका उत्तर देंगें। अब श्री महेन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगें। महेन्द्र सिंह जी, कृपया समय का ध्यान रखें।

महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा आदरणीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि वे अगर सदस्यों की बात सुनें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि ये अपनी सीट पर बैठे और हमारी बात सुनें।

आदरणीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय ने पहली मार्च, 2017 को प्रदेश सरकार के एक साल के कार्यकाल का जिक्र इस अभिभाषण में किया है। अच्छा होता सरकार जब इस अभिभाषण को तैयार कर रही थी तो उसमें जो हम वर्तमान सरकार के ऊपर अनेकों भ्रष्टाचार के आरोप आज से नहीं ,लम्बे अरसे से लगा रहे हैं ।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

आज से नहीं लम्बे अरसे से लगा रहे हैं और

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

8.3.2017/1205/av/dc/1

श्री महेन्द्र सिंह --------- जारी

वर्ष 2012 में जब विधान सभा के चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में एक बात बड़ी सुर्खियों में कही गई थी कि भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जायेगा। मैं उन बातों को दोबारा से इस सदन के बीच में नहीं दोहराऊंगा जिन पर मेरे साथियों ने पहले

बड़े विस्तार से चर्चा कर ली है। प्रदेश में जो हमारा आई0पी0एच0 का विभाग है इस विभाग का पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा महत्व है। मुझे एक बात का बड़ा दुःख होता है कि इन साढ़े चार वर्षों के कार्यकाल के अंदर आज एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि आई0पी0एच0 विभाग की जितनी भी उठाऊ पेयजल परियोजनाएं या उठाऊ सिंचाई परियोजनाएं हैं उनमें से आपने लगभग 85 से 90 प्रतिशत आउट सोर्स करके ठेके पर दे दी है। आई0पी0एच0 विभाग के बजट से प्रतिवर्ष लगभग 60 से 65 करोड़ रुपये उन ठेकेदारों को दिया जा रहा है जो पानी की आपूर्ति करते हैं। उसमें सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि वर्ष 2013-14 में जिन्होंने किसी एक स्कीम को जिस थोड़े से अमाऊंट में लिया था और एक वर्ष के बाद जब उसके दोबारा टैंडर किए गए तो उसमें कुछेक बढ़ोतरी नहीं बल्कि 15-15, 20-20 गुणा बढ़ोतरी की गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि मंत्री जी, आई0पी0एच0 विभाग का क्या होगा? आई0पी0एच0 विभाग का तो ऐसा जनाजा निकल रहा है जैसा जनाजा वर्ष 2004 से 2007 के बीच निकला था। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। आपने विभाग के टोप लैवल के ऐडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा हैवी कर दिया है। उसमें किसी चीफ इंजीनियर, एस0ई0 और ऐक्सियन की पोस्ट खाली नहीं है। मगर जिन्होंने धरातल पर काम करना है जैसे वॉटर गार्ड जो कि पानी छोड़ने का काम करते हैं, फिट्टर या असिसटैंट फिट्टर, पम्प ऑपरेटर या असिसटैंट पम्प ऑपरेटर इत्यादि हैं; विभाग में उन पोस्टों को पूर्ण रूप से खाली कर दिया है। आप उन ठेकेदारों को एक साल का 65 करोड़ रुपये दे रहे हैं। उसकी जगह आप हिमाचल प्रदेश में इस विभाग के अंतर्गत जल रक्षक रखते जिन जल रक्षकों को आप 1500 रुपये या 1700 रुपये प्रति माह मानदेय दे रहे हैं।

8.3.2017/1205/av/dc/2

अगर आप ऐसा करते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर कम-से-कम एक लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलना था। लेकिन फिर अधिकारियों और ठेकेदारों की जेबें कैसे गर्म होनी थी। इससे आप सबके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा

होता है। मेरा इस सदन के अंदर दिनांक 20-12-2016 को प्रश्न संख्या 3549 लगा था। पहले तो उस प्रश्न के ऐनेक्सचर का उत्तर मुझे नहीं दिया जा रहा था। कह रहे थे कि 950 पेज हैं जैसे कि आज मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि बहुत बड़ा दस्ता है। यह हमारा अधिकार है और यह अधिकार हमें इस हाउस ने दिया हुआ है। हम कोई भी सूचना पूछ सकते हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान उस प्रश्न की तरफ ले जाना चाहता हूं। आपके महकमे ने इस प्रदेश के अंदर युनियन, सॉकेट, टी और ग्लोब-वॉल्व के रूप में करोड़ों रुपये की खरीद की हुई है।

श्री वर्मा द्वारा जारी

08/03/2017/1210/टी0सी0वी0/ए0जी0/1
श्री महेन्द्र सिंह ....जारी।

मैं माननीय मंत्री जी को एक बात बताना चाहता हूं कि आपने सवा लाख से ज्यादा युनियन क्रय किये हैं। सवा लाख युनियन का मतलब है कि एक युनियन 8 पाईपों के बाद लगता है यानि लगभग 50 मीटर के बाद एक युनियन लगता है। आपने पूरे प्रदेश की स्कीमों को ठेके पर दे दिया है और उसके जो एग्रीमेंट हुए हैं, उसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि इसकी रिपेयर, मैंटेनेंस सारी ठेकेदार ने करनी हैं। फिर आप करोड़ों रूपये की खरीद युनियन के रूप में क्यों कर रहे हैं? मैंने अपने एक प्रश्न के उत्तर में देखा है कि आपने जो युनियन खरीदें हैं, उसमें रामपुर मण्डल के अन्तर्गत गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी से 32 एम0एम0 का युनियन 165 रूपये में और 25 एम0एम0 का युनियम 108 रूपये में खरीदा है, जबकि दूसरी ज़गह 32 एम0एम0 का युनियन 71 रूपये में हैं। आपने यहां पर जालंधर और दूसरी कंपनियों को इकट्ठा कर दिया है और एक ही कंपनी युनियन और सॉकीट सप्लाई कर रही है। मैं सोकीट के बार में जरूर कहना चाहूंगा। जब आप पाईपें क्रय करते हैं, पाईपों के साथ सोकीट लगकर आती हैं। आपने देखा होगा कि जब पाईपों के बंडल बंधे हुए होते हैं, उन बंडलों के पीछे बोरा लगा होता है, ताकि सोकीट कहीं गिर न जाये। क्या कारण है कि आप इसके बावजूद भी सोकीट/युनियन और दूसरी चीजें खरीद रहे हैं। आपने सारी-की-सारी स्कीमें आउटसोर्स कर दी है। मैंने आपको कहा था कि 2003 और 2007 के बीच में द्रावला का कांड हुआ था। हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला मैकेनिकल, डिविज़न न0 2 (आई0पी0एच0) ने करोड़ों रूपये की फिटिंग खरीदी थी, जोकि हमारी चार्जशीट का एक

हिस्सा था, लेकिन चार्जशीट पर आप विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि कृपया आप इस पर विचार करें। आपने सेंटर विजिलेंस कमीशन की गाइड लाईन को दरकिनार कर दिया है। सी0वी0सी0 के मुताबिक पूरे भारतवर्ष के अंदर टेंडर किये जाते हैं। आपने उनकी गाइडलाईन्ज़ को बदल दिया। आपने कहा ज्वाईंट वेंचर नहीं चलेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर दो ही कंपनियां है, जिनके ऊपर हिमाचल प्रदेश सरकार/आई0पी0एच0 विभाग मेहरबान है। इतनी ऊंची दरों पर काम दिए जा रहे हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में टोरखोला, उठाऊ पेयजल योजना है, जिसका आपने 2013-14 में आउटसोर्स करने का ठेका एक लाख, 62 हजार में दिया था। लेकिन आपने वर्ष 2014-15 में उसका ठेका 20 लाख, 25 हजार में दे दिया। मैं आपसे

08/03/2017/1210/टी0सी0वी0/ए0जी0/2

निवेदन करना चाहता हूं कि आपके आई0पी0एच0 विभाग के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जब हम आई0पी0एच0 विभाग के अधिकरियों/कर्मचारियों से पूछते हैं, तो वे कहते हैं कि हमारे पास फिटिंग का कोई भी सामान नहीं है। ये सामान कहां चला जाता है। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जहां तक स्वास्थ्य विभाग का सवाल है, स्वास्थ्य मंत्री आज यहां पर विराजमान नहीं है, लेकिन अच्छा होता यदि स्वास्थ्य विभाग को भारत सरकार की तरफ से जो बड़ी-बड़ी स्कीमें, बड़े-बड़े पैकेज़ हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के लिए दिए जा रहे हैं, आप इस महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उन सबका ज़िक्र भी करते और इसके लिए उनका धन्यवाद कर देते। मैं इस हाउस के माध्यम से श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो पहले हमारे हाउस के सदस्य/मंत्री हुआ करते थे, आज भारत सरकार के बीच में स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग के मंत्री हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए एक नहीं अनेकों बड़ी-बड़ी योजनाएं दी हैं।

श्रीमती एन0एस0 ... द्वारा जारी।

08/03/2017/1215/ एन0एस0/ए0जी0 /1

श्री महेन्द्र सिंह----- जारी

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को स्वीकृति प्रदान की है। इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमैंट, हाईड्रो इंजीनियरिंग कालेज, बिलासपुर और तीन मेडिकल कॉलेज दिये हैं। उनमें से एक मेडिकल कॉलेज, नाहन, दूसरा मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर और तीसरा मेडिकल कॉलेज, चम्बा में दिया है और इन तीनों मेडिकल कॉलेज के लिए भारत सरकार ने 200 करोड़ रूपये स्वीकृत किए हैं। वर्तमान प्रदेश की सरकार उस 200 करोड़ रूपये की धनराशि को लने के लिए जो औपचारिकताएं पूरी करनी चाहिए उनको पूरा नहीं कर रही है। यह बड़े अफसोस की बात है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुपर स्पैशलिटी ब्लॉक आई0जी0एम0सी, शिमला और डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टाण्डा को 150-150 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की है। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। ट्रामा सैंटर के लिए 17 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की है। मैं इसके लिए उनका धन्यवादी हूं और साथ में ही हिमाचल प्रदेश के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राशि 303 करोड़ रूपये इस वर्ष के लिए स्वीकृत हुई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 40 करोड़ की लागत से मातृ शिशु स्वास्थ्य विंग को भी स्वीकृति दी है। इसी प्रकार इनडोर पेशैंट खंड 10 करोड़ रूपये की लागत का घुमारवीं के लिए स्वीकृत किया हुआ है। एक ऐसा ही इनडोर पेशैंट खंड डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टाण्डा के लिए स्वीकृत किया हुआ है। मैं इसके लिए इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने सैंट्रल गर्वनमैंट हेल्थ स्कीम शिमला शुरू की है। उन्होंने सैंट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बद्दी स्थापित करने के लिए भी स्वीकृति दी है। उन्होंने देश में 'अमृत योजना' लागू की है। 'अमृत योजना' से हिन्दुस्तान में कैंसर, हार्ट की बाई पास सर्जरी से संबंधित दवाईयां सस्ती मिलेंगी। जो स्टंट 1 लाख 50 हजार का पड़ता था अब वह 28,000 में मिलेगा और जो 45,000 का स्टंट पड़ता था वह मात्र 8000 में मिलेगा। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक सरकार भारत

08/03/2017/1215/ एन0एस0/ए0जी0 /2

सरकार है जो हिमाचल प्रदेश के उत्थान के लिए काम कर रही है, करोड़ों, अरबों रूपये हिमाचल प्रदेश के लिए दे रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार कैंसर यूनिट शिमला और मण्डी में स्थापित करने के लिए डी0पी0आर्ज़0 यहां से नहीं भेज रही है। इसलिए मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं चाहती है कि हिमाचल प्रदेश में ज्यादा पैसा आए। हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? स्वास्थ्य विभाग ने हिमाचल प्रदेश के अंदर, आई0जी0एम0सी0 के अंदर एक आक्सीजन गैस प्लांट स्थापित करने के लिए मांडव एयर इंडस्ट्री को स्वीकृति प्रदान की है। पहले जो सिलेण्डर 205 रूपये में मिलता था अब उस सिलेण्डर का रेट हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी की अनुकम्पा से 255 रूपये फिक्स कर दिया गया है। इस आक्सीजन प्लांट को लगाने के लिए मात्र 82 लाख रूपये खर्च होंगे और इस गैस प्लांट से एक साल की आमदनी लगभग 2 करोड़ रूपये है। जब वह प्लांट लग जायेगा तो पांच वर्षों के उपरान्त प्रति वर्ष पांच प्रतिशत की हाईक दी जाएगी। अब आप खुद अन्दाजा लगाएं कि जो सिलेण्डर अभी 255 रूपये का है वह 15 साल के बाद हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग उस सिलेण्डर को लगभग 425 रूपये में खरीदेगा। मेरा आरोप है कि सीधे तौर पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग पर बन रहा है। माननीय मंत्री जी अगर यहां पर होते तो वे इसका जवाब अवश्य देते। मेरा कहना है कि इस प्लांट को रोगी कल्याण संस्था के माध्यम से लगाना चाहिए था । क्या रोगी कल्याण संस्था के पास 82 लाख रूपये की राशि नहीं है? अगर हम उस प्लांट को अपने आप लगाते तो लगभग हमारा 40 से 45 करोड़ रूपये की राशि बचनी थी।

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

श्री महेन्द्र सिंह....जारी

माननीय मंत्री जी आजकल पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी गए थे, जहां पर एक जगह 6 आदमी थे और दूसरी जगह 13 आदमी थे। वहां पर इन्होंने घोषणा कर दी की जितनी भी पी.एच.सीज., सी.एच.सीज. हैं उन सभी में सारे-के-सारे पद भर दिए जाएंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपको वहां पर गए हुए तीन महीने हो गए हैं परन्तु आजतक न ही वहां पर पैरामैडिकल स्टाफ की नियुक्ति हुई और न ही किसी डॉक्टर की नियुक्ति हुई है। आपने कहा था कि हम संदौल के सिविल हौस्पिटल को 100 बिस्तरीय कर रहे हैं। आपने यह भी कहा था कि धर्मपुर सी.एच.सीज. को 100 बिस्तरीय कर दिया जाएगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री, वर्तमान सरकार और माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह नोटिफिकेशन कहां है? ऐसी झूठी घोषणाएं आपको नहीं करनी चाहिए। आदरणीय सुजान सिंह पठानिया जी यहां पर बैठे हुए हैं और इनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण विद्युत/कृषि विभाग है। आदरणीय पठानिया जी मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में ब्यास वैली के ऊपर, बैरी के पास 79 मैगावाट का एक प्रोजैक्ट जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर थी, अनुमोदित हुआ था। जैसे ही वर्ष 2013 में सरकार बदली उसी वक्त सारे-का-सारा सामान, जी.एम. और सभी को उठा कर आप रोहड़ू ले गए। एक विधान सभा प्रश्न के उत्तर में आपने लिखा है कि 'बैरी का प्रोजैक्ट फिजिबल नहीं है। ' जब आपकी सरकार आती है तो इनफिज़िबिल हो जाता है और जब हमारी सरकार आती है तो फिज़िबल हो जाता है।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

माननीय मंत्री जी हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 22 लाख उपभोक्ताओं को आप 5-5 एल.ई.डी. बल्ब देने जा रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे यह प्रश्न किया था और आपने कहा था

कि यह भारत सरकार की स्कीम है। लेकिन हमने कहा यह भारत सरकार की स्कीम नहीं है, भारत सरकार की फंडिंग नहीं है। हमारे देश के प्रधान

08/03/2017/1220/RKS/AS/2

मंत्री जी ने 15 अगस्त, 2016 को लाल किला से कहा था कि एल.ई.डी. बल्ब हमारे देशवासियों को 50 रुपये में मिलेगा परन्तु आपने उस बल्ब की कीमत 100 रुपये, 105 रुपये, 110 रुपये लगाकर लगभग 78 लाख बल्ब हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को ऊंचे दामों पर बंटवा दिए। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? इन बल्बों के ऊपर आपने ज्यादा पैसे रिकवर किए। आपने जिस कम्पनी को काम दिया था उस कम्पनी ने दूसरी और दूसरी कम्पनी ने तीसरी कम्पनी को काम दे दिया। तीन बिचौलिए बैठ गए। तीन बिचौलिए बैठने के उपरान्त कुछ तो अधिकारियों ने भी घपला किया होगा। मैं नहीं जानता कि आपकी नीयत गलत होगी। लेकिन इस प्रकार की जो धांधलियां हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रही है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन धांधलियों को रोकने की भरपूर कोशिश करें।

Speaker: Hon'ble Member, please wind-up.

श्री महेन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक वृक्षारोपण की बात है, इसी हाउस के अंदर हमारे कई प्रश्न लगे हुए हैं। इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हमने वन मंत्री जी को कहा था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पौध रोपण हो रहे हैं, आपने उन पौधों को कहां से खरीदा है? आपके पास कितनी नर्सरीज़ हैं जहां से आप इन पौधों का क्रय कर रहे हैं? आपने दर्शाया है कि हमने अरबों पौधे हिमाचल प्रदेश के अंदर लगाए हैं। आज हमें अरबों नहीं, खरबों नहीं, करोड़ो नहीं, लाखों नहीं, हजारों नहीं बल्कि सैंकड़ों पौध भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जीवित नहीं दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को यदि हम हरा भरा देखना चाहते हैं तो उसमें फोरैस्ट की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। इस भूमिका को निभाने के लिए यदि आप सकारात्मक सहयोग करेंगे तो यह तभी हो सकता है अन्यथा नहीं हो सकता।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

08.03.2017/1225/SLS-AS-1

श्री महेन्द्र सिंह ...जारी

मेरा उद्योग मंत्री जी से निवेदन है। मंत्री जी आपके ऊपर एक छोटा-सा आरोप लग रहा है। हिमाचल प्रदेश में उद्योग विभाग का जो माइनिंग विंग है, जितने क्रशर्ज़ हिमाचल प्रदेश में लगे हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने फ़ैसला दिया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ैसला दिया है कि जिन क्रशर मालिकों पर रवैलिटी का पैसा न देने के कारण पैनल्टी लगी है, आदरणीय अध्यक्ष जी, वह पैसा थोड़ा नहीं है, वह 300 करोड़ के लगभग है। अगर माननीय मंत्री जी के पास सूचना नहीं है तो मेरे पास वह पूरी सूचना है। यह कोर्ट में दी हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से निवदेन करना चाहूंगा...(व्यवधान)...

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस मसले में शामिल लोग अदालत में गए हैं और उनको स्टे मिला हुआ है। मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं, इन पर भी जुर्माना लगा हुआ था जो इन्होंने जमा करवा दिया। इन्होंने करवा दिया, इसलिए ये चाहते हैं कि सारे जमा करवाएं। विभाग भी यही चाहता है कि सारे लोग जमा करवाएं लेकिन क्योंकि 22 लोग अदालत में चले गए और सारा केस क्लब हो गया जो अब 9 तारीख को फिर से लगा है। हमने दोबारा से सबको नोटिस दे दिए हैं और हम चाहते हैं कि सब लोग पैसा दें। अदालत जो निर्देश देगी और जो विभागीय कार्रवाई बनती है, वह हम निश्चित तौर पर करेंगे। इसमें किसी को बचाने का कोई मतलब ही नहीं है।

श्री महेन्द्र सिंह : आपका धन्यवाद। आप 22 केसिज की बात कर रहे हैं जबकि यह 250 केसिज हैं।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप वाईंड अप कीजिए।

श्री महेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, यह इतना महत्वपूर्ण है कि 300 करोड़ रुपया हिमाचल के ख़जाने में आने वाला है। उस 300 करोड़ रुपये को लेने के लिए उद्योग विभाग का माइनिंग विंग कार्रवाई नहीं कर रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने

08.03.2017/1225/SLS-AS-2

किसी भी क्रशर मालिक को ऐसा स्टे नहीं दिया है कि उस पैसे को जमा न करवाएं। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि किसी भी एक क्रशर को ऐसे आदेश नहीं हैं कि आप पैसा जमा न करवाएं। इसलिए मेरा निवेदन है, क्योंकि आपके ऊपर ऊंगली उठ रही है कि कहीं आपकी छत्रछाया में यह सब-कुछ तो नहीं हो रहा है। मैं ऊंगली नहीं उठा रहा हूं बल्कि प्रदेश की जनता उठा रही है कि इस प्रदेश के अंदर जो खनन माफिया हॉबी हुआ है...(व्यवधान)...

उद्योग मंत्री : मेरे ऊपर कोई ऊंगली नहीं उठा रहा है। आपका क्रशर था और आपके ऊपर जुर्माना हुआ। अब आप चाहते हैं कि जुर्माना सभी से बसूला जाए। विभाग ने सभी को नोटिस दिए हैं और सब लोग अदालत में जा रहे हैं। अभी केस लगा है। उसमें कोर्ट जो आदेश देगा, हम वही करेंगे, नहीं तो हम उनकी प्रापर्टी जब्त करेंगे और उनके क्रशर्ज़ बंद करवाएंगे। यह 300 करोड़ रुपये का मसला नहीं है बल्कि 125 करोड़ रुपये के आसपास की बात है। आप उसको बढ़ाकर बोल रहे हैं। ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आप चाहें तो बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये बोल दें।

बहुद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : महेन्द्र सिंह जी, आप पोलिटिक्स में लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं या पैसा कमाने के लिए आए हैं?

श्री महेन्द्र सिंह : आप जो वहां पर बिजनस कर रहे हैं, मेरे से मत कुछ भी बुलवाइए। ...(व्यवधान)... मिस्टर पठानिया, आप चुपचाप बैठे रहो। मेरे से मत ज्यादा उगलवाओ। समझे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज वाईंड अप। आपकी चर्चा काफी लंबी हो चुकी है। आप 20 मिनट बोल चुके हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब भी देना है।...(व्यवधान)... आप 2-3 मिनट में समाप्त कीजिए।

08.03.2017/1225/SLS-AS-3

श्री महेन्द्र सिंह : सर, लोगों ने 40-40 मिनट बोला है जबकि मुझे अभी 20 मिनट हुए हैं जिसमें भी बीच में इंट्रप्शन हो रही है। जितने समय के लिए बाकी लोगों ने बोला, उतना तो मुझे भी बोलने दीजिए।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे कुछ मंत्री मित्रों को ज्यादा पीड़ा हो रही है। मैं अक्साईज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर से जानना चाहता हूं कि आपने पिछली बार अक्साईज एंड टैक्सेशन में जो शराब के ठेकों की नीलामी की, उसमें आपने एक एच.पी.बी.एल. बनाया। क्या कारण है कि उसे बनाने के उपरांत आपने एल-1 लाइसैंस वाले जो थोक शराब बिक्रेता थे,

जारी ...गर्ग जी

08/03/2017/1230/RG/DC/1
श्री महेन्द्र सिंह----क्रमागत

आपने उनके ऊपर एल-1ए बैठा दिया। अब वे एल-1ए कौन है? फिर एल-1ए बैठाने के बाद आपने कहा कि एल-1ए जो एच.पी.बी.एल. है वह सारा-का-सारा ऑर्डर सभी शराब की दुकानों से लेगा, ऑर्डर लेने के बाद फिर उनसे पैसा इकट्ठा करेगा और फिर वह उस एल-1ए को जो ब्लू लाईन है उनको देगा। फिर वह शराब उठाएगा, किस ब्रूएरी से उठाता है या किस बॉटलिंग प्लांट से उठाता है वह उसका एकाधिकार है। फिर किसको वह क्या रेट देता है? आदरणीय मंत्री जी, हिमाचल प्रदेश में आबकारी एवं कराधान विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके माध्यम से सबसे ज्यादा इनकम हिमाचल प्रदेश के खजाने में आती है। आप एक नई आबकारी एवं कराधन नीति बनाने जा रहे हैं। लेकिन पिछले कल जो मंत्रि-

मण्डल की बैठक थी उसमें यह अप्रूव नहीं हो पाई। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष के लिए जो वर्ष अभी चला हुआ है इसमें दिल्ली के बाद गुणगांव का जो व्यापारी है उस व्यापारी के साथ जो साठगांठ हुई है, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि हिमाचल प्रदेश के एल-1 को जो आपने नुकसान पहुंचाया है, हिमाचल प्रदेश में जिनकी छोटी-छोटी शराब की दुकानें चलती थीं उनको जो नुकसान हुआ है, एच.पी.बी.एल. को जो नुकसान पहुंचाया गया है और इसके अतिरिक्त एल-1ए के लोगों को जो नुकसान पहुंचाया गया है उसकी भरपाई कौन कर सकता है? यह आपके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त जब इनका घोषणा-पत्र बन रहा था, तो इन्होंने कहा था कि हम हर बेरोजगार को भत्ता देंगे। हिमाचल प्रदेश में लगभग 12,00,000 बेरोजगार हैं, तो इन्होंने कहा था कि हम हर बेरोजगार को 1,000/-रुपये और 1,500/-रुपये भत्ता देंगे और इन 12,00,000 बेरोजगारों को 1,000/-रुपये के हिसाब से 120 करोड़ रुपये एक वर्ष का बेरोजगारी भत्ता जो उनको मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। आज सरकार का 5वां साल चला हुआ है। यहां हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी नहीं हैं। उन्होंने इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को कहा और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने भी इसके लिए कहा कि हमने जिस बेरोजगारी भत्ते की बात घोषणा-पत्र में कही है, यह उन्हें देना चाहिए। हम विपक्ष की तरफ से भी यह मांग रहे हैं कि पिछले पांच साल का 1000/-रुपये और 1,500/-रुपये से हिसाब यह बेरोजगारी भत्ता हिमाचल प्रदेश के 12,00,000 नौजवानों को मिलना चाहिए जोकि मेरे अनुमान में एक महीने का 120 करोड़ बनता है और पांच वर्षों का

08/03/2017/1230/RG/DC/2

7,000 करोड़ रुपये बनता है। जैसे मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम जुगाड़ू मुख्य मंत्री हैं, तो एक जुगाड़ और कर लेंगे ताकि 7,000 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश के बेराजगारों को भत्ता मिले।

संसदीय कार्य मंत्री : अब पता चल रहा है कि माननीय सदस्य का भाषण चुनाव को देखते हुए पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा है उसके मुताबिक हम जो कह रहे हैं हमारा कहना इनको बुरा लगता है। विपक्ष इसलिए होता है कि सरकार जहां गलत कर रही है उसकी गल्तियों को उजागर करना हमारा काम है। उस पर सुधार करना या न करना इनके ऊपर निर्भर करता है कि वह उसमें सुधाएर करें या न करें। अगर सुधार करेंगे, तो कुछ लंबे चलेंगे, अगर नहीं करेंगे, तो कुछ ही देरी के पश्चात लंबे पड़ जाएंगे। इसलिए वर्तमान सरकार से मेरा निवेदन है कि जो वायदे हिमाचल प्रदेश में इन्होंने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में किए हैं और जिस चुनाव घोषणा-पत्र को वर्तमान सरकार ने सरकारी दस्तावेज बनाया है और जब इसको सरकारी दस्तावेज बनाया गया है, तो ये अपने वायदों से क्यों मुकर रहे हैं? यह कोई राजनैतिक भाषण नहीं है। क्योंकि अब आपका अन्तिम साल है और अन्तिम सालों में भी अब अन्तिम महीने बचे हैं और उसमें भी अब अन्तिम दिन सामने आने वाले हैं। इसलिए हम चाहते हैं।

अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बातें लिखी गई हैं और उनसे यहां कहलाई गई हैं उसमें प्रदेश हित नहीं है, उसमें जनहित और राष्ट्रहित नहीं है और प्रदेश के हित में भी यह नहीं हैं। इसलिए मैं इस अभिभाषण का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं कर सकता। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

एम.एस. द्वारा अगले वक्ता शुरू

08/03/2017/1235/MS/DC/1

अध्यक्षः अब चर्चा में श्री जगत सिंह नेगी, माननीय उपाध्यक्ष भाग लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी(उपाध्यक्ष महोदय)ः अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चल रही चर्चा में भाग लेने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। आपने बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, यहां पर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पिछले दो दिनों से जो चर्चा चली हुई है उसमें चार्जशीट के ऊपर हमारे विपक्ष के साथियों ने काफी बोलने का प्रयास किया है। मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि इस तथाकथित चार्जशीट को, जिसे माननीय राज्यपाल महोदय को हमारे विपक्ष के साथियों ने वहां पेश किया है, उसमें मुझे भी घसीटने की कोशिश की गई है और मेरी छवि को धूमिल करने की एक नाकाम कोशिश हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने की है। मैं पहले तो इनसे यह पूछना चाहता हूं कि आप लोग भली-भांति जानते हैं कि राज्यपाल महोदय को जांच करने की कोई शक्तियां नहीं हैं। वे केवल-मात्र जो किसी की तरफ से वहां पर शिकायत दर्ज की जाती है, उसको सरकार को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त है और लोकायुक्त कानून के तहत बना हुआ है। यदि कोई शिकायत हो, जैसे कोई भी क्रप्शन का मामला किसी मंत्री, माननीय सदस्य या सरकार के खिलाफ हो, तो वह एक कानून के द्वारा बनाई हुई संस्था है, उसमें शिकायत कर सकते हैं। यह जो चार्जशीट है या मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं कि मेरी शह पर किन्नौर में खनन हो रहा है। यदि इनके अंदर दम और सच्चाई है तो ये जाकर लोकायुक्त में शिकायत करें ताकि वहां पर यह फैसला हो सके कि कौन सच्चा और कौन झूठा है।

दूसरी बात जो यहां पर क्षेत्रवाद की कही जा रही है उसके बारे में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में पूर्व मुख्य मंत्री और हमारे विपक्ष के नेता प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी हमारे जन-जातीय क्षेत्र के हैड क्वार्टर रिकाँगपिओ तक आए। रास्ते में रामपुर में भी इनकी जनसभा थी। वहां पर इन्होंने कहा कि रामपुर और किन्नौर में कोई विकास नहीं हो रहा है और सारा-का-सारा विकास नीचे के

08/03/2017/1235/MS/DC/2

क्षेत्रों में हो रहा है। जब ये नीचे के क्षेत्रों में भाषण देते हैं तो कहते हैं कि वहां पर भी कोई काम नहीं हो रहा है और सारा-का-सारा काम रोहडू, रामपुर और किन्नौर में हो रहा है। ये जो ऐसी गुमराह करने वाली राजनीति कर रहे हैं उससे किसी का भला नहीं हो रहा है।

आज मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि इस वर्तमान सरकार के पिछले चार वर्षों में जो विकास अन्य क्षेत्रों के अलावा जन-जातीय क्षेत्रों के अंदर हुआ है वह अपने आप में एक इतिहास है। आज चाहे वह लाहौल-स्पिति का इलाका हो, पांगी-भरमौर का इलाका हो, चाहे मेरा अपने जिला किन्नौर का इलाका हो, आज सब जगह बहुत विकास हो रहा है। आज सभी जगह सम्पर्क सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पेयजल योजनाओं का वहां पर जाल बिछाया जा रहा है और शिक्षा के नये-से-नये संस्थान खुल रहे हैं। इसके अलावा हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में भी बहुत सुधार हुआ है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि जो हमारा जिला किन्नौर का रिजनल अस्पताल रिकाँगपिओ में है वह केन्द्र सरकार की एक कायाकल्प योजना के तहत पूरे हिमाचल में नम्बर एक पर आया है और 50 लाख रुपये का ईनाम हमें मिला है। इसी से पता चलता है कि हमारे वहां पर कितना काम हो रहा है।

यहां पर कॉलेज खुलने की बात भी हो रही है। पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले दुर्गम क्षेत्र में अगर कोई कॉलेज खुला है तो जन-जातीय क्षेत्र रिकाँगपिओ में आज से 21 वर्ष पहले खुला है और उस समय भी राजा वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। उस समय भी यही बात हुई कि इस दूर-दराज़ के क्षेत्र में यह कॉलेज खोलने का कोई फायदा नहीं होगा लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस कॉलेज के खुलने से गरीब बच्चे जो रामपुर और शिमला नहीं आ सकते थे, आज वहीं पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तथा 500 से ज्यादा लड़के-लड़कियां आज की तारीख में वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस कॉलेज को भी हमारे यू0जी0सी0 का जो नैक है उसने एक्रीडिटेशन किया है। हिमाचल के चन्द कॉलेजों को "बी" ग्रेड मिला है और उसमें मेरे रिकाँगपिओ के डिग्री कॉलेज को भी "बी" ग्रेड मिला है।

08/03/2017/1235/MS/DC/3

यहां पर बात हुई कि एस0एम0सी0 के माध्यम से भर्तियां की गईं और उसमें रोस्टर नही लगाया गया, पी0टी0ए0 में रोस्टर नहीं लगाया गया है। मैं इनको यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब वर्ष 1998 से वर्ष 2003 के बीच इनकी सरकार थी तो सारे दुर्गम क्षेत्रों में जो हमारे अध्यापक वहां कार्यरत्त थे, उनको विद पोस्ट वहां से उठाकर नीचे लाया गया और जनजातीय क्षेत्रों में सारे-के-सारे पद

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

08.03.2017/1240/जेके/एजी/1

उपाध्यक्षः------**जारी**------

खाली कर दी गई। हमारे बच्चों को पूरे इनके कार्यकाल में गणित पढ़ाने वाला कोई नहीं था। अंग्रेजी का भी कोई शिक्षक वहां पर नहीं था। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत बड़ा आभारी हूं कि दोबारा जब वर्ष 2003 में कांग्रेस की सरकार आई तब पी.टी.ए., पैरा टीचर्ज लगाने की पॉलिसी बनी, बढ़िया पोलिसी बनी। उसमें यह फैसला किया गया कि वहां पर जो स्थानीय बच्चे हैं, जो अपने सब-डिविजन के अन्दर है, उन्हीं को मान्यता दी गई और उन्हीं को लगाया गया। जो हमारा जनजातीय इलाका है, शड्यूल्ड एरिया है, वहां पर सारे के सारे जनजातीय लोग है। 100 प्रतिशत जो हमारे बच्चे थे उन्हीं को वहां पर नौकरियां मिली और इसमें रोस्टर की कोई जरूरत नहीं थी। इसी तरह से पी0टी0ए0 की बात है। जो एस0एम0सी0 की बात है उसमें भी दोबारा जब इनकी सरकार बनी फिर सारी की सारी पोस्टें हमारी खाली कर दी गई। अब कोई तरीका नहीं था कि किस तरह से इन स्कूलों को चलाया जाए। उसका एक ही तरीका था कि एस0एम0सी0 के माध्यम से इनकी भर्तियां की जाए क्योंकि एस0एम0सी0 के माध्यम से जो भर्तियां की गई उसमें एकदम से महीने के अन्दर आप सारी पोस्टें भर सकते थे। एस0एम0सी0 में जो लैक्चरर लगते हैं, जो टी0जी0टी0 लगते हैं या जे0बी0टी0 लगते हैं उनकी क्वालिफिकेशन जो रैगुलर टीचर्ज हैं, उनके बराबर की है। उनको भी टैट की क्वालिफिकेशन पूरी करनी पड़ती है। इसमें कहीं भी किसी भी किस्म की कमी नहीं थी। यह भी एस0एम0सी0 में बहुत बढ़िया फैसला था कि स्थानीय पंचायत का अगर वह लड़का उस स्थानीय पंचायत से आता है तो पहले उसको 10 नम्बर दिए जाएंगे और उसको वेटेज़ दिया गया। अगर वह सीनियर सैकंडरी स्कूल है तो जो पटवार सर्कल के अन्दर के जो उम्मीद्वार थे, उनको 10 नम्बर का वेटेज दिया गया जिस कारण से वहां पर स्थानीय लोगों को नौकरी मिली और उससे हमारे सारे स्कूलों में

ठीक से शिक्षा का काम हो रहा है। आज आप जानते हैं कि अगर कमिशन से लोग आते हैं सबसे पहला काम उनका यह होता है कि वे अपना च्वाईस का स्टेशन ढूंढते हैं और एस0एम0सी0 में वे अपनी च्वाईस से उस जगह पर आते हैं।

08.03.2017/1240/जेके/एजी/2

एस0एम0सी0 का दोबारा कोई ट्रांसफर नहीं होता है और इस एस0एम0सी0 ने आज हमारे शिक्षा के जो दूर-दराज, जनजातीय इलाके के जो स्कूल हैं, उनमें शिक्षा का बढ़ियां काम हो रहा है। मैं यहां पर याद दिलाना चाहता हूं धूमल साहब को, इन्होंने वर्ष 1998 में विद्या उपासक लगाए। वह आपका डिस्ट्रिक्ट काडर था परन्तु आपने हमारे साथ भेदभाव किया। मेरे जिला किन्नौर से हमीरपुर के 25 लड़कों को आपने विद्या उपासक डिस्ट्रिक्ट काडर के माध्यम से लगाया। फिर एक-दो साल के बाद सारे के सारे 25 लड़के आप वापिस हमीरपुर ले गए। डिस्ट्रिक्ट काडर के अन्दर आपने यह किया। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट काडर के जे0बी0टी0 लगाए थे उन सभी को आपने रामपुर में खदेड़ दिया। किन्नौर से आपने एक किस्म का भेदभाव किया। कल हमारे मित्र सत्ती जी यहां पर कह रहे थे कि जब किन्नौर में बाढ़ आई तो मटर हेलिकॉप्टर में ले गए। बार-बार कहते हैं कि ये हेलिकॉप्टर में मटर ले गए। पूरे हिमाचल को गुमराह करते हैं। आप कितने मटर ले कर गए थे? केवल दो बोरी मटर हेलिकॉप्टर में ले गए थे और उसका प्रचार करते हुए 10-15 साल हो गए तब भी ये थकते नहीं। उन दो बोरी मटर का क्या हाल किया? दो बोरी मटर हेलिकॉप्टर में रखी और एक किसान को साथ बिठाया, किसान को रामपुर में उतारा और मटर की बोरी चण्डीगढ़ में उतार दी। जब किसान बस से चण्डीगढ़ के हेलिपैड में पहुंचा तो वहां पर न मटर मिला न बोरी मिली। ये दो बोरी मटर का प्रचार करते हैं। *** _ किस तरह से ये हिमाचल के लोगों को गुमराह करते हैं? ये जनजातीय लोगों के साथ कैसा भेदभाव करते हैं, यह मैं कहना चाहता हूं। मुझे याद है जब धूमल साहब उस समय मुख्य मंत्री थे पूरा एक महीने पीओ के अन्दर मुझे भूख हड़ताल करनी पड़ी क्योंकि उस समय सतलुज में बाढ़ आई हुई थी। एक महीने से किन्नौर में चलने के लिए और वहां पर लोगों को खाने के लिए राशन नहीं

था। दवाइयों की व्यवस्था नहीं थी। लोग अपने-अपने गांवों के अन्दर सिमट गए थे। उस समय धूमल साहब को याद होगा, आप वहां किन्नौर में आए थे हमने उस समय आपके सामने सारी बातें रखी थी, परन्तु जो हमारा उस

*** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।

08.03.2017/1240/जेके/एजी/3

समय किन्नौर के अन्दर सेब था वह सारे का सारा सड़ गया। आपने 8 रूपये सेब के ऊपर समर्थन मूल्य दिया । फिर कहा कि इसको ग्रेड करके फिर बोरी में डाल करके फलां सैंटर में लाओ। जब रोड़ ही नहीं था, वहां पर व्यवस्था नहीं थी तो कैसे हम उस सेब को बोरी में लाते? पूरे किन्नौर जनजातीय इलाके का सेब उस समय आपके कार्यकाल में सड़ गया। वर्ष 2005 में दोबारा फिर पारछू नदी में सतलुज से भी ज्यादा व्यापक बाढ़ आई परन्तु उस समय कांग्रेस की सरकार थी। राजा साहब मुख्य मंत्री थे। एक दाना किन्नौर का सेब सड़ने नहीं दिया। कुंजम से होते हुए, रोहतांग से होते हुए दिल्ली तक सेब की सब्सिडी एक-एक बागवान को 60-60,70-70 हजार रूपए कांग्रेस की सरकार ने उस समय दी।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

08.03.2017/1245/SS-AG/1

माननीय उपाध्यक्ष क्रमागतः

रिकॉर्ड समय में किन्नौर की सड़कों का निर्माण किया। यहां पर मेरे मित्र आदरणीय महेन्द्र सिंह जी बैठे हैं ये भी जब मंत्री बने तो बड़ा प्रचार किया कि 22 दिन में किन्नौर का पुल बना दिया। इनको मैं बताना चाहता हूं कि 22 दिन में कोई पुल नहीं बनता। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, मैं उस समय 1996-97 के बीच में विधायक था। वांगतू के पुल को बनाने के लिए 6 महीने रात दिन कम्प्रैशर चला कर रास्ता बनाया और पुल बनाने के लिए ठेका आर्मी की इंजीनियरिंग कोर को दिया, जिनको वह काम 22 दिन के अंदर पूरा करना था।

परन्तु उनसे 22 दिन में काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि वहां एक ट्रैजेडी हुई। एक ऑफिसर की वहां पर पत्थर लगने से मौत हुई तो वह पुल दो महीने में लगा। सरकार बदल गई और सबसे पहले कलैण्डर में लिखा कि 22 दिन में एशिया का सबसे लम्बा वैली ब्रिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। यह गुमराह करने की जो राजनीति मेरे दोस्त करते हैं यह बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है। मैं केवल यही इनसे कहना चाहता हूं कि सच्चाई पर बात कीजिए। आज अगर एस0एम0सी0 लग रहे हैं तो जनजातीय इलाके में लग रहे हैं। पी0टी0ए0 में जो लगे हैं तो जनजातीय इलाके में लगे हैं इसलिए आप हमारे साथ भेदभाव न कीजिए। आपकी सरकार के समय में जनजाति उप-योजना जिसमें पूरे हिमाचल के बजट का 9 प्रतिशत मिलता था, वह धूमल साहब के समय में 8.5 प्रतिशत किया गया, जिससे 30 करोड़ का नुकसान केवल मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर हुआ। इसलिए यह भेदभाव की राजनीति को आप छोड़ें। मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूं कि जो चार्ज आपने मेरे ऊपर लगाया है और मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है उसके लिए मैंने माननीय सी0जे0एम0 कोर्ट, रिकॉंगपिओ में दफा 499, 500 के तहत केस दायर किया हुआ है। वहां इस केस का फैसला होगा।*** वहां पर प्रूव होगा। साथ मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि जो लोग शीशे के मकान में रहते हैं उनको दूसरों पर पत्थर नहीं फैंकना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

*** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।

08.03.2017/1245/SS-AG/2

अध्यक्षः श्री प्रेम कुमार धूमल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय उपाध्यक्ष जी अपनी बात रख रहे थे। एक तो बहुत बार इन्होंने झूठ शब्द का प्रयोग किया है जो अन-पार्लियामैंटरी है इस करके उस शब्द को कार्यवाही से हटाया जाए। इन्होंने कहा कि 8 रुपये सपोर्ट प्राइस दिया था। तथ्य है और वैरिफाई किये जा सकते हैं कि 10 रुपये सेब का समर्थन मूल्य वहीं देकर और सेब जिसके बगीचे का था उसके पास ही रखकर स्कूलों में खिला दो, वहां घर में खा लो,

10 रुपये के हिसाब से समर्थन मूल्य दिया था। अगर कोई वाया कुंजमपास लाना चाहता है तो सारा किराया भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने ट्रकों से दिया था। ये कह रहे हैं कि जो मटर थे उनको चंडीगढ़ ले गए। एयरफोर्स के वे हैलीकॉप्टर थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्पैशल परमिशन दे कर हिमाचल के लिए दिए थे और उसके माध्यम से पी0ओ0 और रामपुर के बीच ही फ्लाइट होती है तो चंडीगढ़ मटर कैसे जा सकते हैं? मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि 2005 में जब ट्रैजेडी हुई थी तो सारे मीडिया ने कवर किया था कि ट्राईबल लोगों को तो लिफ्ट नहीं किया गया लेकिन जो टूरिस्टस बाहर से आए थे उनको ले जाने में इनके टाइम में सारी फ्लाइट्स लगी थीं। एक शब्द बड़ा विचित्र था, मैं इसकी अपेक्षा नहीं करता था क्योंकि मेरे पड़ोसी हैं और रोज़ सवेरे बड़ी अच्छी तरह से मिलते हैं। विद्या उपासक का केस सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं, अब उनको इंक्रीमैंट और रेगुलर करने की बात आई है। ये कहते हैं कि दो महीने में ही उनको वापिस ले गए। जब डिस्ट्रिक्ट काडर था तो किन्नौर में कैसे लगने थे? जे0बी0टी0 का तो मैं मान सकता हूं कि जे0बी0टी0 का 5 परसैंट में ट्रांसफर हो गया हो, विद्या उपासक तो लगता ही अपने जिले में था और बिना रेगुलराईज़ हुए कैसे ट्रांसफर हो गई? इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय जब सदन में बोलें तो ठीक बोलें। ट्राईबल फंड की भी इन्होंने एक नई बात निकाल दी। उनके लिए 9 परसैंट का प्रोविजन है। शिड्यूल्ड कास्टस के लिए, उनकी आबादी प्रदेश में 26 परसैंट हो गई है, कांग्रेस सरकार में वह 11 परसैंट मिलता था,

जारी श्रीमती के0एस0

08.03.2017/1250/केएस/एएस/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जारी----

यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने इनकी जब आबादी 24.72% थी तो हमने बजट बढ़ाकर 24.72% किया था । बाकी इन्होंने कोर्ट में मामला किया है, उसका दर्द यहां पर भी व्यक्त कर दिया। हम तो इसलिए चुप थे कि आपने कोर्ट में किया है, कोर्ट में ही जवाब देंगें। कोर्ट समन करेगा और लोग जवाब देंगें, जो देना होगा। आप अपना पक्ष

रखेंगें, जिन पर आपने केस किया है वे अपना पक्ष रखेंगें लेकिन मेरा यह निवेदन है कि इस पीठ पर बैठने वाले व्यक्ति को संसदीय शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए और तथ्यों पर ही बात करनी चाहिए। धन्यवाद।

08.03.2017/1250/केएस/एएस/2

अध्यक्षः अब श्रीमती सरवीन चौधरी जी चर्चा में भाग लेंगी।

श्रीमती सरवीन चौधरीः अध्यक्ष महोदय, जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण इस माननीय सदन में रखा गया, उसमें चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। जिस तरीके से इस सदन में पक्ष के लोगों को बोलने का मौका मिला, मैं सबसे पहले यह कहना चाहती हूं कि अभी-अभी इस सदन के उपाध्यक्ष महोदय ने यहां पर अपनी बात रखी और जिस शालीनता के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष ने उनको सुना और उसका जवाब दिया, यह बात पक्ष में बैठे लोगों के नेताओं को भी सीखनी चाहिए। ये दस-दस बार एक-एक सदस्य के बीच में उठकर उसको इंट्रप्ट करते हैं। बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से कांग्रेस को सीखनी चाहिए। जो हमने आरोप पत्र गवर्नर साहब को दिया है, गवर्नर साहब के अभिभाषण पर यहां पर चर्चा हो रही है और आप सभी डरे हुए हैं। सभी मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे हुए हैं। अगर उसका लम्बा चिट्ठा हम यहां पर पढ़ने लगें तो घण्टों लग जाएंगें और जिस तरीके से यहां पर उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि इनमें हिम्मत है तो लोकायुक्ता के पास कहें। समय आएगा, जहां जो जरूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के लोग वह भी करने को तैयार हैं। आप अपनी बात को किसी भी तरीके से मोड़ कर कहते हैं और आपका झूठ लगातार जनता के सामने आ रहा है और आने वाले दिनों में और तेज़ी से सामने आएगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक-एक व्यक्ति जो है, आरोप पत्र के ऊपर हमने बहुत ही सोच-समझकर, बहुत सी बातें तो छूट गई है, जो आपकी कमियां और आपका भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार से लिप्त जो कांग्रेस की सरकार है उसके चिट्ठे सामने आते हैं तो तकलीफ ज्यादा होती है विशेष रूप से आपके नेता को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। पता नहीं

किस कारण से वे इतने परेशान रहते हैं कि उनमें गुस्सा भी है ।जो चोरी और सीनाजोरी की बात कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है इसके ऊपर इनको नियंत्रण करना चाहिए। सबसे पहले आपने कहा कि सारे वायदे हमने पूरे कर लिए हैं, यह सबसे पहला झूठ और उसमें आप बताएं आपने कहा था हर घर को नौकरी मिलेगी।

08.03.2017/1250/केएस/एएस/3

क्या हर घर में नौकरी मिल गई? चुनाव आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी को अपनी सफाई देने के लिए घर-घर जाना पड़ेगा कि हम नौकरी क्यों नहीं दे पाए। लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि आप अपने वायदों पर ठीक नहीं उतरे हैं। आपने बेरोज़गारी भत्ते की बात को, जो केन्द्र का कौशल विकास भत्ता है, कुछ दिन के लिए कोशिश की कि उसका क्रेडिट लें लेकिन जनता समझती है कि कौशल विकास भत्ता क्या है? केन्द्र की स्कीमों का क्रेडिट लेने की आपकी आदत है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता इतने सक्षम हैं कि वे अपनी केन्द्र की स्कीमों को जनता तक पहुंचाएंगें और कांग्रेस को घर-घर नौकरी व भत्ते देने का जवाब जनता को देना ही पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मेरे से पहले सभी ने इस बात को यहां पर रखा कि सबका कल्याण समग्र विकास लेकिन वास्तव में सरकार को यह कहना चाहिए कि अपनों का कल्याण किया है आप लोगों ने और कुछ का विकास किया है। अपनों का ही कल्याण किया क्योंकि धरातल पर तो आपने यही किया और यही हो रहा है। जनता के पैसे को पानी की तरह आपने बहाया है जिसका जिक्र यहां पर होना चाहिए। जो चेयरमैन, वाईस चेयरमैन आपने लगाए हैं इससे जो कॉर्पोरेशन्ज़ घाटे में चल रही हैं, उनके ऊपर और बोझ डाला है। उनकी गाड़ियों का, तनख्वाहों का, विदेशी दौरों पर आपने जिस तरीके से चेयरमैनों और वाईसचेयरमैनों के ऊपर खर्च किया उससे कॉर्पोरेशन्ज़ और घाटे में जाती रही। इसी के साथ-साथ आप लोगों ने एडिशनल एडवोकेट्स जनरल की एक लम्बी फौज खड़ी की है। उस फौज ने क्या किया, किसका विकास किया? मुख्य मंत्री अपने केसों की पैरवी के लिए सरकारी वकीलों का इस्तेमाल

करते रहे। इसीलिए आपने एडिशनल एडवोकेट जनरल इतने ज्यादा लगाए। उन्होंने किसका विकास किया ?

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

8.3.2017/1255/av/AS/1

श्रीमती सरवीन चौधरी-------- जारी

उन्होंने अपना विकास किया होगा। उन्होंने अपनी पैरवी की होगी। इसी के साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि खर्चा प्रदेश सरकार का हो रहा है और दिल्ली जाने के बारे में जो यहां पर बार-बार प्रश्न लगते रहे कि कितना खर्चा हुआ या किस मकसद से गये? उस बारे में एक ही जवाब आता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। इस प्रकार का उत्तर सीधे-सीधे दर्शाता है कि यह सरकार फिजूलखर्ची भी करती रही और अपना कल्याण तथा कुछ लोगों का विकास करती रही। कल ही कोई डिसकस कर रहा था, मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहती। कांग्रेस पार्टी की सरकार के लोगों को जनता के विकास का काम भूल गया है।

यहां पर बार-बार शिक्षा की गुणवत्ता की बात की जा रही है। मेरे से पहले वक्ता ने भी अपनी बात में शिक्षा के बारे में बड़ी लम्बी-चौड़ी दलीलें दी है। दलीलें ऐसी दी गई कि अपनी बात को तोड़-मरोड़ कर अपनी सरकार के पक्ष में करने की कोशिश की गई। गुणवत्ता किस चीज से आती है? ज्यादा इनस्टिच्यूट खोलने से तो शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता नहीं आ सकती। प्राइवेट स्कूल में लोगों को कैसे ठगा जा रहा है यह तो मुख्य मंत्री जी के अपने बेटे ने ही उनसे प्रश्न कर दिया। यह *अमर उजाला* में आया है कि 'निजी स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसे हिमाचल सरकार'। यह अच्छी बात है क्योंकि यह विभाग मुख्य मंत्री जी के पास है। एक जमाना था जब पिता अपने पुत्र को पत्र लिखता था। एक बार बिड़ला ने अपने बेटे को पत्र लिखा था कि जब पैसे ज्यादा हो जाए तो उसे लोगों की भलाई

/ सेवा के लिए लगाना चाहिए। यह पत्र बहुत सुंदर लिखा गया है। लेकिन आज जमाना उल्टा हो गया क्योंकि पुत्र अपने पिता को लिखता है कि अपना विभाग तो देख लो कि इसमें कितनी गुणवत्ता है। अगर प्राइवेट सरकार अपने मनमाने ढंग से पैसे वसूल कर रहे हैं तो हिमाचल सरकार क्या कर रही है? आप लैपटोप देने की बात करते हैं और कहते हैं कि शिक्षा विभाग में इतने लैपटोप दे दिए। मैं पूछना चाहती हूं कि प्राइवेट स्कूलों में कितने लैपटोप दिए गए? प्राइवेट स्कूल तो अच्छी फीस लेते हैं, उनके पास पैसा भी है और उनको टैक्स में भी छूट है। प्राइवेट स्कूल के मेधावी छात्रों को भी स्कूल की तरफ से लैपटोप दिए

8.3.2017/1255/av/AS/2

जाने चाहिए थे। सरकार का दायित्व था कि सरकारी स्कूलों में सर्वेक्षण करवाये कि उनमें किन लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। इस बारे में एक सर्वेक्षण करवाकर उन बच्चों को जो मेधावी बच्चे थे उनकी सीमा तय करके उन बच्चों को लैपटोप तथा दूसरी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए थी। मुख्य मंत्री जी शिक्षा विभाग की तरफ से इस तरीके से ड्रामा कर रहे हैं। उनका अपने विभाग पर कंट्रोल नहीं है। शिक्षा विभाग एक अधिसूचना जारी करता है कि इग्ज़ाम से पहले स्कूल्स में फंक्शन नहीं होंगे। मगर स्कूलों में फरवरी महीने तक भी ढोल-ढमाके होते रहे और कांग्रेस के नेता वहां पर पूरी शानो-शौकत के साथ कार्यक्रम देखते रहे तथा बच्चों की पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं की गई। वैसे तो चुने हुए विधायक को स्कूलों के फंक्शन में बुलाना चाहिए लेकिन कांग्रेस पार्टी तो इतनी संकीर्ण सोच की पार्टी है कि यहां एक भी स्कूल में कभी भी विधायक को न बुलाकर ऐसे शख्स को बुलाया जाता है जिनका शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं है। वे लोग कितने पढ़े हैं मुझे नहीं पता और वे स्कूलों में जाकर किस प्रकार का वातावरण रखते हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती। मगर जो अधिसूचना मुख्य मंत्री के विभाग से जारी हुई अगर उस पर ही असर नहीं हो रहा है तो उसको मुख्य मंत्री जी को देखना चाहिए कि स्कूलों में किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है। आपके लोग स्कूलों में रोज़ किस प्रकार के प्रोग्राम कर रहे हैं। पिछले 15-20 दिनों पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि स्कूल की छत गिर गई। मुझे अभी उस स्कूल का नाम याद नहीं आ रहा है। बच्चे पंचायत घर या खुले में पढ़ने के लिए बिठाए गये। आज भी गवर्नमैंट स्कूल्स का यह हाल है कि उनकी बिल्डिंग की छत गिर रही है। इतना फंड आ रहा है, यहां

तक कि केंद्र से जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत पैसा आ रहा है उसका भी यह सरकार दुरुपयोग कर रही है। मैं शाहपुर तक सीमित रहते हुए एक उदाहरण देना चाहूंगी कि शाहपुर, दरगेला, रैलू, चढ़ी, बो और कल्याड़ा में आर0एम0एस0ए0 के तहत कहीं 20 लाख, कहीं 24 और

श्री वर्मा द्वारा जारी

08/03/2017/1300/टी0सी0वी0/डी0सी0/1
श्रीमती सरवीण चौधरी.....जारी।

कहीं 29 लाख रुपये विद फर्निचर पैसा आया। हिमाचल सरकार ने इसकी ड्राईंग ही चेंज कर दी, जहां 4-4 कमरे बनने चाहिए थे, वहां एक-एक कमरा बना। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। केन्द्र का पैसा जो स्कूल में आया उसका दुरुपयोग क्यों हुआ? जहां 29-29 लाख रूपया स्कूलों में आया और इन स्कूलों के नाम मैंने दिए हैं। इसमें माननीय मुख्य मंत्री इंक्वायरी करें और शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर हैं, उनसे पूछें ये कैसे हुआ है। केन्द्र ने जो ड्राईंग दी, उसको क्यों बदला गया? केन्द्र के पैसों का दुरुपयोग क्यों किया गया? इसी तरह से पहली से आठवीं तक के एग्जाम बोर्ड द्वारा लेने का ड्रामा किया गया। बोर्ड ने प्रश्न पत्र, आंसरशीट दे दी और उन्हीं स्कूलों में टीचर्ज ने पेपर लिए और रिजल्ट बनाकर बोर्ड को दे दिया। बोर्ड ने इस रिजल्ट को अपनी वैबसाइट में डाल दिया। मैं पूछना चाहती हूं कि स्कूलों में छात्र/छात्राओं को मार्क्सशीट क्यों नहीं मिल रही है। इससे पहले छात्र/छात्राओं को मार्क्स बताये जाते थे, कि किसी सब्जैक्ट में कितने मार्क्स हैं? लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। Continuous & Comprehensive Evaluation (CCE) के मार्क्स जो एड होने थे, वह नहीं हुए हैं और आठवीं के बच्चों को 9वीं क्लॉस में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट दे दिए जाते हैं, लेकिन जो सर्टीफिकेट मार्क्सशीट मिलना चाहिए था, वह उनको नहीं मिल रहा है। विभाग कहता है कि शिक्षा बोर्ड देगा और बोर्ड करता है कि विभाग देगा। पहले एस0एस0ए0 के माध्यम से सर्टीफिकेट मिलते थे, लेकिन शिक्षा विभाग का इतना बुरा हाल है, न बोर्ड को क्लीयर गाइडेंस पता है और न ही विभाग को क्लीयर गाइडडेंस पता है। ये विभाग मुख्य मंत्री जी के पास है। स्कूलों में फंक्शन करनवाने में ही कांग्रेस के लोग मस्त रहते हैं, उनकी तकलीफ़ों को भी इन्हें देखना चाहिए

था। इसके साथ ही स्कूलों के आसपास नशीले कैप्सूल बिक रहे हैं। ये कहते हैं कि नशे के ऊपर हमने अभियान चलाया हुआ है। मैं दावे से कह सकती हूं, आज भी अगर पुलिस सीरियस हों, स्कूलों के आसपास नशे के कैप्सूल बिक रहे हैं। नशे के कुछ ऐसे मादक पदार्थ हैं, जिन पर बहुत लम्बी सजा है, लेकिन जहां तक कैप्सूल की बात आती है, एक दिन पकड़ते हैं, दूसरे दिन जमानत हो जाती है और चौथे दिन वे फिर कैप्सूल बेचने शुरू कर देते हैं। जिससे हमारी युवा पीड़ी का भविष्य बुरी तरह से खराब हो रहा है। मैं शाहपुर के एक स्कूल की बात करना चाहती हूं। मैं स्कूल का नाम कोट नहीं करना चाहती हूं, उस स्कूल में टीचर्ज़ ने चैकिंग की और वहां पर विद्यार्थियों के बैग से शराब की बोतलें

08/03/2017/1300/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

निकली और एक विद्यार्थी तो नशे में इतना धूत था कि टीचर्ज़ को उसको पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ा। उसका केस नहीं बनाया गया। लेकिन आज समाज को सुधारने की जरूरत है। स्कूल के आसपास शराब पीकर लोग बैठे रहते हैं और स्कूल की छात्राओं पर जो कोमेंट हो रहे हैं, उसके बारे में लोग आये दिन हमसे शिकायत कर रहे हैं। इसलिए हिमाचल सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। यहां पर हिमाचल प्रदेश में एस0एम0सी0 और आउटसोर्सिज पर जो कर्मचारी लगे हैं, उनके बारे में भी चर्चा हुई। पिछले कल श्री किशोरी लाल जी यहां पर ओ0बी0सी के लिए आरक्षण की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहती हूं कि इनको 18 प्रतिशत आरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे दिया है। आपकी सरकार को चाहिए था कि कम-से-कम ओ0बी0सी0 का सर्वेक्षण ही करवा देते। ताकि पता चल पाता कि हिमाचल प्रदेश में ओ0बी0सी0 कितने हैं? जहां तक आरक्षण की बात है वह 18 प्रतिशत है, यह भी हमारी सरकार ने किया है। आपकी सरकार ने 27 परसेंट के बारे में क्या सोचा? आपने कभी इनका सर्वेक्षण करवाने की कोशिश की है? आपने तो यहां पर ओ0बी0सी0 का मंत्री ही नहीं बनाया, जो सरकार तक ओ0बी0सी0 का पक्ष रख सकता था। इस प्रदेश में ओ0बी0सी0 एक जात नहीं है, जैसे एस0सी0 एक पर्टिकुलर बिरादरी नहीं है, बहुत-सी बिरादरियां एस0सी0 में आती है। इसी तरह ओ0बी0सी0 में भी एक लम्बी बिरादरी है। मेरे ख्याल से 48 बिरादरियां उसमें आती हैं। आपकी कांग्रेस सरकार कम-से-कम सर्वेक्षण तो करवा लेती ताकि पता चलता कि इनकी संख्या कितनी है? ये जो 18 परसेंट

आरक्षण है, ये तो पुराने सर्वेक्षण के हिसाब से हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने दिया हुआ है। माननीय धूमल जी के समय में इसकी क्रिमीलेयर की लिमिट भी बढ़ती रही है।

श्रीमती एन0एस0 ... द्वारा जारी।

30/11/2015/1305/ एन0एस0/डी0सी0 /1

श्रीमती सरवीन चौधरी ----- जारी

आप भी कोशिश कीजिए ताकि समाज में सबको इक्वैलिटी और परसेंटेज़ के अनुसार रिजर्वेशन को सुनिश्चित किया जा सके। आज भी जब प्रश्न हो रहा था तो एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोगों का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। मैं मुख्य मंत्री जी के ऊपर सीधा आरोप लगाती हूं कि ये गोल-मोल जवाब देते रहे हैं और यह इसमें सीरियस नहीं हैं तथा किसी भी नौकरी में यह रोस्टर फोलो नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार को यह भुगतना पड़ेगा क्योंकि जब भी नौकरियों की बात आई इन्होंने रोस्टर को दरकिनार किया है। इन्होंने ऐसा कुछ ही वर्गों के विकास के लिए नहीं किया बल्कि सबके के लिए ही इन्होंने ऐसा किया है। अगर उसके बीच में थोड़े से एस.सी., एस.टी., या ओ.बी.सी. आ गए हैं तब वह अलग बात है। मैं समझती हूं कि आप लोगों को रोस्टर लागू करना चाहिए और इन जातियों के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। यहां पर आपने 'फसल बीमा योजना' का ज़िक्र किया है। यह भी अच्छा होता अगर आप 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' का भी यहां ज़िक्र करते जिसको केंद्र सरकार ने दिया है और उसकी डी0पी0आर0 आप यहां पर बनारहे हैं। आपने इस स्कीम को पैराग्राफ 33 में रखा है। आपने इसमें केंद्र की 'प्रधानमंत्री सिंचाई योजना' का कोई ज़िक्र नहीं किया है। आप केवल अपनी ही पीठ मत थपथपाओ, जो केंद्र दे रहा है उसका भी साथ-साथ धन्यवाद करते रहो ताकि केंद्र से आप बराबर डी0पी0आर्ज़0 बना कर विकास करवा सकें। आपने 500 हैक्टेयर क्षेत्र पर उत्पादन की बात कही है । मैं सेब के बगीचों की बात कहना चाहूंगी। पीछे हाई कोर्ट का एक आदेश सेब के बगीचों से पेड़ काटने का आया था। मुझे लगता है कि उस बैल्ट के लोगों में जब राजा ने ही

नाज़ायज जमीन पटवारियों से लिखवा कर ले ली और सोचा कि हम तो सुप्रीम है ऐसा चलता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और अधिकारी भी खुश करने की हौड़ में होते हैं। जब उन्होंने इतने हैक्टेयर जमीन कैप्चर कर ली और बगीचे लगा लिए तब बाकी जनता ने भी यह सोचा

30/11/2015/1305/ एन0एस0/डी0सी0 /2

कि हमें भी क्या फर्क पड़ेगा हम भी इसी हौड़ में करते हैं। लेकिन जब कोर्ट का डिसीजन आया कि पेड़ काटो। तब मुझे लगता था कि हिमाचल सरकार को कोर्ट में अपनी दलील रखनी चाहिए थी। लगे हुए पेड़ों को काटने की बजाए हिमाचल सरकार को कहना चाहिए था कि इन पेड़ों को लगा रहने दो और इस एरिया को पंचायत के अंडर कर दो तथा इसमें जो सेब लगेंगे उनको बेच कर एक इनकम का सोर्स बन जाएगा। परन्तु इन्होंने कुछ पेड़ गरीबों के दिखाने के लिए कटवा दिये और अमीरों के वैसे ही पड़े हुए हैं। इसलिए जब लाठी पड़ती है तो हमेशा गरीब के ऊपर पड़ती है। वर्तमान सरकार को इस तरीके से सेबों की पैरवी करनी चाहिए थी। हमारे समय में जब श्री ब्राक्टा जी मंत्री होते थे तो मुझे याद है कि मैडम स्टोक्स ने एंटी हेलगन का बड़ा विरोध किया था। इन्होंने कहा था कि यह बागवानों के साथ मज़ाक है। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसका रिजल्ट आने में टाईम लगता है। उस समय कांग्रेस के लोगों ने बहुत शोर किया लेकिन आज लोग एंटी हेलगन को प्राईवेटली भी लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार, बेईमानी, ज्यादा कीमत पर सामान खरीदना इस सरकार में बहुत क्लीयर है। हरेक जगह, विभाग में हम इसको क्लीयेरिटी से देख सकते हैं। (घण्टी) अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा समय चाहिए। एंटी हेलगन के परिणाम आज सामने आ रहे हैं। आपने यहां पर एल.इ.डी. बल्ब की बात कही है। यहां पर किसी का कोई स्कूल, क्रशर या कोई अन्य बिजनैस होगा या कोई विरला ही ऐसा होगा जिसका मेरी तरह कोई बिजनैस नहीं है। मंत्री जी आप तो उसका उत्तर दें जो आप पर सी.आई.डी. ने केस किया है। आपने 50 या 60 रूपये के एल.इ.डी. को कैसे 100 और 105 रूपये में बेच दिया? इसके लिए जिम्मेवारी तो मंत्री की ही फिक्स होती है। (व्यवधान) आपने अखबारों में पैम्पलेट भेजा था और आपने उसमें 'बचत योजना' के नाम से क्रेडिट लेने की कोशिश की है। ये पैम्पलेट हिमाचल प्रदेश में सब जगह बांटे गए हैं और नई उजाला योजना के नाम से बंटे थे। यह स्कीम केंद्र की है और केंद्र आपसे इसकी पूरी पैरवी करेगा कि आपने बल्ब

मंहगे क्यों दिये हैं? जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 50 या 60 रूपये में बल्ब देने की बात कही तब हिमाचल में यह इतना महंगा क्यों हो गया? आप शान्तिपूर्वक मेरी बात सुनिए क्योंकि आप सब भी उसी में संलिप्त हैं।

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

08/03/2017/1310/RKS/AG/1

श्रीमती सरवीन चौधरी... जारी

पैराग्लाइडिंग में जिस तरह से करोड़ों रुपये का घपला हुआ है वह भी सामने है। शुद्ध पानी की जब बात आती है तो श्रीमती विद्या स्टोक्स जब इधर बैठी होती थी तो कहती थी कि मेरा पेट ही खराब रहता है। मैं तो वी.आई.पी. एरिया में रहती हूं। यहां का पानी बहुत बुरा है। अब कंकाल वाला पानी पीकर उनका पेट बिल्कुल साफ चल रहा है। जब आप इस तरफ होते हैं तो परिभाषा कुछ और होती है। आज श्री महेन्द्र सिंह जी ने यहां पर घोटालों का जिक्र किया। आई.पी.एच. विभाग जिस तरह से चल रहा है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहती हूं। जिस तरह से ठेकेदारी हो रही है मैं उस पर भी कमेंट नहीं करना चाहती हूं। सुन्दरनगर में एयरक्राफ्ट की रिपेयर का मामला भी एक मज़ाक है। आपने पैंशन की बात कही। आपने कहा कि 60 हजार लोगों को नई पैंशनें दी गई परन्तु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक लाख से ज्यादा लोगों को नई पैंशनें दी थी। यह मैं इस सदन में दावे के साथ कहती हूं।

नोटबंदी के ऊपर कांग्रेसी बहुत हौ-हल्ला करते हैं। माननीय सदस्य श्री संजय रतन जी ने इसके ऊपर बहुत कुछ कहा और वे भीतर से बहुत दुःखी हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता ने नोटबंदी के ऊपर कभी एजिटेशन नहीं किया। किसी ने यह नहीं कहा कि यह गलत है। नेताओं को मज़बूरी में कहना पड़ा कि यह गलत है। मुझे लगता है इनका हस्तिनापुर नोट वाले लोगों के पास है। सत्तापक्ष के लोग इससे बहुत दुःखी हैं, जबकि हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें पार्टियों का तो कोई सवाल ही नहीं था। यह तो एक

सच्चाई की बात थी। जिसके पास ज्यादा नोट थे वे रद्दी बन गए। इसके लिए हम मोदी जी को धन्यवाद करते हैं।

Speaker: Madam, please try to wind-up.

श्री सरवीन चौधरी: सर, आज महिला दिवस है और आप मुझे 10 मिनट और दे दीजिए।

08/03/2017/1310/RKS/AG/2

Speaker: No, no. I will stop you down. I will give you five minutes. You please wind-up in five minutes. Okay.

श्रीमती सरवीन चौधरी: अध्यक्ष महोदय, श्री संजय रतन जी ने होलीलॉज की बात कही। मैं कहना चाहती हूं कि आपने मुख्य मंत्री जी की रिसैटल प्लान बना दी है। आपने जोश में बड़ी प्रशंसा की कि धर्मशाला में दूसरा होलीलॉज बना दिया जाए। मुख्य मंत्री जी वहां रहे, ऐसा बहुत कुछ कहा। हम सब जानते हैं कि यहां पर भी होलीलॉज है। इस हॉलीलॉज में बहुत तंगी आ रही है क्योंकि यह किराये पर भी दिया हुआ है। आपने उनका रिसैटल प्लान बना दिया, उसके लिए आपको बधाई। आपके कई लोग मुख्य मंत्री की लाइन में खड़े हुए हैं लेकिन किसी का सपना पूरा नहीं होगा। क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहां पर वन मंत्री जी बैठे नहीं है। मिड हिमालय में बहुत घोटाले हुए हैं। कम्यूनिटी सैंटर जो बाई लॉज में है ही नहीं, जो प्रोजैक्ट के अंदर चीजें आती ही नहीं, उनकी भी खरीददारियां कर ली गई। कम्यूनिटी सैंटर बना दिए गए, उनके शिलान्यास, उद्घाटन भी कर दिए गए। समय आएगा, अगर केन्द्र के पैसे का दुरुपयोग हुआ होगा। जिन्होंने शिलान्यास, उद्घाटन किए हैं और उन अधिकारियों पर भी गाज़ गिरेगी जिन्होंने मिड हिमालय प्रोजैक्ट के पैसे का दुरुपयोग किया है। कई मशीनें खरीद कर दे रहे हैं जोकि उनके बाई लॉज में है ही नहीं। कल श्रीमती आशा जी कह रही थी कि बेटों की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर बेटे सही नहीं हो तो बात करने में हर्ज़ भी क्या है। मैपल डैस्टिनेशन एंड ड्रीमबिल्ड कम्पनी किसने बनाई? वर्ष 2011 में दिल्ली में,

डेरा मंडी, महरोली में एक फार्म हाऊस किसने खरीदा? वक्कामुल्ला कौन है? मेरे पास लम्बी डिटेल है। यदि किसी ने बड़ा घोटाला किया हो तो यह मामला यहां आना चाहिए। मेरे पास केंद्र सरकार की भी लम्बी लिस्ट है, वह लम्बी लिस्ट शायद जरयाल जी ने कल यहां रखी थी। आपके घोटालों की भी लम्बी लिस्ट है,

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

08.03.2017/1315/SLS-AG-1

श्रीमती सरवीन चौधरी ...जारी

आप कहें तो मैं पढ़ दूं। ...(व्यवधान)... इस लिस्ट में कांग्रेस सरकार के लंबे-चौड़े घोटालों की बात है जिसे मैं यहां पर ले कर दूंगी। इनमें बोफोर्स घोटाला है, शेयर घोटाला है, चीनी घोटाला है। यह लंबी लिस्ट है और इसे मैं अपने भाषण में ऐड करना चाहूंगी, इसलिए मैं इसे यहां पर रख दूंगी।

अध्यक्ष महोदय, कल आशा जी ने कमैंट किया। मैं उसके ऊपर भी आना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि हम गधों से कोई प्रेरणा नहीं लेते। मैं कहना चाहूंगी कि कोई व्यक्ति जानवर से, कोई पेड़-पौधों से और कोई सेव से प्रेरणा ले लेता है। यह भी कहा जाता है कि गधों की तरह काम करो। यह मेरी आपको एडवाइज़ है। गधों की तरह काम करने का मतलब है - मेहनत करो। भ्रष्टाचार कम करो, लोगों का काम करो और सच्चाई पर चलो। तो गधों की तरह आप काम करो। कांग्रेस पार्टी को काम करने की जरूरत है। ***..(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, यह मुहाबरा है और इस मुहाबरे को मैं बार-बार कह सकती हूं। ...(व्यवधान)... यह मुहाबरा है और यह हमारी किताबों में लिखा हुआ मुहाबरा है कि समय आने पर गधे को भी बाप बनाओ और गधे की तरह काम करो। ...(व्यवधान)... यह मुहाबरा हमारी किताबों में लिखा हुआ है।...(व्यवधान).... संजय, यह मुहाबरा है, इसमें क्या हो

गया।...(व्यवधान)... कल ऐसे ही हो रहा था...(व्यवधान)... मैं भी ऐसे कह सकती हूं क्योंकि कल ऐसा हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह सत्तापक्ष की ओर संकेत करके और नाम लेकर कहा है, इसलिए इसे कार्यवाही से एक्सपंज किया जाए। ...(व्यवधान)...

08.03.2017/1315/SLS-AG-2

श्रीमती सरवीन चौधरी : नहीं, एक्सपंज नहीं होगा। ...(व्यवधान)... यह हिंदी का मुहाबरा है और यह सही उतरता है।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : इन शब्दों को कार्यवाही से एक्सपंज किया जाता है।

श्रीमती सरवीन चौधरी : नहीं, सर, अगर आप एक्सपंज करेंगे तो मैं बजट स्पीच में दोबारा बोलूंगी। ...(व्यवधान)... मैं बजट स्पीच में बोलूंगी कि कुछ लोग समय आने पर ऐसा करते है। यह हिंदी का मुहाबरा है और इसे एक्सपंज करने वाली कोई बात नहीं है।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक मध्याह्न भोजन के लिए 2.10 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

————————————————————————————————

*** अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

08/03/2017/1415/RG/AS/1

(विधान सभा की बैठक भोजनावकाश के उपरांत पुनः आरम्भ हुई)

अध्यक्ष : अब श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी, माननीय मुख्य संसदीय सचिव चर्चा में भाग लेंगे।

मुख्य संसदीय सचिव(श्री इन्द्र दत्त लखनपाल) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1 मार्च, 2017 को प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के ऊपर इस सदन में

जो अभिभाषण पढ़ा और उसके सन्दर्भ में माननीय मुख्य संसदीय सचिव श्री जगजीवन पाल जी सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आए तथा उसका अनुसमर्थन माननीय विधायक श्री संजय रतन जी ने किया। इस संबंध में, मैं इस अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, पिछले चार वर्षों से माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का जो समग्र विकास हुआ है वह हमारे साथी विपक्ष के लोगों को पसन्द नहीं आ रहा है। पिछले तीन-चार दिनों से जो इस अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की गई उसमें विपक्ष के लोगों ने केवल मात्र राजनीतिक आधार पर सुर्खियों में बने रहने के लिए बहुत ही निम्न स्तर की यहां टिप्पणियां कीं। अच्छा होता कि वे सरकार की कमियों के साथ-साथ

एम.एस. द्वारा जारी

08/03/2017/1420/MS/AS/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (मुख्य संसदीय सचिव)जारी------

जो इस अभिभाषण में शब्द लिखे गए हैं, जो प्रदेश के विकास के लिए आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने एक गम्भीरता के साथ निर्णय लिया है और इस पहाड़ी राज्य का जो एक मॉडल के रूप में विकास किया है, उसके ऊपर भी धन्यवाद करते। इन्होंने केवल-मात्र अपनी राजनीति चमकाने के लिए निम्न स्तर की बातें कहीं और बेतुकी बयानबाजी करते हुए प्रदेश में जो इन चार वर्षों में विकास हुआ है, उस पर नाकाम पर्दा डालने की कोशिश की है। आज प्रदेश के किसी भी कोने में आप चले जाएं। जो इस प्रदेश के आम नागरिक हैं, चाहे वे किसान, बागवान, मजदूर या हमारे कर्मचारी हैं, सब खुश हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग जो हमारे प्रदेश में कर्मचारियों का है वह आज खुशी से फूला नहीं समाता है क्योंकि कई निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में लिए गए हैं। उनके वेतन-भत्ते बढ़ाए गए और उनकी पदोन्नतियां जो लम्बे समय से रूकी हुई थीं, की गईं। वह क्या कम काम है? हमारे प्रदेश में जो कर्मचारी सरकार की नीतियों को अमलीजामा पहनाते हैं उनको जो लाभ दिया गया है, वह क्या आपको मालूम नहीं है? आपको उसके

लिए धन्यवाद करना चाहिए था। आज 3000 के लगभग दैनिक वेतन-भोगी जलवाहक जो हमारे प्रदेश में काम कर रहे थे, उनको मान-सम्मान मिला और आज नियमित होकर उनको पोस्टिंग मिली है। क्या यह भी कम बात है? क्या यह आप लोगों के लिए गवारा नहीं है या आप लोग मना कर दें कि ये जो सरकार ने किया है यह गलत किया है? आप छोटी चीज के ऊपर क्यों बात करते हैं? जो समग्र विकास हुआ है और जो इस अभिभाषण में बातें लिखी गईं हैं वे चाहे पशु पालन के लिए हों, चाहे बागवानी के ऊपर हों या वाणिकी के ऊपर हों, आप इसके हरेक पहलू को देखते और फिर उसके ऊपर चर्चा करते। आज जो अनुबन्ध आधार पर अध्यापक थे उनको नियमित किया गया है क्या वह कम बात है? वर्ष में दो बार उनको नियमित करने का तोहफा दिया गया है, क्या वह भी कम बात है? हजारों पी0टी0ए0 अध्यापक जिनके ऊपर तलवार लटकी हुई थी, आज उनको अनुबन्ध पर लाया गया है। क्या वह भी कम बात है? आज लोक निर्माण विभाग में जो

08/03/2017/1420/MS/AS/2

दिहाड़ीदार हैं उनको नियमित किया गया है, उनको वेतन वृद्धि दी गई है। इसके अलावा हमारे प्रदेश में वृद्ध लोग जो आत्म-सम्मान से जीना चाहते हैं उनको आदरणीय वीरभद्र सिंह जी ने सम्मान दिया, सामाजिक सुरक्षा पैंशन दी, क्या वह छोटी बात है? आज महिलाओं को जिस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी गई और जो विवाह योग्य कन्याएं हैं, उनके लिए "मुख्य मंत्री कन्यादान योजना" के तहत दी जाने वाली राशि में वृद्धि करके उसको 40 हजार रुपये किया गया है, क्या वह छोटी बात है? क्या यह बात आप लोगों की समझ में नहीं आती है? तब तो आप लोग भी यदि आपके क्षेत्र में कोई ऐसी कन्या हो जिसका विवाह करना हो, तब आप मुख्य मंत्री जी के पास चापलूसी करते हैं और वहां से पैसा स्वीकृत करवाते हैं। क्या यह विकास की बात नहीं है? इसी प्रकार से अन्य भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्रदेश में चलाई गई हैं।

इसी तरह से जो गम्भीर रूप से बीमारी से पीड़ित लोग होते हैं जब उन्होंने पी0जी0आई0 या अन्य दूर-दराज के क्षेत्रों में इलाज के लिए जाना होता है तो उनके साथ एक अटैंडेंट को बस में सफर की फ्री सुविधा दी गई है। इसके अलावा एम्बुलैंस में मातृत्व

सेवा के लिए घर से अस्पताल तक ले जाने और घर तक छोड़ने के लिए मुफ्त में एम्बुलैंस सेवाएं दी जा रही हैं क्या यह भी छोटी बात है?

अध्यक्ष जी, इस पहाड़ी राज्य में सड़कों का जो सुदृढ़ीकरण हुआ है, इसके बारे में कल यहां पर हमारे साथी बोल रहे थे कि शिमला से कांगड़ा तक सड़क गड्ढों में तब्दील है। आपको मालूम होना चाहिए कि 300-400 करोड़ रुपये की लागत से कन्दरौर से लेकर कांगड़ा तक सड़क का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है जिसमें 11 पुलों का भी निर्माण किया जा रहा है। क्या यह छोटी बात है? आज पूरे प्रदेश के अंदर सीमित साधनों के बावजूद माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने योजनाबद्ध तरीके से एक मैनेजमैंट के हिसाब से जो प्रदेश का विकास किया है यह छोटी बात नहीं है।

जहां तक मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र की बात है, मेरे बड़सर विधान सभा क्षेत्र में पिछले चार वर्षों से 11 बड़े पुलों पर काम चला हुआ है जो वर्षों से अधर में लटके हुए थे। लोगों को आवाजाही के लिए समस्या आती थी। कनैक्टिविटी की वजह से लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही थी लेकिन आज वे काम हो रहे हैं

08/03/2017/1420/MS/AS/3

हैं। 6-7 सड़कें जो 5-5 और 6-6 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही हैं क्या ये विकास के काम नहीं हैं? आई0पी0एच0 विभाग में खड्डों के ऊपर चैक डैम लगाए जा रहे हैं, तटीयकरण किया जा रहा है और नई-नई मशीनरीज लगाई जा रही हैं। पुराने पम्पिंग स्टेशन बदले जा रहे हैं और नई-नई लाइनें बिछाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो पिछले 20-30 सालों से पाइपें सड़ गई थी उनको बदला गया है।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

08.03.2017/1425/जेके/डीसी/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री इन्द्र दत्त लखनपाल):------**जारी**-----

क्या ये विकास के काम नहीं है? और तो और जो जिलाधीश महोदय को केन्द्र सरकार से रिलीफ का पैसा आता है, उसके अन्दर केन्द्र सरकार ने कट लगाया। आप कहते हैं कि केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार को भरपूर बजट दे रही है। इससे पहले क्या केन्द्र में जब यू0पी0ए0 सरकार थी और उस समय यहां पर आपकी सरकार में मुख्य मंत्री, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी थे तो वे हमारे केन्द्र के मंत्रियों का धन्यवाद करने जाते थे कि हमें अनुदान मिला है और हमें सब कुछ मिल रहा है और ये प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी का धन्यवाद करते हैं? जैसे ही ये परवाणू से ऊपर आते थे तो कहते थे कि हमसे भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव तो अब किया जा रहा है। सिंचाई योजना में कट लगा दिया। टूरिज्म में कट लगा दिया। जितनी भी हमारी ग्रामीण योजनाएं थी उनमें केन्द्र सरकार ने कट लगा दिया। ये आंकड़े बोलते हैं। विभाग बोलते हैं और विभाग के अधिकारी रिपोर्ट देते हैं, यह भेदभाव नहीं है तो और क्या है? देश में जब एन0डी0ए0 की सरकार बननी थी उस समय मोदी जी ने प्रधान मंत्री बनना था तब बड़े-बड़े भाषण हुए। 100 दिन में मंहगाई कम कर देंगे। 100 दिन में पाकिस्तान से कटे हुए सर ले आएंगे। 100 दिन में काला धन विदेशों से देश में लाएंगे। काले धन के ऊपर नोट बन्दी पर जो यहां पर चर्चा कर रहे थे और अभी हमारी साथी माननीय विधायक, श्रीमती सरवीन चौधरी जी कह रही थी कि हमें नोटबन्दी से कोई फर्क नहीं पड़ा। निःसन्देह आपको कोई फर्क नहीं पड़ना था। फर्क उस आदमी को पड़ा जो गरीब व्यक्ति है, जो गांवों में काम करता है, मजदूरी का काम करता है, जो बोटी का काम करता है, जो बाल काटने का काम करता है और जो मजदूरी का काम करता है, उसको फर्क पड़ा है। जो किसान है, जो मध्यवर्गीय किसान है, बागवान है उसको फर्क पड़ा है। बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आम व्यक्ति है उससे कहा तो यह गया था कि विदेश से हम 100 दिन के अन्दर काला धन ले कर आएंगे। बड़ी-बड़ी बातें हुई कि बख्शा नहीं जाएगा। जेल में डाला जाएगा। 60 साल में कांग्रेस ने इस देश में बड़ा भारी भ्रष्टाचार किया। माननीय प्रधान मंत्री जी को ढाई साल हो गए हैं देश की सरकार को चलाते

हुए लेकिन एक भी कांग्रेसी जेल के पीछे आज तक नहीं गया है। ये सब झूठ पर आधारित बयानबाजियां करते हैं, वे समझ से परे हैं। देश के अन्दर एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। आज आई0टी0 युग की बात करते हैं, राष्ट्रीयकृत्त बैंकों की बात करते हैं, ये किसकी देने है? पंच वर्षीय योजनाएं यदि इस देश में चल रही है तो ये किस की देन है? अगर पृष्ठ भूमि को देखा जाए और इतिहास को देखा जाए जिस समय इस देश में सूई तक नहीं बनती थी आज इस प्रदेश में क्या नहीं हो रहा है, अगर उस ढांचे के अन्दर काम किया जा रहे है तो उसका भी धन्यवाद किया जाना चाहिए। ये एक निरन्तर प्रक्रिया है। देश में कोई सरकार होती है और प्रदेश में कोई अन्य सरकार होती है, लेकिन जो उसके संविधान के अनुसार हक-हकूक बनते हैं उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजनीतिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। विकास तो सभी का समग्र होना चाहिए और उससे भी आगे बढ़ने की बात की जानी चाहिए। आज प्रदेश में मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह जी ने जिस प्रकार से समग्र विकास किया है वह विपक्ष के लोगों को हज़म नहीं हो रहा है। जो इस अभिभाषण के अन्दर बातें लिखी गई हैं, जो आम जनता से जुड़ी हुई हैं, जिससे आम जनता का विकास हुआ है। आज हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय एक लाख से अधिक है, क्योंकि यह विकास केवलमात्र 5 या 10 वर्षों में हो गया, इसके लिए बहुत लम्बा समय लगा और सभी ने ईमानदारी से काम किया। चाहे इसमें विपक्ष के लोग मुख्यमंत्री मंत्री रहे हों, चाहे इधर से मुख्य मंत्री रहे हों। हमारे प्रदेश के लिए सभी ने अच्छा काम किया और यही कारण है कि आज हमारा प्रदेश पूरे देश में ईमानदारी के लिए जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जब बाहर जाता है पूरे देश के अन्दर तो हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति को ईमानदारी का तमगा मिलता है और यह हमारे लिए एक गर्व की बात है। दूसरे, जहां तक मनरेगा की मैं बात करना चाहूंगा कि पिछले ढाई वर्षों के अन्दर जो भेदभाव केन्द्र सरकार ने हमारी प्रदेश सरकार के साथ किया है उसका कोई नमूना पूरे देश में देखने को नहीं मिलता है। पूरी ऑडिट रिपोर्टस, पूरे

08.03.2017/1425/जेके/डीसी/3

आय-व्यय का जितना भी उनका पैसा आया उसकी पूरी रिपोर्ट हमने भेजी, लेकिन उसके बावजूद जो मटिरियल का पैसा था वह अभी तक हमें नहीं मिला है। आज भी हमारे क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से जो मजदूरी जिन लोगों ने की उनको पैसा नहीं मिल रहा है ये भेदभाव नहीं तो और क्या है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

08.03.2017/1430/SS-DC/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री इंद्र दत्त लखनपाल) क्रमागतः

14वें वित्तायोग की बात जब की जाती है तो पंचायती राज के अंदर जो जिला परिषद् और ब्लॉक समिति के सदस्य हैं उनकी पावर्ज़ खींचने के लिए वीरभद्र सरकार को दोषी ठहराया जाता है। आखिर क्यों? हमारे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि जब वे सरकार में आयेंगे तो इनकी शक्तियां बहाल करेंगे। अच्छा रहता कि आप लोग जब यहां प्रदेश सरकार ने और इस सदन ने भी यहां से प्रस्ताव पारित किया कि जिला परिषद् और ब्लॉक समिति के सदस्यों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, तो उसका समर्थन करते। वे चुनकर आए हैं उनको फंडस दिये जाने चाहिएं। लेकिन जो यह राजनीतिक आधार पर चर्चा और परिचर्चा होती है वह निंदनीय है। जो आपकी जिम्मेवारियां बनती हैं उनको गम्भीरता के साथ निभाया जाना चाहिए। वहां केन्द्र सरकार में अपना पक्ष रखना चाहिए कि हमारे चुने हुए लोगों को आर्थिक शक्तियां दें चाहे वे भारतीय जनता पार्टी से समर्थित हैं या कांग्रेस से समर्थित हैं सभी का काम समाज के विकास के लिए योगदान देने की बात होती है। लेकिन हम यहां अखबारों में पढ़ते हैं या जो विपक्ष के कार्यक्रम होते हैं तो वहां पर वे गुमराह करने वाले भाषण देते हैं। लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वीरभद्र सरकार ने किसी के हकों पर डाका नहीं डाला है। 14वें वित्तायोग में तीन-चार बार यहां से मैमोरैंडम गया तो

उसको वापिस भेजा गया कि हम इसको नहीं दे सकते हैं। इसके लिए हमने भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन किया है कि जिला परिषद् और ब्लॉक समिति के सदस्यों की पहले की तरह आर्थिक शक्तियां बहाल की जाएं ताकि उन्होंने चुनाव में जो लोगों से वायदे किये हैं उनको पूरा कर सकें।

आज महिला दिवस है। इसलिए मैं महिलाओं को महिला दिवस की बधाई भी देता हूं क्योंकि महिलाओं ने हमारे समाज का समग्र विकास किया है। आज जिस प्रकार से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़कर काम कर रही हैं वह हमारे लिए गौरव की बात है। यह कोई छोटी बात नहीं है। आज आप सड़क में देखिये, मनरेगा के माध्यम से हमारी माताएं, बहनें और महिलाएं काम करती हैं यह हमारे लिए गौरव की बात

08.03.2017/1430/SS-DC/2

है। यह जो हुआ है यह मनरेगा के माध्यम से हुआ है। जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रथम स्पीच दी थी जब वे इस देश के प्रधान मंत्री बने तो जो उनका तालियां पीट-पीट कर बात करने का स्टाइल है उसमें कहा कि मनरेगा के जो गढ्ढे हैं इसको मैं यू0पी0ए0 सरकार का प्रतीक चिन्ह बनाकर रखूंगा। आज तो मनरेगा के अंदर उनको दोबारा से भारी-भरकम बजट देना पड़ा। वाहवाही ले रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि मनरेगा के वगैर इस देश का काम चलने वाला नहीं है, यदि मनरेगा को बंद करने की कोशिश की तो पूरे देश में हाहाकार हो जायेगा, हमारा सामाजिक विरोध हो जायेगा तो फिर उनको इसमें फंडस का प्रावधान करना पड़ा। अगर आज उन फंडस का आबंटन देखा जाए तो केवल मात्र उन प्रदेश को ज्यादा दिया जा रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। दूसरी सरकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। चाहे वे किसी प्रकार के भी फंडस हैं उनमें जब आबंटन की बात आती है तो हिमाचल प्रदेश को टारगेट किया जाता है। बावजूद इसके कि वीरभद्र सिंह जी जिस कार्यकुशलता और दूरदृष्टि से इस प्रदेश का विकास निरंतर करते आ रहे हैं विपक्ष और अन्य लोगों के भारी विरोध के बावजूद वह अपने आप में एक मिसाल है। अध्यक्ष महोदय, आज जो पूरे देश के अंदर महंगाई की मार आम व्यक्ति को झेलनी पड़ रही है उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। आज गैस के सिलेण्डर के रेट कितने बढ़ गए। पैट्रोल-डीजल के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य कम हैं आज उनके दामों को क्यों कम नहीं

कर रहे? प्रधान मंत्री महोदय, जब दिल्ली के चुनाव थे, मुझे याद है, तब वहां पर ताली पीटकर बड़े जोर-जोर से कहते थे कि कैसा प्रधान मंत्री चाहिए, देश में तेल के रेट कम करने वाला चाहिए कि बढ़ाने वाला चाहिए। आज वे क्यों नहीं बोलते हैं? आज तो रेट बढ़ रहे हैं। आज कैसे रेट बढ़ रहे हैं? अपने ही बोले हुए चुनावी जुमलों में वे फंस चुके हैं। आज झूठ के सिवाय उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। इस देश की जो तरक्की हुई है वह कांग्रेस और यू0पी0ए0 सरकार की वजह से हुई है। आज वही नीतियां पूरे देश के अंदर चल रही हैं। मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने से कोई नयापन इस देश के अंदर नहीं आया है। दो करोड़ नौकरियां देंगे, यह उन्होंने बात की थी। बड़ी-बड़ी सभाओं के अंदर बात की थी कि प्रतिवर्ष दो करोड़ नौकरियां देंगे। अगर उस चीज़ को देखा जाए तो ढाई वर्ष के अंदर 5 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलनी थीं परन्तु इसी नोटबंदी की वजह से डेढ़ करोड़ नौकरियों की छंटनी हुई है, आने वाले समय में उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इस देश के युवा लोग इतने मूर्ख नहीं हैं

जारी श्रीमती के0एस0

08.03.2017/1435/केएस/एजी/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री इन्द्र दत्त लखनपाल) जारी----

कि दोबारा आपके साथ चलेंगें। आपको इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। हमारे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्य मंत्री महोदय के नेतृत्व में पिछले चार वर्षों से नौकरियों की भरमार हुई है। वह चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे कोई और क्षेत्र हो। आप आऊटसोर्सिंग की बात करते हैं। मिली तो उससे नौकरियां हमारे प्रदेश के लोगों को ही है। आज उसके ऊपर नीति बनाने की बात की जा रही है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आऊटसोर्स पर जो हमने कर्मचारी रखे हैं, उनको भी हम मुख्य धारा में लाएंगें और इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय बधाई के पात्र है। उनकी सोच है कि कर्मचारियों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। यह एक बड़ी सोच है। जहां आपको इस चीज़ का धन्यवाद करना चाहिए था, आप नकारात्मक रवैया अपनाकर उसकी आलोचना करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक आधारभूत ढांचे की बात है, हमारे प्रदेश के अंदर उसका सुदृढ़ीकरण हुआ है। उसकी विकास दर हमारे प्रदेश में बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारी अन्य दो-चार मांगे रह गई हैं, जो हमने घोषणा पत्र में लिखी थीं, उनके ऊपर भी इस वर्ष कार्रवाई होगी। हमें माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ऊपर पूरा विश्वास है कि अपनी दूरदर्शी सोच के अनुसार वे इसी बजट सैशन में जब नई घोषणाएं करेंगें तो जो हमारे घोषणापत्र के कुछ वायदे रह गए हैं, उनको हम पूरा करेंगें। हालांकि चार वर्षों में मुख्य मंत्री जी ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे प्रदेश में घूमकर एक-एक समस्या को समझकर, चाहे पी.एच.सी. खोलने की बात हो या सी.एच.सी. अपग्रेड करने की बात हो, स्कूलों को अपग्रेड करने की बात हो, उन्होंने भरपूर कार्य किया है और जिसने जो मांगा है, ऐसा नहीं है कि जहां से हमारे केवल कांग्रेस के ही विधायक जीतकर आए हैं, वहीं पर दिया है अपितु पूरे प्रदेश में जहां से कांग्रेस के विधायक भी नहीं हैं, वहां पर भी उन्होंने आम जनता की मांगों को पूरा किया है। वह चाहे कॉलेज खोलने की बात हो या स्कूल खोलने की बात हो, पानी की स्कीम की बात हो या सड़क पक्की करने की बात हो, उन्होंने कार्य किया

08.03.2017/1435/केएस/एजी/2

है। आज हमारे स्वर्ण जाति के जो पिछड़े हुए लोग थे, जो आई.आर.डी.पी. में, बी.पी.एल. में थे, उनको मकान बनाने के लिए मुख्य मंत्री आवास योजना का आगाज़ किया जिसके माध्यम से लोगों को पैसा मिल रहा है क्या यह धन्यवाद करने वाली बात नहीं है? आप लोगों के भी तो उसमें पंचायतों के माध्यम से लोग शामिल हो रहे हैं इसलिए आपको भी इसका धन्यवाद करना चाहिए था। इसी प्रकार से जो कन्यादान राशि बढ़ाई गई, उसके लिए भी आपको धन्यवाद करना चाहिए था। गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग रह रहे हैं, उनको मकान बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, उसका भी धन्यवाद करना चाहिए था ।

अध्यक्ष महोदय, यदि शिक्षा की बात की जाए तो मेरे अपने ही विधान सभा क्षेत्र में 11 मिडिल स्कूल, हाई स्कूल हुए और तीन गवर्नमैंट सीनियर सैकंडरी स्कूल बने। इन स्कूलों में साईंस और कॉमर्स के सब्जैक्ट भी हमने दिए ताकि लोगों को सुविधानुसार पढ़ाई करने

का मौका मिले। ये सारी बातें हुई हैं। साईंस ब्लॉक दिए। दियोठसिद्ध मंदिर में 10 करोड़ रु0 की लागत से लंगर हॉल का काम चला हुआ है। हमारी भोटा के अंदर एक छोटी नगर पंचायत है उसमें 6 करोड़ की लागत से पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। 10 करोड़ की लागत से सीवरेज़ की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वहां पर उसकी योजना का आरम्भ होने वाला है। इसी प्रकार से विधान सभा क्षेत्र बड़सर के अंदर जितनी भी सड़कों पर पानी जमा रहता था, सड़कों पर तारकोल नहीं टिकता था, 10 करोड़ की लागत से वहां इंटरब्लॉक टाईलिंग सिस्टम से उन सड़कों को पक्का किया जाएगा, क्या यह छोटी बात है? इसी प्रकार से हमारी ऊखली से ले कर बिझड़ी तक जो सड़क है, 11-12 किलोमीटर का जो एक स्पैन है, उसको 6 करोड़ रु0 की लागत से ठीक किया जा रहा है। दंभोटा से दखोड़ा तक सड़क का कार्य 5 करोड़ रु0 की लागत से पूरा किया जा रहा है।

परिवहन व्यवस्था की जहां तक बात है, हमारे अपने बड़सर विधान सभा क्षेत्र में पूर्व सरकार के समय में जो पांच बसें एच.आर.टी.सी. की चलती थी, वे बन्द कर दी गई

08.03.2017/1435/केएस/एजी/3

थी। उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे होंगें लेकिन इस वर्ष हमने उन पांच बसों के अतिरिक्त 14 नई बसें और चलाई है। जो बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंदर से गुजरती है और लोगों को उसका लाभ हुआ है। आज हर क्षेत्र में पूरा समग्र विकास हुआ है और उसका पूरे का पूरा श्रेय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी को जाता है। आने वाले समय में जिस प्रकार से सभी ने कहा है, हम केवल मात्र कांग्रेस के विधायक होने के नाते यह बात नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की जनता इस बात को कह रही है। चाहे वह चौराहे की बात हो, गली-कूचों की बात हो, हर जगह इस बात को कहा जा रहा है कि इस बार मिशन रिपीट होगा।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

8.3.2017/1440/av/ag/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री इन्द्र दत्त लखनपाल)---------- जारी

और कांग्रेस पार्टी प्रदेश में माननीय वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनायेगी।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल।

8.3.2017/1440/av/ag/2

श्रीमती सरवीन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक सेकेंड, मैं कुछ कहना चाहती हूं।

Speaker: Madam (Smt. Sarveen Chaudhary), there is no clarification in-between. Everybody is speaking. You also spoke.

श्रीमती सरवीन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप किस चीज़ के ऊपर बोलना चाह रही है?

श्रीमती सरवीन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाह रही थी कि मैंने एक मुहावरा कहा था उसको आपने ऐक्सपंज किया है या नहीं? यह मुहावरा तो किताबों में लिखा हुआ है और किताबों से तो इस मुहावरे को कोई मिटा ही नहीं सकता। इसको तो हम इस सदन में दस बार भी बोल सकते हैं। यह किताबों में लिखी हुई बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस के गधे और बी0जे0पी0 के गधे में फर्क हो जाए। यह तो केवल गधे के ऊपर बात चली और अगर ऐक्सपंज करना है तो पिछले दिन से ही ऐक्सपंज कर दीजिए। आशा जी ने जिस तरह से बात उठाई थी तब से लेकर ऐक्सपंज कर दें। उनका गधा तो पेपर और मीडिया में; सब जगह आ गया और हमने अगर कोई मुहावरा बोला तो वह ऐक्सपंज कैसे हो सकता है? यह तो मुहावरा है और किताबों में लिखा है इसलिए हमने अगर कुछ कहा तो वह ऐक्सपंज नहीं होना चाहिए, मेरा आपसे यह आग्रह है। हम नहीं तो बजट स्पीच में

बोल देंगे, हमें फिर मौका मिल जायेगा। यह एक लोकोक्ति है, मैंने कोई आउट ऑफ सिलैबस नहीं बोला और मैंने यहां पर किसी का नाम भी नहीं लिया। मेरा आपसे केवल इतना आग्रह था।

दूसरा, मैं यह कहना चाहती हूं कि यहां पर सत्र चल रहा है और आज महिला दिवस के ऊपर प्रदेश की सब महिलाओं को बधाई दी जा रही है। आज महिला दिवस मनाया जा रहा है। मैं इस सदन में यह बात रखना चाहती हूं कि इस सदन में केवल तीन महिलाएं हैं मगर उनको महिला दिवस पर नहीं बुलाया गया जहां प्रदेश का महिला दिवस मनाया गया है।

8.3.2017/1440/av/ag/3

में बुलाना चाहिए था। वहां पुरुष थोड़े ही न जायेंगे या वहां पर पुरुषों को कोई साड़ी थोड़े ही भेंट करेगा कि महिला दिवस पर पहन कर आओ। इस सदन में महिलाएं हैं। जब यहां पर महिलाएं हैं तो हमें वहां महिला दिवस के ऊपर बुलाना चाहिए था। अगर प्रदेश की इस विधान सभा की सदस्य महिलाओं को ही यह सम्मान नहीं दिया जा रहा है तो यह सरकार इस प्रदेश की महिलाओं के लिए कहां तक संवेदनशील है? मैं यही कहना चाहती थी और यह जानना चाहती थी कि मेरे द्वारा कही गई लोकोक्ति ऐक्सपंज की गई है या नहीं? धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैं आपको सदन की ओर से और अपनी ओर से महिला दिवस की बधाई देता हूं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कई मुहावरे ऐसे हैं जो कि सदन के अंदर फिट नहीं होते इसलिए मैंने उसको ऐक्सपंज किया है। (Interruption) No, no. There is no argument for this. I have taken a decision. You are challenging my decision. (Interruption) You sit down then. I won't allow you. (Interruption) No discussion on this. Not to be recorded. There is no discussion. (Interruption) That means if I speak something, every word will be discussed everywhere. Where is a rule? I have taken a decision. You should be quiet. This is my final decision.

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बहन श्रीमती सरवीन चौधरी जी ने कहा कि आज महिला दिवस के समारोह में इनको नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं बुलाया; हम दोनों यहीं बैठी हैं। हमें यहां बैठे सारे लोग तो विश कर रहे हैं। आपको नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया और अध्यक्ष महोदय, आपके थ्रू हम दोनों यह प्रोटैस्ट लॉंच करते हैं कि हम दोनों को बुलाना चाहिए था।

जय राम ठाकुर श्री वर्मा द्वारा जारी

08/03/2017/1445/टी0सी0वी0/ए0एस0/1

श्री जय राम ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया गया है और जिस पर चर्चा हो रही है, मैं भी अपने आपको इसमें शामिल करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज "महिला दिवस" है, मैं भी तमाम महिलाओं को बधाई देता हूं। यहां इस माननीय सदन में दो महिला माननीय सदस्या के माध्यम से जो उद्गार रोष के (पीड़ा) वयक्त किये गये हैं, पूरा सदन इनके साथ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। यदि आज के दिन कार्यक्रम ही महिला दिवस के रूप में मनाये और इस सदन की महिलाओं को उसमें नियमंत्रण न हो, तो सचमुच में ये पीड़ा का विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां पर पढ़ा, उस पर यह चर्चा लगभग समापन की ओर बढ़ रही है। इस माननीय सदन के बहुत-सारे सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है। इस चर्चा के दौरान ऐसे जानवर पर भी चर्चा हो गई, जिसका सहज़ रूप में ज़िक्र नहीं किया जाता है। लेकिन आपने उस पर रूलिंग दी और उसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं हैं। परन्तु एक तरफ से उसी शब्द का ज़िक्र होता है,दूसरी तरफ से भी उसी शब्द का ज़िक्र होता है, एक तरफ का निकाल दिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ का नहीं निकाला जाता है। मुझे लगता है कि यह संदर्भ ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो यहां पर चर्चा के माध्यम से बात सुनी, उसमें जुगाड़ से बनी हुई सरकार, जुगाड़ से चल रही है और चार वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया। यह हम नहीं कह रहे हैं, इस सरकार के मुख्य मंत्री स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि मैं जुगाड़ से सरकार को चलाने का प्रबंध किये जा रहा हूं। इसका

अर्थ वे भी और हम भी अच्छी तरह से समझते है, लेकिन एक बात को लेकर हमारे मित्र दुविधा में तो अवश्य हैं और वे सामने बैठें हैं। सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ये बज़ट सत्र वर्तमान सरकार का अंतिम बज़ट सत्र है और स्वाभाविक रूप से काम हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद और कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए कहना पड़ रहा है। सबसे पहले तो यह बात समझने की आवश्यकता है कि विकास का नज़रिया हम सब लोगों का होना क्या चाहिए? आज माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में नहीं बैठे हुए हैं और हम चाहते थे कि यदि यहां होते तो हम भी कुछ बात उनसे करते। प्रश्न पैदा होता है कि मात्र फ़ट्टे लगाकर ही उसको विकास का नज़रिया माना जाये। जिन चीजों को लेकर कुछ मांग भी बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन उन चीजों को लेकर राजनैतिक दृष्टि से कोई

08/03/2017/1445/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

बात कह दी जाती है। जब यहां पर राजधानी की जिक्र आ रहा था, मैं समझता हूं कि शुरूआत यही से करनी चाहिए। हम अभी तक नहीं समझ पाये कि दूसरी राजधानी का अभिप्राय क्या है? मैं वर्षों तक संगठन का काम करने के लिए जम्मू-कश्मीर में जाता रहा हूं, वहां पर दरबार मूव होता है। वहां पर 6 महीने के राजधानी श्रीनगर में रहती है और 6 महीने के लिए जम्मू में आती है। उसकी वज़ह है कि बनिहाल टनल के बाद सर्दी के मौसम में रास्ता बन्द हो जाता था। उसका बड़ा कारण वह था।

श्रीमती एन0एस0 .....द्वारा जारी।

08/03/17/1450/ns/as/1

श्री जय राम ठाकुर-----जारी

लेकिन यहां पर मुझे नहीं लगता कि धर्मशाला और शिमला के बीच कोई ऐसी बर्फवारी होती होगी जिसके कारण हमारा रास्ता बंद हो जाता हो। अब हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर हमारे साथी मित्र सामने बैठे हैं और मुझे लगता है कि वे भी समझ रहे हैं वे हां-हां कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है? क्या

यह राजधानी छः महीने के लिए शिमला और छः महीने के लिए धर्मशाला होगी। इसका क्या अभिप्राय है? या फिर इसका अभिप्राय इस प्रकार से लेना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश 68 विधान सभा क्षेत्रों का एक छोटा-सा प्रदेश है, जिसकी एक विधान सभा शिमला में थी और एक विधान सभा धर्मशाला में कर दी गई है। अब धर्मशाला की विधान सभा बनाने के बाद 365 दिनों में से 5 दिनों के लिए खोली जाती है और 360 दिन वह बंद रहती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या धर्मशाला की राजधानी भी पांच दिनों के लिए होगी? मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को ले करके न खुद समझ पा रहे हैं और न ही कुछ समझाने की परिस्थिति बना पा रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शिमला, धर्मशाला जो क्षेत्र की बातें होती हैं और यहां पर यह मामला बहुत उलझा भी है लेकिन एक जगह इनके बीच में भी पड़ती है जिसको मण्डी के नाम से जाना जाता है। जिसका कभी ज़िक्र ही नहीं आता है। मुझे लगता है कि कांगड़ा के बाद दूसरा बड़ा जिला मण्डी है और मण्डी केंद्र में पड़ता है। माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में वे आए हैं तो सबसे पहले मण्डी लोक सभा क्षेत्र से उन्होंने शुरूआत की है। मुख्य मंत्री जी ने लोकसभा के सांसद के रूप में मण्डी (महासू) से शुरूआत की थी। सांसद के रूप में पांच बार मण्डी से प्रतिनिधित्व किया है और उसके बाद उनकी पत्नी सांसद रही हैं। लेकिन फिर भी मण्डी का ज़िक्र नहीं आ रहा है। हमसे लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह राजधानी और भी मिल सकती है? अगर मिल सकती है तो मण्डी के लिए भी मांग लो। कहीं ऐसी परिस्थिति न बन जाए कि हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और 12 जिलों में राजधानी हो जाए। किसी बात का अर्थ मैं मानता हूं कि अनुभव के आधार पर हम इनकी इज्ज़त और सम्मान करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी इनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि यह जो कर रहे हैं क्या वह व्यावहारिक है? जो कर रहे हैं वह कहीं परिहास का विषय तो नहीं बन रहा है। हमें लग रहा है कि यह परिहास का विषय बन रहा है तो इनको भी इस बारे में सोचना चाहिए जो छठी बार मुख्य मंत्री बने हैं और सातवीं

08/03/17/1450/ns/as/2

बार मुख्य मंत्री बनने की बातें कह रहे हैं। उनको भी इस बात को सोचना चाहिए कि कहीं यह परिहास का विषय ही न बन जाए। मुझे नहीं पता कि विकास का नज़रिया इनकी नज़र में क्या है? अध्यक्ष महोदय, नज़र का तो इलाज़ किया जा सकता है लेकिन नज़रिये का कोई इलाज़ या आप्रेशन नहीं होता है। इनका नज़रिया ऐसा है कि ज़मीन पर कुछ नहीं

करना और यहां पर सभी साथी कह रहे हैं कि हमें स्कूल, कॉलेज, तहसील और उप-तहसीलें मिली। हम भी सुन रहे हैं कि जहां भी मुख्य मंत्री महोदय जा रहे हैं जो भी डिमांड की जा रही है वह दी जा रही है। खासतौर पर चुनाव का वर्ष आता है तो यह परिस्थितियां ओर भी ज्यादा तेज़ गति से बढ़ती हैं। इसकी वजह यही है कि सरकार बनाने का जुगाड़ करना है। यह जुगाड़ के बजाए ओर कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, क्या यह सत्य नहीं है? जो संस्थान खुले हैं वे बंद होने के कगार पर हैं। क्योंकि वहां पर आपकी स्टॉफिंग इस वजह से नहीं हो पा रही है कि नये संस्थान पर अट्टा-पट्टा लगा करके आप लोग आ रहे हैं उस संस्थान को चलाने के लिए वहीं से आपको अध्यापक, लैक्चर्र और अन्य स्टॉफ भेजना पड़ रहा है। इसके कारण चले हुए संस्थान बंद होने के कगार पर हैं। इसके बावजूद भी अगर यह मानते हैं कि हमारा विकास का नज़रिया यह है तो मैं इनको बधाई देता हूं। हमारे कुछ मित्र इस खुशफहमी में हैं कि आने वाले समय में हमारे लिए उससे कुछ निकल आएगा तो मैं आपको बता दूं कि उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। इसकी वजह यह है कि यह इसको पहली बार नहीं कर रहे हैं, यह आपने पिछली बार भी किया था जब वर्ष 2003 से 2007 तक सत्ता में थे उस वक्त भी यही दौर चला हुआ था। लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। जो अतीत से सिखता नहीं है उसको जिन्दगी में कोई दूसरा आदमी नहीं सिखा सकता है। इनको स्वीकार करना चाहिए कि वर्ष 2007 के दौर में भी यही किया गया था लेकिन अध्यक्ष महोदय वह काम नहीं आया। वर्ष 2007 में जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध बहुमत के साथ सत्ता में आई।

श्री आर0के0एस0---जारी।

08/03/2017/1455/RKS/DC/1

श्री जय राम ठाकुर... जारी

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्रों को कहना चाहता हूं कि पूरा देश 'कांग्रेस मुक्त' हिन्दुस्तान हो गया है, जो कि एक हकीकत है। पड़ोसी राज्य हरियाणा में जो हमारी पार्टी के कैंडिडेट होते थे उनकी ज़मानत जब्त हो जाती थी। लेकिन आज हरियाणा राज्य में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार है। जिस असाम राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पास विधान सभा चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट पूरे नहीं हो पाते थे वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी

की विशुद्ध सरकार चल रही है। जिस जम्मू-कश्मीर में अधिकांश जगह हमारे प्रत्याशी खड़े नहीं होते थे, वहां आज भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन के साथ सरकार चल रही है।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार सत्ता में आ चुकी है। वर्ष 1990 के बाद यह परिस्थिति है कि एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। अगर बारी के हिसाब से देखा जाए तो अब हमारी बारी आती है। लेकिन हमारे मित्र फिर भी गलतफहमी में हैं। कुछ लोग यू.पी., पंजाब, उत्तराखंड का जिक्र कर रहे हैं। आज 8 तारीख है, 2 दिन शेष बचे हैं और नतीज़े आपके सामने आ जाएंगे। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दूसरे पेज़ में कहा गया है कि जितनी भी घोषणाएं हैं वह पूरी कर दी गई है। इस बात का मेरे सभी मित्रों ने जिक्र किया। मैं बहुत लम्बी बात में नहीं जाना चाहता हूं। घोषण पत्र के माध्यम से आपने कहा कि हमने सारे वायदे पूरे कर दिए। क्या यह सत्य नहीं है कि आपने घोषणा पत्र में जिक्र किया था कि हम हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को भत्ता देंगे? यह एकमात्र मुद्दा था जो कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए संजीवनी साबित हुआ। क्योंकि जो बेरोजगार होता है, वह बड़े कठिन दौर से गुजर रहा होता है। जब नौकरी नहीं मिलती है तो वह भटक रहा होता है। उसे उम्मीद होती है कि यदि नौकरी नहीं मिलेगी तो कम-से-कम मेरा खर्चा बेरोजगारी भत्ते से चलता रहेगा। बेरोजगारों को यह कहा गया कि आप अपना खाता खोल दो और आपके खाते में हर महीने एक हजार रुपये आता रहेगा। चुनाव के दिनों में कांग्रेस के नेता घर-घर में

08/03/2017/1455/RKS/DC/2

घूमने लगे और लोगों से पूछने लगे कि आपके घर में कितने बेरोजगार बच्चे हैं। किसी ने कहा कि दो बेरोजगार बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि दो खाते खोल दो। उनके खाते में पैसे आ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, चार वर्ष बीत गए उस बेरोजगारी भत्ते का जिक्र किस प्रकार से हुआ है। मुख्य मंत्री कहते हैं कि यह हमने नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कहता है कि हमने कहा है और हमारे घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र है। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि

अनुभवहीन लोगों ने घोषणा पत्र बनाया है। लेकिन जब घोषणा पत्र जारी किया गया था तो वे स्वयं पार्टी के अध्यक्ष थे और उनका फोटो भी इस घोषणा पत्र में शामिल है। इसके बावजूद मुकर जाना कहां तक ठीक है। कांग्रेस पार्टी में एक विचित्र परिस्थिति है। सत्ता वाले संगठन को नहीं मानते और संगठन वाले सत्ता को नहीं मानते हैं। इस तरह का तालमेल इनकी पार्टी में स्पष्ट दिखता है तो ये प्रदेश को क्या दे पाएंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही पिछड़े विधान सभा क्षेत्र से संबंधित हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी उस विधान सभा क्षेत्र में भी दौरा करते हैं और वहां पर खूब घोषणाएं की जाती हैं। अपनी विधान सभा क्षेत्र का मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी जब मेरे विधान सभा क्षेत्र में गए तो वहां पर जिक्र हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर रहा है और वह कोई काम नहीं कर रहा है।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

08.03.2017/1500/SLS-AG-1

श्री जय राम ठाकुर...जारी

मुख्य मंत्री जी, आप आ गए हैं, मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूं। जिस दिन आपकी जनसभा में इस बात का ज़िक्र हुआ, आपके माध्यम से आपके साथियों ने करवाया; आप कहना चाहते थे या नहीं कहना चाहते थे, यह मुझे मालुम नहीं। लेकिन आपके साथियों ने कहा कि यह कहना है। जिस लम्बा थाच डिग्री कॉलेज का आप उद्घाटन करके गए, जो सिराज में है, वह लगभग 6.50 करोड़ रुपये की लागत से पूरा हुआ है। उसमें 5.00 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय दी गई थी। अध्यक्ष महोदय, आज आई.डी. धीमान जी यहां पर नहीं हैं। उनको साथ ले जाकर हमने उस भवन का शिलान्यास किया था। जब भवन बनकर तैयार हुआ तो उद्घाटन करने के लिए मुख्य मंत्री जी आ गए।

ब्लॉक का भी वहां पर उद्घाटन किया गया। माननीय धूमल जी ने उस भवन का शिलान्यास किया और मैं मंत्री था। डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से भवन बनकर तैयार हुआ और उद्घाटन करने के लिए मुख्य मंत्री जी आए। उसके बावजूद भी कहा गया कि विकास नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दावे के साथ मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मेरे सिराज विधान सभा क्षेत्र में एक भी ऐसा भवन नहीं मिलेगा जिसके लिए कांग्रेस के 4 सालों के कार्यकाल में बजट का प्रावधान किया गया हो, उसका शिलान्यास किया गया हो या भवन का काम शुरू किया गया हो या भवन पूरा हुआ हो; ऐसे भवन को मैं भी देखना चाहता हूं। आज जितने भी विकास कार्य उस विधान सभा क्षेत्र में हो रहे हैं, उनके शिलान्यास उस वक्त हुए थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हां, एक काम ज़रूर करने की कोशिश हुई है। शिलान्यास हुआ था लेकिन उसके बाद फिर से शिलान्यास करने की कोशिश होती है। बाली चौकी में सीनियर सेकैंडरी स्कूल के भवन का शिलान्यास मैंने 27 मई, 2012 को ग्रामीण विकास मंत्री के नाते किया था। लेकिन इनके एक बड़े नजदीकी आदमी हैं जिसको ये मना नहीं कर सकते। पता नहीं क्या वजह है जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई। कहता है कि इसका शिलान्यास दोबारा से होगा। और आप दोबारा से शिलान्यास करने के लिए चले गए। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि शिलान्यास हो चुका है, लेकिन कहा कि कोई बात नहीं, अभी काम शुरू होना है क्योंकि उसका टैंडर अभी हुआ है। SMC के प्रधान और पूरी कमेटी ने प्रिंसिपल को लिखकर दिया, पुलिस थाने में दिया, तहसीलदार को दिया कि इस भवन का शिलान्यास हो चुका है और

08.03.2017/1500/SLS-AG-2

दोबारा से शिलान्यास करने की आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद कहा गया कि इसका शिलान्यास किया जाए और पट्टिका लगा दी गई। वहां पर स्कूल के बच्चे, उनके अभिभावक खड़े हुए कि यह मज़ाक सहन नहीं किया जा सकता और अभिभावकों द्वारा उसको तोड़ दिया गया। एफ.आई.आर. पुलिस ने दर्ज़ करके रखी है और उस पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं, ऐसे बीसों शिलान्यास और उद्घाटन मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुए हैं। मेरी एक सड़क जो छतरी से जंजैहली के लिए आती है, मगरुगा-छतरी सड़क, उसका आज से 6 साल पहले काम शुरू हो चुका था। 60 प्रतिशत काम उसका पूरा हो चुका है, लेकिन एक नेता इनके चले जाते हैं और कहते हैं कि इसका भूमि पूजन

दोबारा से किया जाए। वह भूमि पूजन के लिए वहां खड़ा हो जाता है और कहता है कि भूमि पूजन की रसम पूरी की जाए और धाम का इंतजाम किया जाए। फिर धाम का इंतजाम होता है और भूमि पूजन की रसम होती है। ऐसा पूरे हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। मैं इसका ज़िक्र इसलिए कर रहा हूं कि यहां दो बड़े नेता शिलान्यास और पट्टिका का ज़िक्र कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी माननीय सदन में कहा है कि कम-से-कम 8 जगह मेरी शिलान्यास की पट्टिकाओं को मेरे विधान सभा क्षेत्र में तोड़ा गया है, लेकिन न तो उसमें एफ.आई.आर दर्ज़ है और न ही विभागों द्वारा उनको रैस्टोर किया गया है।

Speaker: Please wind up.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं कनक्लूड कर रहा हूं। अभी हमारे लखनपाल जी कई बातों का ज़िक्र कर रहे थे। पंचायती राज विभाग से संबंधित कुछ बातों का भी ज़िक्र कर रहे थे। अगर मैं ज़िक्र किए बिना रहूं तो मेरे मित्र अनिल शर्मा जी नाराज हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ODF का बहुत ज्यादा श्रेय लेने की बात हो रही है। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि सिक्कम के बाद हिमाचल प्रदेश ODF घोषित होने वाला था। इसकी सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई थीं। उस वक्त मैं स्वयं जाकर केंद्र में UPA सरकार के मंत्री को मिला था। मैं सैक्रेटरी, भारत सरकार को भी मिला था। उन्होंने हमें इस बात की बधाई भी दी।

जारी ... श्री गर्ग जी

08/03/2017/1505/RG/AG/1

श्री जय राम ठाकुर----क्रमागत

उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि यह जल्दी हो जाए, लेकिन इसका श्रेय उस समय की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां थी, उसको न मिल पाए इस कारण से इसको डिले किया गया। लेकिन मैं इस समय के देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और केन्द्र में वर्तमान सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इसका

नजरिया बदला। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं चाहे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है-(घण्टी)-- उसके बावजूद राज्य को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित करने के लिए केन्द्र के संबंधित विभाग के मंत्री श्री तोमर जी तथा माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा जी यहां उपस्थित हुए। लेकिन यह प्रयास कब से चल रहा था? यह बात भी सोचने की है। यह ऐसे ही नहीं हुआ और वर्तमान सरकार ने इसमें कुछ विशेष नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहां हम किसी बात का जिक्र कर देते हैं या किसी छोटी बात का जिक्र कर देते हैं। यहां पर श्री रणधीर शर्मा जी ने कल जिक्र किया कि मण्डी में चोरी की 23 गाड़ियां पकड़ी गईं। वह कोई छोटा-मोटा गिरोह नहीं बहुत बड़ा गिरोह है। प्रदेश के अलावा बाहर भी उसकी तारें जुड़ी हुई हैं। उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन वहां जो रामलाल एक ए.एस.आई है उसका जिक्र हुआ और हमें जानकारी मिली कि उसको लाईन हाजिर कर दिया गया। यह तो बहुत चिन्ता का विषय है कि यदि हम यहां जिसका जिक्र करें, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। लेकिन जिस प्रकार से सारी चीजें की जा रही हैं उनको लेकर मुझे सोचने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष : कृपया अब समाप्त करिए। Please wind up otherwise I will stop you. अब बहुत समय हो गया। अभी और भी बोलने वाले हैं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे संस्थान खोले हैं मैं उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र यहां करना चाहूंगा और बहुत से मेरे चुनाव क्षेत्र में भी खुले हैं। उन सभी संस्थानों को संचालित करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता थी उनको नहीं किया जा रहा है। तीन पी.एच.सी. मेरे यहां खुलीं और तीनों में ताले लगे हैं। दो के उद्घाटन में इनके चहेते ने माननीय मुख्य मंत्री जी का फट्टा लगाया है, मुख्य मंत्री जी शिमला में थे और एक में स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं जाकर आए हैं। जहां तीन वर्षों से डॉक्टर होना चाहिए था वहां ताला लगा हुआ है। क्या इसको विकास कहते

08/03/2017/1505/RG/AG/2

हैं? मैं इस बात से अच्छी तरह से सहमत हूं कि वर्तमान सरकार सिर्फ फट्टा लगाकर अपने विकास को सीमित करना चाहती है। जमीन पर अगर काम करने की बात आएगी, तो ये

तमाम जिम्मेवारियां आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो उसके जिम्मे पड़ने वाली हैं। ---(घण्टी)---- अध्यक्ष महोदय, यहां कॉलेज की बात कर रहे थे। मेरे यहां एक कॉलेज है, तो मुख्य मंत्री जी चार वर्ष हो गए वहां 150 से अधिक बच्चों की संख्या नहीं बढ़ पाई। हर वर्ष बजट का प्रावधान पांच करोड़ होता है कि पांच करोड़ इस बार, पांच करोड़ इस बार। लेकिन पांच वर्ष बीतने के बावजूद एक ईंट वहां नहीं लग पाई।

Speaker: Not to be recorded now. (Interruption) No, no. Not at all. I have been asking you for the last ten minutes. (Interruption) Everybody is to speak, you see. You are not the sole representative of this House. There are so many who want to talk and the Hon'ble Chief Minister will reply after that. Let others also speak. (Interruption) No, no. Not at all. I don't agree with you.

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री दिल्ली जाने वाले थे इसलिए हमने छोड़ दिया था और 6 लोग बोलने वाले थे जिनमें से तीन लोगों ने छोड दिया है।

अध्यक्ष : मुझे यह बताइए कि हमने किसी को भी बोलने से रोका नहीं है। लेकिन समय की पाबन्दी तो होनी चाहिए। Somebody is speaking for 30-40 minutes. लेकिन समय की कोई पाबन्दी ही नहीं है। You should keep up with the limit of the time.

श्री सुरेश भारद्वाज : ये बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब इनको समाप्त तो करने दें।

अध्यक्ष : मैं इनको कन्क्लूड करने के लिए पिछले दस मिनट से कह रहा था।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन "not to be recorded" यह बहुत ही डिसग्रेसफुल लगता है। हर समय इस शब्द को आप बार-बार ले आते हैं।

Speaker: Is it not discussed when I say something and you don't agree.

08/03/2017/1505/RG/AG/3

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा था और हम आपके प्रति आदर करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमने कुछ भी नहीं देखा है। जब हम अपनी स्पीच समाप्त करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष : किस माननीय सदस्य को हमने समय नहीं दिया? There should be limit of the time. जितनी देर में आप बात कर रहे हैं उतनी देर में तो अपनी स्पीच आप समाप्त कर देते।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन समाप्त करने के लिए थोड़ी बात तो कहनी पड़ती है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और मैंने समय थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, लेकिन जो यहां राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिस पर चल रही चर्चा में आपने मुझे भाग लेने का मौका दिया, तो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपका धन्यवाद।

एम.एस. द्वारा जारी

08/03/2017/1510/MS/AG/1

अध्यक्षः अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री चर्चा में भाग लेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, विपक्ष के दो सदस्यों ने मुझे भ्रष्ट का दर्ज़ा दिया है और उन्होंने कहा है कि जो एल0ई0डी0 बल्बों की डिस्ट्रीब्यूशन हुई, उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार का हाथ था। मैं उस पत्र को पढ़ रहा हूं जो मैंने 12 जनवरी, 2017 को केन्द्रीय मंत्री को लिखा था।

Himachal Pradesh BJP Unit has submitted a chargesheet against the Government of Himachal Pradesh to the Hon'ble Governor of Himachal Pradesh on 24.12.2016 alleging therein a scam in the procurement and distribution of LED bulbs in the State saying that poor quality Chinese LED lamps were procured and distributed. It is imperative to put things in right perspective by bringing following to your notice.

The Government of India launched the National Programme for LED Distribution "Domestic Energy Efficiency Lightening Programme", on 5th January, 2015. Various States including Himachal Pradesh adopted the Scheme with the sole objective of saving energy, replacing 60-Watt conventional bulbs with 7-Watt LED lamps. M/s Energy Efficiency Services Limited (EESL), a Government of India undertaking is the implementing agency all across India and accordingly a MoU was signed by HPSEBL, the State owned DISCOM after getting the approval of Himachal Pradesh State Electricity Regulatory Commission with M/s EESL.

It is worth mentioning here that the responsibility for the procurement and distribution of the LEDs under the Scheme DELP is with M/s Energy Efficiency Services Limited (EESL). State Government and HPSEBL are in no way associated with the procurement process and of the LED bulbs. HPSEBL is the

08/03/2017/1510/MS/AG/2

only facilitating M/s Energy Efficiency Services Limited in distribution of LED bulbs, that too when the consumer opts for EMI mode of payment. The role of HPSEBL is only to ensure recovery of instalments via energy bills. These bulbs being distributed are from Indian companies, namely, Bajaj Electrical, Philips, Surya, Osram, Orient etc. and not from the Chinese companies as is being alleged.

सर, ये दो-चार लाइनें और हैं। मैं थोड़ा इस पर भी बोलूंगा जैसे पार्टी के ऊपर बात आ रही है कि आप जा रहे हैं और आप दुबारा कभी यहां वापिस आने का सपना नहीं देख सकते। अध्यक्ष जी, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री को आज से तीन साल पहले दुनिया हिलती हुई नज़र आई और इतने भारी बहुमत से उनको जिताया कि दुनिया में त्राहि-त्राहि मच गई तथा जो उन्होंने वायदे किए कि मैं आपको यह भी दूंगा, वह भी दूंगा।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

08.03.2017/1515/जेके/एएस/1

बहुउद्दशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः--------**जारी**-----

मेरा पोता 10 साल का है। उस वक्त वह 7 साल का था। हम प्यार से उसको गुगू कह कर बुलाते थे । मैंने उसको कहा कि गुगू तुमको 15 लाख मिलने वाला है। कहने लगा बाबा 15 लाख? मैंने कहा, हां, 15 लाख। वह कहने लगा कौन देगा? मैंने कहा मोदी जी देंगे। इलैक्शन हो गए। वह बेचारा साल भर मुझे फोन करता रहा। बाबा जी मेरे पैसे आए? मैंने कहा कि बाबा जी के ही नहीं आए तो तेरे कैसे आएंगे? वो आज भी मुझे फोन करता है। अब वह पैसे लेने के लिए नहीं करता बल्कि मेरा फूल बनाता है कि बाबा जी पैसे आए। मैंने एक बात की थी, हम जब पहली बार यहां पर एम0एल0ए0 बन कर आए तो मैं, राणा हरबंस सिंह और एक हमारे साथ कोई और था हम सभी माल रोड़ से जा रहे थे। आगे हमें वाई0एस0 परमार जी मिले उनके साथ बुशैहरी जी बात कर रहे थे। हमने जा करके उनके पाँव को हाथ लगाया, हमने कहा कि हम एम0एल0ए0 हैं तो उन्होंने एक बात कही कि अरे, भाई नौज़वानों आपकी उम्र से लगता है कि आप लोग कांग्रेस के नहीं हो। हम उस वक्त 30-32 या 34-34 साल के थे। हमने कहा सर, हम जनता पार्टी से हैं। कहने लगे आप लोग अच्छे समय में आ गए परन्तु एक बात का ख्याल रखना this is the honorary job of the highest honour. 2 अगर पैसा कमाना है तो कोई बिजनैस करो, कहीं और चले जाओ। मुझे वाई0एस0 परमार के वे शब्द याद आ गए थे कि आपने 50 लाख जुर्माना भरा

और फिर दोबारा अपने क्रशर को चलाया। अगर हम राजनीतिज्ञ ही इसमें लग जाएंगे तो बाकी गरीब आदमी को तो धंधा करने का टाईम ही नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे काम तो कोई अफसर नहीं रोकेगा, दूसरे को परमिशन नहीं देगा। मैं इसलिए कह रहा था। मैं कोई और बात के लिए नहीं कह रहा था। हमारी मनरेगा स्कीम का बड़ा मज़ाक उड़ाया। अध्यक्ष महोदय, यह बात कहां जाती है? कोई 24-26-28 साल की लड़की है, उसके दो बच्चे हैं और विधवा है। उसके पास जमीन जायदाद नहीं है। वह अपने बच्चों को कैसे पालती होगी? इस स्कीम से उसके गांव में 20 हजार रु0 पैदा करने का हक दिया। मैं अपने घर से निकला सड़क और जो बाड़ होता है उसके बीच में कुछ घास वाली जमीन होती है तो वहां पर कुछ लड़कियां घास काट रही थी। मैंने कहा कि बेटा यह स्कीम कैसी है?

08.03.2017/1515/जेके/एएस/2

कहने लगी अंकल जी क्या माड़ी है? पहला साथी ही घरयाला ते मांगी के पैसे लेने पौंदे थे, आज 15-15, 20-20 हजार रूपया साडा बैंके च जमा है, कने असां कमां दिया भी है। एक शायद मेरा पास्ट जानती होंगी, जिस तरह से उसने बात की। कहने लगी कि साडे घरेआले भी लगे हुण। मैंने कहा कि यह तो और भी खरी गल है। पर साडी दिहाड़ी मिलती 120 रूपये, उस वक्त दिहाड़ी 120 रूपये थी कने साडे घरेआले जो मिलती है 60 रूपए। मैंने कहा कि यह कैसे हो सकता है? उसने कहा कि मिलती तो उनको भी 120 रूपये है पर वह 60 रूपये की शराब पी जाता है। उनका कहने का मतलब यह था कि इस स्कीम के तहत हम अपने घरों को चला रही हैं और हमारे घरवाले तो कुछ भी नहीं करने वाले हैं। काले धन की बात मैं पहले ही कर चुका हूं। ये नोट बन्दी की बात चली हुई है। इसमें टी0वी0 के ऊपर एक शो आ रहा था।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

08.03.2017/1520/SS-AS/1

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री क्रमागतः

तो एक लड़के ने बी0जे0पी0 के रिप्रैजैंटेटिव को पूछा कि सर यह जितना भी पैसा पकड़ा जा रहा है यह सारे-का-सारा बी0जे0पी0 का है इसका क्या मतलब है? देखना ढीठपन, यह बी0जे0पी0 की ईमानदारी बताता है। मैं बड़ा हैरान-परेशान कि यह क्या ईमानदारी है? क्योंकि हमने उनको नहीं बताया कि अपना पैसा छुपा लो, यह हमारी ईमानदारी है। अध्यक्ष जी, जेहड़ी पूरी-दी-पूरी पार्टी बनारस बैठियो है पिछले पंजां-छैंयां दिना दी इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, अब इनके पास क्या बचा हुआ है? ये तो इनको राज्यपाल महोदय का अभिभाषण डिस्कशन के लिए मिल गया। इसलिए मैं यहां पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा उसके एक-एक शब्द का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

08.03.2017/1520/SS-AS/2

अध्यक्षः अब श्री बी0के0 चौहान जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बी0के0 चौहानः अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने के लिए समय देने हेतु आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने यहां पर पढ़ा, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा। तीन-चार प्वाइंटस पर अपने विचार रखूंगा। सबसे पहले तो किसी प्रदेश के लिए उसके विकास के लिए कार्य करने की मंशा के साथ-साथ क्षेत्र की जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी लक्ष्य होता है। इसलिए जो प्रदेश की जनता है उसके लिए विकास के तीन क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं जोकि मैं मानता हूं। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा मूलभूत सुविधाएं, जिनमें सड़कें इत्यादि आती हैं। जहां तक पहले बिन्दु शिक्षा का सवाल है, मैंने कुछ दिन पहले ही एक प्रश्न एलीमैंटरी एजुकेशन के बारे में सरकार के विभाग से पूछा था।

उसमें पूछा था कि, How many Primary Schools in my Constituency are having less than 15 students? दूसरा था How many teachers are working in each school to teach these students? The third was what is the number of rooms available in each school to accommodate these students i.e. how much the accommodation in the school? तो उसका जवाब जो आया वह बड़ा गौर करने योग्य है

जारी श्रीमती के0एस0

08.03.2017/1525/केएस/एएस/1

श्री बी0के0 चौहान जारी----

पहले जो प्राईमरी स्कूलों में चम्बा में ऐनरोल्मैंट है, उसको अलग-अलग पार्ट में दिया है। 72 बच्चे एनरोल्ड हैं और उनके लिए 13 कमरे हैं, स्कूलों की संख्या 8 हैं। टीचर सिर्फ एक स्कूल में दिखा रखा है जो लगभग टाऊन के पास ही है, उसमें एक एच.टी. है और दूसरा जे.बी.टी है। बाकी सभी स्कूलों में एक-एक टीचर है। दूसरे ग्रुप में 17 स्कूल हैं। उनमें भी 101 बच्चे पढ़ रहे हैं । तीसरे ग्रुप में 9 स्कूल है। ये दोनों मिलाकर बनते हैं 26 एक और 18 एक । इनके लिए 10 स्कूलों में दो टीचर हैं और 14 में एक-एक टीचर है। उसके बाद 7 स्कूल और हैं जिनमें टोटल स्ट्रैंथ बच्चों की 89 हैं इनके लिए 10 जे.बी.टी. टीचर हैं और तीन एच.टी. हैं। अध्यक्ष जी, अगर मैं सभी स्कूलों के बारे में कहूंगा तो समय लगेगा लेकिन मेरे पास पूरी डिटेल है कि ऐवरेज़ हर प्राईमरी स्कूल में एक टीचर है। अगर एवरेज़ निकाले तो इसकी टोटल स्ट्रैंथ पर एक टीचर प्रति स्कूल बैठता है। बड़ी दयनीय स्थिति है। चम्बा चुनाव क्षेत्र बहुत बड़ा है और टैरेन के हिसाब से भी डिफिकल्ट है। इसका मतलब यह है कि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं शायद उन्होंने भी निरीक्षण नहीं किया है और न वे कभी स्कूलों के निरीक्षण के लिए जाते होंगें क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं और अध्यापकों की संख्या इतनी कम है। किसी न किसी ने तो इसके बारे में सरकार को रिपोर्ट की होगी। अगर की होती तो

सरकार अवश्य जागती और न जितने बच्चे एक टीचर को पढ़ाने हैं, उस अनुपात में टीचर की भर्ती करती लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, चम्बा में। एलिमेंटरी ऐजुकेशन की दुर्दशा है। कोई काम नहीं हो रहा है।

अ0व0 द्वारा जारी----

8.3.2017/1530/av/ag/1

श्री बी0 के0 चौहान---------- जारी

मैं अमूमन अपने क्षेत्र के स्कूलों में जाता हूं और वहां कम-से-कम एक-चौथाई स्कूलों में अध्यापक होते ही नहीं है। इस तरह की अराजकता चम्बा को और भी पीछे ले जा रही है। एक तो चम्बा का टैरेन खराब है, दूरदराज के एरिया में जो स्कूल है उनमें तो टीचर महीने में एक बार ही हाजिरी लगाने जाते हैं और उसके बाद वहां स्कूल राम भरोसे रहते हैं। मुझे लगता है कि चम्बा में कोई भी विकास नहीं हो पायेगा। अगर चम्बा निर्वाचन क्षेत्र की अपकमिंग जनरेशन को शिक्षा से इस तरह से महरूम रखा जायेगा, वहां नाममात्र के टीचर बिठा दिए। इग्ज़ाम तो लोअर क्लासिज के वही लेते हैं जो वहां पर टीचर्स अप्वाईंटिड हैं। वे तो अपने सीनियर्ज को यह दिखाने के लिए सब बच्चों को पास ही कर देंगे कि हमने बच्चों से बहुत मेहनत करवाई है। प्राथमिक शिक्षा की जो स्थिति है मैं उसकी दूरदशा भी यहां पर बयां करना चाहता हूं। इस ओर जल्दी-से-जल्दी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं इस बारे में ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता। समय के अभाव में मैं इस बारे में बहुत कम वर्णन कर रहा हूं। मैं चाहता था कि आपको इसकी छोटी-छोटी समस्याओं से अवगत करवाऊं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक जगह ग्रुप ऑफ प्राइमरी स्कूल्स का टोटल किया है जिसमें कुल 280 छात्र हैं और उन स्कूलो में मेरे निरीक्षण के दौरान केवल 14 टीचर्स उपलब्ध हुए। ये 280 छात्र 18 स्कूलों में हैं, स्ट्रैंथ काफी है लेकिन टीचर कुल 14 है। इसी तरह से एक वैली में एक और 8-10 स्कूलों का ग्रुप है। उसमें भी 280 छात्र हैं और वहां पर 54 टीचर्स हैं। अब आप देख लीजिए टीचर्स का वितरण किस तरह से किया गया है। किसी भी डी0ई0ओ0 या शिक्षा विभाग के किसी और अधिकारी ने अपना माईंड अप्लाई किया ही नहीं है कि कितने छात्र पर एक टीचर होना चाहिए। वहां पर छात्रों के अनुपात के अनुसार टीचर्स की नियुक्ति की जानी चाहिए थी। इस तरह से हेफेजर्डली काम चल रहा है। यह डाटा विभाग ने ही दिया है। मैंने एक प्रश्न किया था उसके जवाब में मुझे यह डाटा उपलब्ध करवाया गया

8.3.2017/1530/av/ag/2

है और कुछ जिला अधिकारियों से जिनको मैं जानता हूं उनसे मैंने यह सूचना ली है। मैं ज्यादा न बोलता हुआ यही कहूंगा कि जो अधिकारीगण है खासकर के जो फील्ड में काम करते हैं उनको इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाए। अध्यापकों का जो वितरण है उसके लिए कोई अनुपात तय किया जाए या फिगर तय की जाए कि एक टीचर कितने बच्चों को ठीक तरह से पढ़ा सकता है। अब किसी स्कूल में तो 4-4, 5-5 टीचर है और किसी में एक है तथा किसी में एक भी नहीं है। यह एक बड़ी दयनीय स्थिति है। मैं समझता हूं कि मेरे यहां पर

श्री वर्मा द्वारा जारी

08/03/2017/1535/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

श्री बी0के0 चौहान ... जारी।

शिक्षा की बड़ी दयनीय स्थिति है। यहां सदन में जो मेरे सहयोगी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, ये भी शिक्षा विभाग की इस सिचुएशन ने अवगत होंगे। इनके क्षेत्रों में भी शिक्षा विभाग की स्थिति ऐसी ही होगी, क्योंकि चम्बा बहुत बड़ी कंस्टीचुएंसी है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि समय रहते एलीमेंटरी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया, तो हमारी आने वाली जनरेशन शिक्षा से महरूम रह जायेगी, क्योंकि किसी भी चीज का बेस यदि आधा-अधुरा होगा और उनका आधार यदि ठीक से पक्का नहीं किया जायेगा, तो आगे वे छात्र अच्छा नहीं कर पायेंगे। (घण्टी) अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। दूसरा, जो विषय मैंने लिया है, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के आधार पर उसके बारे में कह रहा हूं, वह हैल्थ है। शिक्षा विभाग की तरह स्वास्थ्य संस्थाओं की हालत भी लगभग वैसी ही है, जैसी स्कूलों की हैं। अस्पताल हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं है। रूरल एरिया को छोड़ दीजिए, लेकिन चम्बा के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनकी दशा भी दयनीय है। उसमें डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी हैं। मैंने जब इस संबंध में पूछा तो जवाब मिला कि कुल 78 पोस्टें चम्बा में विशेषज्ञों की हैं और उनमें से भी अभी तक कुछ खाली हैं। 78 में से केवल 18 पोस्टें भरी हुई हैं और 60 पोस्टें खाली हैं। ये पोस्टें काफी अर्से से नहीं भरी गई हैं। उनको भरने के लिए सी0एम0ओ0 ने लिखा है, लेकिन हैडक्वार्टर पर अभी तक ये सीटें नहीं भरी गई हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने चम्बा के लिए मेडिकल कॉलेज दिया है। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि आपके जो चम्बा के स्वास्थ्य संस्थानों का इंफ्रास्ट्रेक्चर है, वह चरमराया हुआ है, उसको ठीक करने की जरूरत है। इसके लिए कोई टीम भेज करके उसको ठीक करने की कृपा करें। उसके बाद विशेषज्ञ की जो पोस्टें खाली हैं, उनको भरा जाये, तो चम्बा पर आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्रीमती एन0एस0.... द्वारा जारी।

08/03/17/1540/ns/ag/1

श्री बी0के0चौहान-----जारी

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ एक अनुरोध माननीय मत्री जी से करना चाहूंगा कि चम्बा में अकोमोडेशन है। कल श्रीमती आशा जी ने भी आपको स्पष्ट किया था। लेकिन

दुःख की बात तो यह है कि आपने प्रिंसीपल छः महीने पहले भेज दिया हुआ है। वह वहां पर बैठ करके कोई काम नहीं कर रहा है। वहां पर अन्य स्टॉफ भी शीघ्र भेजा जाए। आपको उसके सहयोगी, सबोर्डिनेट स्टॉफ को शीघ्र अप्वाईंट करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि जब भी आप उसका उद्घाटन करेंगे या करवायेंगे तो उस वक्त कम-से-कम चम्बा के हैल्थ इन्फरास्ट्रक्चर, इंस्टीच्यूशन्ज़ की जो व्यवस्था है, उसमें सुधार हो और उस तरफ ध्यान दिया जाए। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा।

अध्यक्षः माननीय सदस्य प्लीज़ बाईंड अप कीजिए। बहुत देर हो गई। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब भी देना है। He has to reply. He will also take time.

Shri B.K. Chauhan: Just I will take five minutes more. अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इस सरकार ने सिर्फ स्वास्थ्य विभाग को छोड़ करके पूरे चम्बा जिला की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया है। मुख्य मंत्री महोदय हमारे रोडज़ की बड़ी दयनीय स्थिति है। आपको खुद सब कुछ ज्ञात ही है। अभी हाल ही के छः महीनों में कितने ऐक्सिडेंट और कैजुअलिटी हुई हैं और इसी को देखते हुए मैं पहले से ही ट्रॉमा सैंटर की डिमांड कर रहा था। इस बार मैंने फिर की है। स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने आश्वासन तो दिया है लेकिन आश्वासन, आश्वासन ही न रह जाए क्योंकि इससे पहले भी आप ऐसा एक बार कर चुके हैं कि चम्बा को हम प्रायोरिटी पर देंगे लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। इस बार मैं चाहूंगा कि ट्रॉमा सैंटर जल्दी-से-जल्दी बने। क्योंकि यह केवल रोड ऐक्सिडेंटस ही नहीं हैं जिसके लिए मैं बोल रहा हूं। इस बार तो बहुत सारे लोग और जो सैलानी आए थे उनकी भी मृत्यु हुई है। लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ते हुए बर्फ में एवालांच की चपेट में आ गए और एक साल के बाद उनकी

08/03/17/1540/ns/ag/2

डैड बॉडी निकाली गई। इस तरह से बहुत सारे हादसे इस बार हुए हैं। दो एक्सिडेंट तो जोत पर हुए हैं। हाल ही में जो पहला स्नोफॉल हुआ था, उसमें अमृतसर के 8 से 10 सैलानियों की मृत्यु हो गई थी। एक गाड़ी चम्बा की तरफ को आ रही थी वह भी खाई में

गिर गई थी उसमें एक-दो कैजुअलिटी हुई थी। इस तरह के हादसे बरसात और सर्दियों में भी होते रहते हैं और हमें ट्रॉमा सैंटर के लिए टांडा या शिमला जाना पड़ता है तथा तब तक घायल की मृत्यु हो जाती है। इसके लिए भी मैं आप से अनुरोध करूंगा।

Speaker: Please wind-up otherwise I will stop you. Kindly say whether you accept it or reject it.

श्री बी0के0चौहान : सर, ठीक है। मैं एक प्वाईंट और सामने रखना चाहूंगा।

Speaker: You don't want to listen to the Hon'ble Chief Minister's reply.

श्री बी0के0चौहान : पहले-पहले जो आएंगे उनको पूरा समय दिया गया और हमें पीछे इसलिए रखा गया है कि हम बोलें ही नहीं।

अध्यक्ष: मैंने आपको ज्यादा समय दिया है।

Shri B.K. Chauhan: Sir, do you want that I should not speak at all. लास्ट में जो बोले they should not be given time. What does it mean?

Speaker: You have spoken almost for 25 minutes. 25 minutes I have not given to anybody. You can see the record. Nobody has spoken for more than 25 minutes.

Shri B.K. Chauhan: Have you kept this limit of time for the people who have spoken before me at least?

श्री आर0के0एस0---जारी

08/03/2017/1545/RKS/AS/1

श्री बी0 के0 चौहान.... जारी

Speaker: They have spoken less than your time. You have taken the maximum time.

B.K.Chauhan: You are applying your rules only on those who come at the end.

Speaker: You can see the record. We have got the record.

B.K.Chauhan: Hon'ble Speaker, Sir, with due respect I can say that you are not doing justice with me.

Speaker: I will not allow you now. You please wind up.

B.K. Chauhan: You have given times to others more than one hour.

Speaker: I will not allow you on any topic now.

B.K.Chauhan: Sir, I have to bring one more point.

Speaker: You can speak on the Budget...(Interruption)... No recording please. You should be adhered to the Rules.

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, चौहान साहब बहुत कम बोलते हैं और इनको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। जिन्होंने यहां पर अंट-शंट बोला उनको एक घंटा बोलने का मौका मिल गया मगर चौहान जी शरीफ़ आदमी हैं और इन्हें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।

08/03/2017/1545/RKS/AS/2

श्री बी0 के0 चौहान: सर, आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के ध्यान में यह बात ला रहा था कि अभी जो एक साल में इंटरव्यू हुए हैं वे इंटरव्यू किसी मैरिट या अनुभव

के आधार पर नहीं हुए just pick and choose. I don't want tell the criteria. कि किस बेसिज़ पर हुए। यदि किसी बच्चे की एजुकेशन क्वालीफिकेशन, एक्सपीरियंस, उसकी ट्रेंनिंग या डिप्लोमा नहीं देखा जाएगा, तू भी रख लिया, तू भी रख लिया और डिजर्विंग कैंडिडेट घर को हाथ मलते हुए जाते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण वन विभाग का इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में आवश्यक चीजों को दरकिनार किया गया। हम चम्बा जिला से भारतीय जनता पार्टी के तीन विधायक हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से एक लड़का सिलैक्ट हुआ है। बाकि most of the majority of the selected candidates are only from one constituency. इस इंटरव्यू में शायद आठ सौ, नौ सौ या एक हजार आदमी वन विभाग ने सलैक्ट किए हैं परन्तु मेरे निर्वाचन क्षेत्र से एक ही लड़का सिलैक्ट हुआ है। इसमें भी जो लड़का मैरिट में सलैक्ट होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। सलैक्ट वह हुआ जिसकी मां डी.एफ.ओ. के घर में काम करती थी। यह इसमें क्राइटेरिया है। फिर भी अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि मैं बैठ जाऊं, तो मैं बैठ जाता हूं। ये जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं क्या हम उनको स्वाल करते जाएं?

Speaker: Shri B.K. Chauhan Sahib, I think you will not able to finish it in three days. अगर आप इस तरह से बोलते रहेंगे तो आपको तीन दिन लग जाएंगे। You kindly wind it up.

श्री बी0 के0 चौहानः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बताना भूल गया जिसकी वन मंत्री जी मुझे याद दिला रहे हैं। इस इंटरव्यू में चंबा जिला से सिर्फ मेरे निर्वाचन क्षेत्र से ही एक कैंडिडेट सलैक्ट हुआ और बाकि सब भरमौर से सलैक्ट हए हैं।

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र से ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से कैंडिडेटों की सलैक्शन हुई है और यह सिलैक्शन पोस्टों के मुताबिक मैरिट व नियमों के अनुरूप हुई है।

श्री बी0 के0 चौहान श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

08.03.2017/1550/SLS-AS-1

श्री बी0 के0 चौहान : अध्यक्ष महोदय, अंत में मुझे यही प्रार्थना करनी है कि मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता था कि जो इस तरह का सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है कि 2-2, 3-3 हजार बच्चे इंटरव्यु देने आते हैं लेकिन उसमें मैरिट और एक्सपीरियंस को इग्नोर करके जो पिक एंड चूज किया जाता है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। ऑफ्टर ऑल सारी जनता पैसा नहीं दे सकती; सभी लोग पैसा नहीं दे सकते क्योंकि चम्बा एक गरीब जिला है। मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं कि लोग सरेआम यह बात करते हैं कि पैसा लेकर यह काम हो रहे हैं। यह बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था। ...(व्यवधान)... what do you mean behave yourself? Stop it. Don't speak unparliamentary language. मैंने आपका नाम नहीं लिया और न किसी और का नाम लिया। ...(व्यवधान)...अध्यक्ष महोदय, देख लीजिए, सब-कुछ आपके सामने है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता लेकिन मैं यह सब बातें रखना चाहता था। आप बार-बार बैठने के लिए कह रहे हैं, इसलिए मैं आपसे विदा लेता हूं।

धन्यवाद।

Speaker : I will give some other day.

Health Minister: Hon'ble Speaker, Sir, I raise two issues regarding health. No.1, Trauma Centre, he said Trauma Centre should be sanctioned, I am please to inform you that Trauma Centre for Chamba has been already sanctioned and we have released 2.5 crore rupees. On our recommendation the Government of India has done it. भारत सरकार ने हमारी सिफ़ारिश पर किया। It is with our request. आप सुनो। हमने सिफ़ारिश की, तब चम्बा में मैडिकल कॉलेज खोला गया। मैडिकल कॉलेज UPA सरकार के समय गुलाम नबी आज़ाद जी ने दिया है। अब उसके लिए बिल्डिंग बना रहे हैं। ...(व्यवधान)...डॉक्टरों की पोजिशन चम्बा में ठीक है। That is with regard to posting of doctors in Medical College Chamba. चम्बा में इस वक्त सरप्लस डॉक्टर्ज़ हैं। आपने प्रिंसिपल के बारे में कहा। प्रिंसिपल लगाया

08.03.2017/1550/SLS-AS-2

गया है और वह इंटरव्यु कंडक्ट कर रहा है। उन्होंने इंटरव्यु कंडक्ट करके असिस्टैंट प्रोफ़ैसर और रजिस्ट्रार बगैरह अप्वायंट किए हैं। ...(व्यवधान)...

श्री बी.के.चौहान : वहां पर जो स्पैश्लिस्ट हैं, वह सब सुलतानपुर में लाईन में 5-6 क्लीनिक खोलकर और अपनी बिल्डिंग बनाकर पैसा कमा रहे हैं और आपका अस्पताल खाली है।

Health Minister: We have initiated action against them. They are being Charge sheeted and we will see that they should be dismissed or terminated from the service.

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं अपना भाषण आरंभ करूं, मैं कहना चाहूंगा कि मुझे कहा गया था कि मुख्य मंत्री द्वारा अभिभाषण का उत्तर 2.00 बजे अपराह्न दिया जाएगा। अब 4.00 बज चुके हैं। इस सदन की कुछ परंपराएं होती हैं कि कब डिबेट शुरू होती है और कब डिबेट खत्म किए जाते हैं। मगर मैं कहना चाहूंगा कि अगर बहुत ज्यादा लोगों ने बोलना हो, let him speak till mid night. 10 बजे तक बोलते रहें।

जारी ... श्री गर्ग जी

08/03/2017/1555/RG/DC/1
मुख्य मंत्री----क्रमागत

ऐसे ऐक्स्ट्रा आदमी को अकॉमोडेट करने के लिए हमेशा समय को ऐक्स्टेंड किया जाता है। यह नहीं है कि जो पूर्व निश्चित कार्यक्रम है कि Chief Minister will reply at 2.00 p.m. और अब मैं चार बजे बोल रहा हूं। मैं इस बारे में आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव श्री जगजीवन पाल, माननीय मुख्य संसदीय सचिव ने रखा तथा श्री संजय रतन ने इसका अनुसमर्थन किया, उस पर जो चर्चा माननीय सदन द्वारा पिछले दो दिनों से की गई है उसमें प्रति पक्ष के नेता सहित कुल 38 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। इसमें से 15 पक्ष के थे, दो पक्ष के सहयोगी सदस्य थे और 20 प्रतिपक्ष के सदस्य थे। हम सबके लिए यह एक गर्व का विषय है कि माननीय सदस्यों द्वारा सदन की परम्पराओं के अनुसार इसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया एवं गुणात्मक चर्चा यहां की गई।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन में कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार ने पिछले चार वर्षों में प्रदेश का समग्र एवं भरपूर विकास किया है। हमारी सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को साथ लेकर, प्रदेश के हर हिस्से को साथ लेकर, प्रदेश के हर हिस्से को एक माला में पिरोया है तथा हर वर्ग की दुःख और तकलीफों को दूर करते हुए प्रदेश में विश्वास, भाईचारा एवं खुशहाली लाई है।

अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा के दौरान सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे। सबसे पहले विपक्ष की ओर से जो एक बड़ा सवाल उठाया गया वह कांग्रेस के मैनीफेस्टो के बारे में था। कहा गया कि कांग्रेस के मैनीफेस्टो के अनुरूप काम नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि सौ फीसदी कोई भी मैनीफेस्टो कार्यान्वित नहीं होता। हमने जो मैनीफेस्टों में लिखा था उसका 99% कार्य पूरा किया है। एक प्वाइंट था जो हमने आगामी कुछ आर्थिक कारणों से उसको नहीं अपनाया। वह था बेरोजगारी भत्ता। कोई भी सरकार ऐसा कदम उठाने से पहले अपने खजाने को देखती है, अपने संसाधनों को देखती है और उसके बाद ही ऐसे अहम कदम उठाए जाते हैं। हमने यह सोचा कि बेरोजगारी भत्ता भी महत्वपूर्ण है। मगर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमारे बच्चों को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार मिले। उसके

08/03/2017/1555/RG/DC/2

लिए हमने काफी धन लगाया। हमने कहा कि जिस बच्चे की उम्र 15 साल है उससे ऊपर के तीस साल तक के जो लोग हैं वे स्किल डवलपमेंट अलाउन्स ले सकते हैं। Employment through skill development ताकि उनकी स्किल अच्छी हो और वह ऐम्प्लायऐबल हो

जाए। इसको हमने ज्यादा महत्व दिया है। यह नहीं है कि जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात है, हम उसको भूल गए हैं

एम.एस. द्वारा जारी

08/03/201 7/1600/MS/DC/1

मुख्य मंत्री जारी-----

जब भी ऐसे अवसर होंगे, वे चाहे जब भी हों, यदि हमारे पास संसाधन होंगे और हम इसके लिए अलग से धन का प्रावधान कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हम उसको अमल में लाएंगे। लेकिन आज तक हम इसको अमल में नहीं ला पाए और इसका कारण संसाधनों की कमी है। वैसे भी हमारा चुनाव घोषणा पत्र पांच साल का है। -(व्यवधान) -हंसते क्यों हो? हो सकता है हम लाएं, हो सकता है हम न ला पाएं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो चाहते हुए भी संसाधनों की कमी की वजह से हम नहीं कर पाते हैं। यह बात साफ होनी चाहिए। आप लोगों ने जो बातें अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहीं, क्या वे आपने शत-प्रतिशत पूरी की हैं? बहुत सी चीजें हैं जो नहीं हुई हैं। उसके लिए हम आपको दोष नहीं देते हैं। हो सकता है कि आपकी नीति का परिवर्तन हुआ हो, हो सकता है आपको भी संसाधनों की कमी आई हो। इसलिए यह कहना कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र का शत-प्रतिशत पालन होना चाहिए, वह आवश्यक नहीं है। अभी भी हमारे पास एक वर्ष का समय और है। मुझे अभी भी यकीन है कि जब अगला चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आएगी। ***"मुदैई लाख बुरा चाहे, होता क्या है, होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है" ।***

अध्यक्ष जी, विपक्ष की तरफ से जो बातें कही गई हैं उनका मैं अक्षरशः जवाब नहीं देना चाहता। मैं कुछेक बिन्दुओं का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने पहले तो कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र की बात की है जिसका अभी मैंने जिक्र किया। मुझे खुशी है कि हमने कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में जहां रोजगार देने की बात है, जहां पर सड़कों को बढ़ाने की बात है, जहां पर पीने-के-पानी को देने की बात है, बिजली का विस्तार करने की बात, बिजली में और गुणवत्ता लाने की बात है, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार करने की बात है और हिमाचल

प्रदेश में मेडिकल कॉलेजिज खोलने की बात है, वे हमने पूरी की हैं। मैं यह दावा नहीं करता कि हमने हर जगह पर काम कर दिया है। हो सकता है कि कुछेक जगह रह गई होंगी, जहां पर कुछ काम बाकी करने को रह गए होंगे। मगर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हमारी सरकार ने इन सेवाओं का विस्तार किया है जिसका हमें गर्व है।

08/03/201 7/1600/MS/DC/2

अध्यक्ष जी, विपक्ष के लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन की बात की है। यह कोई नई बात नहीं है। मैं भी काफी छोटी सी उम्र में राजनीति में आ गया था और आज मैं 83 वर्ष का हो गया हूं। इन वर्षों के अंदर चाहे जनसंघ रहा हो या भारतीय जनता पार्टी रही हो उनकी तरफ से डिस्क्रिमिनेशन की ही बातें होती रही हैं। यह इनका परमानैंट मुद्दा है। कभी डिस्क्रिमिनेशन क्षेत्र के नाम पर, कभी जाति के नाम पर और कभी नये और पुराने हिमाचल के नाम पर कहते हैं। इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की बात करना आपकी मानसिकता का एक हिस्सा है। हमारी सरकार डिस्क्रिमिनेशन में विश्वास नहीं रखती है। -(व्यवधान)- आप सुनते जाइए you may agree with me or you may not. I have listened to you with respect and you listen to me with respect.

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

08.03.2017/1605/जेके/एजी/1

मुख्य मंत्रीः----जारी---

हमारे मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हमने एक-दूसरे के खिलाफ कई दफा चुनाव लड़े हैं। जब आप जनसंघ में थे, तब भी लड़े हैं और जब भारतीय जनता पार्टी में है, तब भी लड़े हैं। कोई चुनाव ऐसा नहीं हुआ जिसमें आपने शुरू-शरू में बड़े-बड़े सिद्धांतों की बात न की हो और अंततः जैसे चुनाव की गर्मी बढ़ती जाती है फिर आपकी भारतीय जनता पार्टी हो या जन संघ हो, हमेशा फिर क्षेत्रवाद फैलाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं। निचले पहाड़, बीच के पहाड़, ऊपर के पहाड़, नया हिमाचल, पुराना हिमाचल और जब ये चीज भी न चले तो फिर राजपूत ये ब्राह्मण, ये हरिजन, इस तरह की बातें की जाती है।

(व्यवधान) बिल्कुल ठीक है। आप लोग इस तरह की बाते करते हैं। मैं आपकी मानसिकता को पूरी तरह से जानता हूं। इतने वर्षों में मैं आपकी मानसिकता में पी0एच0डी0 हो गया हूं। यही मैं आपको कहना चाहता हूं। आपकी इतनी संकीर्ण विचारधारा है, आप लोग शर्म करो। हमको तो गर्व होना चाहिए कि हम इस देश के वासी हैं। हमें गर्व होना चाहिए हम हिमाचल प्रदेश के वासी हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी आप नया हिमाचल, पुराना हिमाचल, ऊपर के पहाड़, नीचे के पहाड़ की, इस किस्म की जात-पात की बातें करते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि हमारा देश आज मजबूत देश है। हम आजाद हुए और हमने एक ऐसा संविधान बनाया जो कि आजादी के इतने वर्षों तक एक बहुत सफल संविधान 65 साल के अन्दर सिद्ध हुआ है। हमारे देश के अन्दर कई धर्म के लोग हैं। हिन्दु है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, फारसी है, बौद्ध है, ईसाई है और भी कई धर्म व सम्प्रदाय के लोग हैं। देश एक तब रहेगा जब सारा देश इकट्ठा रहेगा। आप लोग तो हमेंशा जातपात, इलाकावाद, क्षेत्रवाद की बात करते हैं और ये आप लोगों की मानसिकता है। ये आपकी राजनीति नहीं है। ये राजनीति से ऊपर उठ कर आपकी मानसिकता बन चुकी है। ***. (Interruption) मैं इस बात को कहना चाहता हूं। .....(व्यवधान).....

Speaker: Please keep quiet.

————————————————————

*** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

08.03.2017/1605/जेके/एजी/2

Chief Minister: Let me withdraw this word. *** . . . (Interruption) बोलिए, बोलिए। (व्यवधान) बैठिए, बैठिए। .....(व्यवधान).....

Speaker: Please sit down.

मुख्य मंत्री: आपने बहुत बातें की है हम क्यों चुप बैठे रहें? मैं बालता हूं और आपको उसको सुनना पड़ेगा। .....(व्यवधान).....

Speaker: Please sit down. (Interruption) हो गया, अब बात खत्म हो गई। It is finished now. (Interruption)

मुख्य मंत्री: आपने जितने भी इलैक्शन हिमाचल प्रदेश में लड़े हैं, जितने भी विधान सभा के इलैक्शन हुए हैं, हर इलैक्शन के अन्दर क्षेत्रवाद और जातिवाद फैलाया गया है। ये सारा हिमाचल प्रदेश इस बात को जानता है। .....(व्यवधान)..... मैं सच बोल रहा हूं इसलिए आपको चुभ रहा है। (Interruption)

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

08.03.2017/1610/SS-AG/1

मुख्य मंत्री क्रमागत: I am not yielding.

अध्यक्ष: मेरी बात सुनिये। अब बात खत्म हो गई। --(व्यवधान)--

मुख्य मंत्री: जहां तक *** शब्द का संबंध है, I have withdrawn the words. --(व्यवधान)--

अध्यक्ष: इन्होंने थिंकिंग के बारे में कहा था। --(व्यवधान)--

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैंने कहा कि ***, यह मैंने शब्द विदड्रो कर लिया है। I wanted to say that their mental outlook is not proper. I wanted to say that. --(व्यवधान)-- बात खत्म हो गई। (Interruption) My sister, everything is okay. (Interruption)

Speaker: Expunge the remarks.

Chief Minister: This was a slip of tongue on my part. What I should say is that you are mentally sick. I said that I withdraw that word.

अध्यक्षः शब्द विदड्रो हो गया और आप फिर भी नहीं मानते। शब्द एक्सपंज कर दिया, फिर भी आप नहीं मानते।

मुख्य मंत्रीः बात खत्म हो गई। । still say कि आपकी जो कोर राजनीति है, चाहे वह जनसंघ था या चाहे भारतीय जनता पार्टी है it is nothing but casteism, regionalism and secularism. --(व्यवधान)-- कांग्रेस ने देश को आज़ाद किया और आज़ादी के बाद एक गरीब प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले गए। --(व्यवधान)--

Speaker: Please sit down. --(व्यवधान)-- आप बैठ जाईये प्लीज़। वह शब्द विदड्रो हो गया। आप क्या बात करते हैं? विदड्रो हो गया है। (Interruption)

———————————————————————————— जारी श्रीमती के0एस0

*** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

08.03.2017/1615/केएस/एएस/1

Hon. Speaker ... continue...

Hon'ble Members, please, listen to me. (व्यवधान) आप बैठ जाइए। सुन लीजिए। Please sit down. इन्होंने अपने शब्द वापिस ले लिए हैं। (व्यवधान)..The Hon'ble Minsiter has already withdrawn his words, which he said.

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, न केवल विपक्ष के नेता ने बल्कि इनकी ओर से कई सदस्यों ने भेदभाव की बात की। As if one designate is discriminating against other. This again comes to realism. There is no question of discrimination. भेदभाव का कोई मतलब ही नहीं है। हमारी डिक्शनरी में ही डिस्क्रिमिनेशन जैसा शब्द नहीं है। जो भी अच्छा किया है, वह सभी के लिए है और हमने जो नीतियां बनाई हैं, वे भी सभी के लिए हैं। हम हिमाचल को एक समझते हैं और हिमाचल प्रदेश की पूरी जनता की तरक्की और विकास के लिए, हिमाचल को आगे ले जाने के लिए हम वचनबद्ध है। हम क्षेत्रवाद और

जातिवाद में विश्वास नहीं रखते। हम नया हिमाचल, पुराना हिमाचल में विश्वास नहीं करते। हम नीचे के पहाड़, ऊपर के पहाड़ में विश्वास नहीं करते। हमारे लिए सारा प्रदेश, सारा देश एक है। हम इसी भावना से काम करते हैं। आप तो टोपी के रंग में भी राजनीति करते हैं। इनको मालूम नहीं है कि मैं पांच बार मुख्य मंत्री बना हूं और तीन दफ़ा मैंने लाल टोपी पहनकर ओथ ली है। ये समझते हैं कि भाजपा वाले लाल टोपी पहनेंगें और कांग्रेस वाले हरी टोपी ही पहनेंगें। आप हर चीज़ में भेदभाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। मैं तो सभी कांग्रेस के सदस्यों से भी कहना चाहता हूं कि भविष्य में आप लाल टोपी भी पहना करो और हरी टोपी भी पहना करो ताकि जो ये क्षेत्रवाद का भूत पैदा कर रहे हैं वह खत्म हो जाए। टोपी की राजनीति खत्म करो।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः मुख्य मंत्री महोदय, टोपी के रंग से फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपकी मानसिकता के कारण पड़ रहा है। आपके परिवार में ही अब लाल टोपी लगनी शुरू हो गई है। आप भी तो हरी टोपी ही लगाते हैं। हम लाल लगाते हैं तो क्यों दिक्कत हो रही है?

08.03.2017/1615/केएस/एएस/2

मुख्य मंत्रीः आप हरी टोपी क्यों नहीं लगाते, पीली क्यों नहीं लगाते, नीली टोपी क्यों नहीं लगाते?

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः आप लाल टोपी क्यों नहीं पहनते? अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि हम भेदभाव नहीं करते।

मुख्य मंत्रीः आप कहते हैं ग्रीन ब्रिगेड, रैड ब्रिगेड लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहूंगा कि आप लाल टोपी भी पहनिए, हरी टोपी भी पहनिए और विपक्ष के लोग भी ऐसा ही करें। If you are true Himachali, you will not discriminate on the basis of colour.

Prof. Prem Kumar Dhumal: We will not discriminate. I have already said there is a red cap brigading your house now.

धूमल जी अ0व0 की बारी में----

8.3.2017/1620/av/as/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल... जारी

मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप क्षेत्रवाद नहीं करते। (---व्यवधान---) अभी सुप्रीम कोर्ट का एच0आर0टी0सी0 पर एफ0आई0आर0 करने का आर्डर हुआ है। नगरोटा-बगवां से 73 कंडक्टर सिलैक्ट हुए और 37 आपके रोहड़ू से हुए। 305 में से जो मैरिट में थे उनमें से एक लड़का सिलैक्ट हुआ है। कोर्ट से आर्डर आ गया। (---व्यवधान---) 73 और 37 की फिगर है और यह फिगर कोर्ट में गई है। इसलिए क्षेत्रवाद तो आप करते हैं। अभी फॉरैस्ट के बारे में बी0के0 चौहान जी सुना रहे थे कि कितने लोग कहां के सिलैक्ट हुए। क्या मंत्रियों के चुनाव क्षेत्र में ही योग्य लोग पैदा हो रहे हैं? कहां पर लिटरेसी का स्तर कितना ऊंचा है? आप इस प्रकार के दोष देकर के कि कोई फासिस्ट पार्टी है या कोई फलाना है। क्या हमने आपकी पार्टी का जिक्र किया? हमने तो गवर्नमैंट की पॉलिसीज को डिसकस किया, आपके मेनिफैस्टो को डिसकस किया क्योंकि आपने उसको राज्यपाल महोदय के माध्यम से पढ़वाया था, हम उस पर बोले हैं। आप उनका जवाब दो जो यहां पर मुद्दे उठाये गये। आप हमें डिसक्रिमिनेशन का जवाब दो, जो डिफ्रैंसिज हुए उनका जवाब दो। प्रदेश में जो डवैल्पमैंट नहीं हुई और हमारे निर्वाचन क्षेत्र से जो दफ्तर चेंज किए गए उनका जवाब दो; आप लग पड़े इतिहास पढ़ने और इतिहास हम भी पढ़ सकते हैं। हमने फ्युडेलिज़म पर नहीं बोला, हमने रजवाड़ाशाही पर नहीं बोला, हमने ये शब्द टच भी नहीं किए। इसलिए आप भी अब नये कंटैक्स्ट पर बोला कीजिए।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय धूमल साहब ने एच0आर0टी0सी0 की बात करते हुए एक केस के बारे में कहा है। शायद धूमल साहब को याद नहीं कि इन्होंने पूरे पांच वर्ष विजिलैंस लगाकर हमारी इनक्वायरी करवाई।

इन्हीं के टाइम में रिपोर्ट आई कि वह केस कुछ नहीं बनता है। एक इंडिविजुअल कोर्ट में गया और कोर्ट ने पता नहीं किस बेस पर यह फैसला लिया है। अधिकारियों के खिलाफ जो उन्होंने कहा वह अधिकारी कोर्ट में गये हुए हैं। उसकी यहां पर चर्चा नहीं बनती थी मगर आपने

8.3.2017/1620/av/as/2

चर्चा की है तो मेरा स्पष्टीकरण देना भी बनता है। (---व्यवधान---) फैक्ट यह भी है कि आपने पूरे पांच साल इनक्वायरी की है। फैक्ट यह भी है कि आपने क्लीन चिट दी। (---व्यवधान---) आप जाकर अपना रिकार्ड चैक कर लीजिए। हमें फांसी चढ़ा दो क्योंकि आपके समय में धूमल साहब (---व्यवधान---) अब आप मेरी बात सुन लो। आपको याद होगा कि आपके समय में ओ0बी0सी0 के साथ अन्याय हुआ था और एक वकील ने सुसाइड करने का प्रयास किया था। आपको यह बात याद है या नहीं? कृपा करके मेरा मुहं मत खुलवाओ। मैं यहां विपक्ष में चार साल बैठकर कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का रिकार्ड मांगता रहा मगर आपने नहीं दिया था। इसलिए इस बात को अब रहने दो। अब अगर कोई नगरोटा का लग गया तो क्या वह कांगड़ा का नहीं है? उस चीज़ की किसी को तकलीफ हो रही है? वे भी पेपर देकर के आए हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, रोहड़ू से कोई 37 आदमी नहीं लगे वहां से मुश्किल से 5-6 आदमी लगे होंगे। (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : आप (श्री नरेन्द्र ठाकुर जी द्वारा कुछ कहने के लिए खड़े होने पर कहा।) बैठ जाइए।

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। ऐसे हर कोई मैम्बर अपनी बात बोलने के लिए बीच में कैसे खड़ा हो सकता है? इस तरह से तो सारे मैम्बर बोलते रहेंगे।

अध्यक्ष :**श्री वर्मा द्वारा जारी**

08/03/2017/1625/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

अध्यक्षः मैं आपसे एक निवेदन करूंगा -(व्यवधान)- प्लीज़, प्लीज़ -(व्यवधान)-ठाकुर साहब एक मिनट -(व्यवधान)-

श्री नरेन्द्र ठाकुरः सर, सरेआम हेराफेरी हुई है, -(व्यवधान)-

Chief Minister: I am continuing with my speech.

श्री नरेन्द्र ठाकुरः हमीरपुर से एक लड़का था, जिसके 99 परसेंट नम्बर थे, उसको इग्नोर किया गया और 50 परसेंट वाले लड़के को नौकरी दे दी गई।-(व्यवधान)- ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? -(व्यवधान)-

मुख्य मंत्रीः नरेन्द्र भाई, अच्छा है जो आप हमारी पार्टी से ऊधर चले गये। You are most indisciplin man. वहीं रहना वापिस आने की कोशिश मत करना। Sit down. -(व्यवधान)- अध्यक्ष महोदय, it is enough now. It is their strategy, it is their pre-planned strategy to disturb me while I am giving my speech. ---(Interruption)--- Yes I have got CID report yesterday. There are some Members who will try to do this. It is your well planned strategy. मैं बोलता रहूंगा, चाहे रात के 12.00 बज जाये। You can't bully me. --- (Interruption) --- CID means Intelligence, I am telling you about Intelligence. --- (interruption)--- It was Intelligence that you are conspiring to disturb my speech today. --- (interruption)--- शर्म कर (श्री सुरेश भारद्वाज) रोहडू का रहते हुए ऐसी बकव़ास करता है,शर्म कर- शर्म कर। -(व्यवधान)- (विपक्ष के सभी सदस्य अपनी-अपनी सीट खड़े हो गये और नारे लगाने लगे)

Speaker: Please be seated -(व्यवधान)- बैठ जाईये। बैठ जाईये। -(व्यवधान)-

मुख्य मंत्रीः आप मेरे और भारद्वाज के बीच क्यों आते हैं? हमारे पुश्तैनी संबंध है, एक दूसरे के साथ। -(व्यवधान)- आप खुक्सूभाट क्यों बन रहे हैं। -(व्यवधान)- जिसका मतलब है, मान-न-मान मैं तेरा मेहमान -(व्यवधान)- पंडित जी बैठ जाइये।

अध्यक्षः मेरी यह रिक्वैस्ट थी कि इनको अपना उत्तर पढ़ने दीजिये, फिर आप करते रहना जो ऑब्जेक्शन आपको करना होगा।

श्री एन0एस... द्वारा जारी।

08/03/17/1630/ns/dc/1

मुख्य मंत्री : पंडित जी आप बैठ जाईए। (--व्यवधान)

अध्यक्षः मेरी आप सबसे यह रिक्वैस्ट है कि इनको राज्यपाल के अभिभाषण का उत्तर पढ़ने दीजिए। आप अपना ऑब्जैक्शन बाद में करें। मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री सुरेश भारद्वाजः आप उस तरफ (रूलिंग पार्टी) को अलाऊ नहीं करते हैं तब भी लाल बत्ती जल जाती है और हमें (विपक्ष) अलाऊ करते हैं तब भी नहीं जलती है। (--व्यवधान)

अध्यक्षः मैं ऐसा नहीं करता हूं।

मुख्य मंत्रीः हमें तो यह शिकायत है कि स्पीकर साहब आपकी तरफ ही देखते रहते हैं। हमारी तरफ देखते ही नहीं हैं। आपको एक-एक घंटें का समय बोलने के लिए दिया गया है। यहां पर हमारे कई सदस्यों (सत्ता पक्ष) को बोलने का मौका ही नहीं मिला है। (--व्यवधान)

अध्यक्ष : आप मुख्य मंत्री जी के उत्तर के बाद क्लैरिफिकेशन लीजिए। आप स्पीच के बीच में डिस्टर्ब न करें। (--व्यवधान) श्री सुरेश भारद्वाज जी आप क्या बोलना चाहते हैं।

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बड़ी शालीनता के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो इस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आया, हमने उसकी चर्चा में भाग लिया। यह (मुख्यमंत्री) पहले से ही नहीं चाहते हैं कि यह सदन चले। इसलिए यह कोशिश

करते रहते हैं कि सदन के चलने से पहले ही कुछ-न-कुछ सदस्यों के बारे में बोल दें ताकि यह सदन चल ही न पाए। जब सदन चल पड़ता है तो यह कोशिश कर रहे थे कि हम राज्यपाल के अभिभाषण पर खड़े हो जाएं लेकिन हम उस पर खड़े नहीं हुए। हमने संशोधन दिए तो कहते हैं कि यह रूल्ज़ में नहीं है। अपने आप रूल बुक पढ़ते

08/03/17/1630/ns/dc/2

नहीं है और हमें बोलते हैं कि रूल में नहीं है। अब जब भाषण पर रिप्लाई हो रहा है, संसदीय कार्य मंत्री के साथ बात करके इन्होंने जो कहा उसके अनुसार हम बैठ करके इनको (मुख्य मंत्री) सुन रहे हैं। हम यहां पर इसलिए नहीं बैठे हैं कि हम ***या हम बकवास करते हैं। आपने "गधे को बाप बोला जाता है" इन शब्दों को आपने फटाफट निकलवा दिया। गधा बेचारा यहां आ नहीं सकता इसलिए निकाल दिया। (--व्यवधान)

अध्यक्ष : यह भी विदड्रा हो गया है। That has been withdrawn. (--व्यवधान)

मुख्य मंत्री : अभी यहां पर गधे की बात हुई ही नहीं है।

श्री सुरेश भारद्वाज : हम मुख्य मंत्री जी का सम्मान करते हैं। (--व्यवधान) मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा कि मैं 83 साल का हो गया हूं और यह हिमाचल प्रदेश के बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं तथा हम व्यक्तिगत रूप से इनका पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन इस प्रकार के शब्दों को सुनने के लिए प्रदेश की जनता ने हमें यहां पर नहीं भेजा है। (--व्यवधान)

अध्यक्ष : यह शब्द विदड्रा हो गये हैं।

श्री सुरेश भारद्वाज : अगर यह (मुख्य मंत्री)इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो हम भी इसी शैली में जवाब देंगे। (--व्यवधान) अगर यह ठीक शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो हम सुन रहे हैं और हम यहां बैठे हुए हैं। (--व्यवधान)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया उसे मैंने विदड्रा किया।। have right to say anything else. आपकी महिला एम0एल0ए0 (विपक्ष) श्रीमती सरवीन

चौधरी कहती हैं कि "आपकी पार्टी गधे की बाप है।" Is this the language? She should withdraw it. (--व्यवधान) Yes, she said it and it is on the record.

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी आप अपना रिप्लाई कम्पलीट कीजिए।

08/03/17/1630/ns/dc/3

Chief Minister : I heard it clearly. She said. आगे आईं और हमारे तरफ इशारा करते हुए कहा कि "ये गधे के बाप हैं।" She said it.---(Interruption)--- You withdraw it. (--व्यवधान) शर्म करो।

अध्यक्ष : आप शान्त रहिए। यह एक्सपंज हो जाएगा। (--व्यवधान) मैंने एक्सपंज कर दिया है।

मुख्य मंत्री : (--व्यवधान) शर्म करो। महिला हो करके ऐसा बोलती हैं।

श्री आर0के0एस0-----जारी।

08/03/2017/1635/RKS/AG/1

मुख्य मंत्री... जारी

फौजी अफसर की बीबी होते हुए ऐसा बोलती हो। (व्यवधान)...

Speaker: Kindly sit down. Please sit down. (Interruption)

Chief Minister: Madam, as a lady, we respect you. Hon'ble Speaker, Sir, as a lady, we respect her. जब ये ऐसे ऑब्नोक्सियस वर्ड्स यूज करती है और हमारी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि आप 'गधे के बाप' हैं। What is this? (व्यवधान)...

अध्यक्ष: आज महिला दिवस है, आज आप गुस्सा मत कीजिए। (व्यवधान)... हो गया (व्यवधान)... अभी क्लैरिफिकेशन कर लेंगे। (व्यवधान)... मुख्य मंत्री जी के रिप्लाई के

बाद आपकी क्लैरिफिकेशन ले लेंगे। (व्यवधान)... मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। (व्यवधान)... । will see the records also. (व्यवधान)...मैं आपको अलाउ करूंगा। (Interruption)

Chief Minister: Hon'ble Speaker, Sir, I am continuing my speech (व्यवधान)...

अध्यक्षः धूमल साहब मैं यह कह रहा हूं कि let him read out and then I will give her an opportunity to clarify. (व्यवधान)... गवर्नर स्पीच में जब भाषण चल रहा है, मैं इनको क्लैरिफाई करने के लिए मौका दूंगा।(व्यवधान)...

मुख्य संसदीय सचिवः हमने तो यह बोला कि सामने वाले लोग गधे को भी बाप बना सकते हैं। (व्यवधान)...

अध्यक्षः आप बैठिए। I will give you an opportunity to clarify. इसके बाद मैं तुरंत दूंगा (व्यवधान)... मैं अभी नहीं दूंगा (व्यवधान)... बीच में ये रिप्लाई दे रहे हैं(व्यवधान)...

मुख्य मंत्रीः मेरा कहना है शर्म करो, शर्म करो it is not an unparliamentary word. मैं इनकी शान को रखने के लिए कह रहा हूं (व्यवधान)...जो शब्द आपने कहे हैं वे गलत हैं। 'शर्म करो', मैंने क्या गलत बोला।

अध्यक्षः मेरी बात सुन लीजिए। मेरे पास रिकॉर्डिंग की कॉपी आ गई है,

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

08.03.2017/1640/SLS-AG-1

माननीय **अध्यक्ष**...जारी

आप चाहें तो मैं इस रिकार्डिंग की कॉपी को पढ़ देता हूं then you can decide.

आपने यह कहा है "मेहनत करो। भ्रष्टाचार कम करो, लोगों का काम करो और सच्चाई पर चलो। **तो गधों की तरह आप काम करो। ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी को काम करने की जरूरत है। ***** ...(व्यवधान)... यह मैंने एक्सपंज कर दिया है। ...(व्यवधान)... आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। What do you want to say?

श्रीमती सरवीन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात पूछना चाहती हूं कि इस सदन में गधा सबसे पहले लाया कौन? कौन-सी पार्टी का बंदा लाया? किसने पहले कहा? दूसरी बात, जो मैंने कहा, मैं उससे नहीं मुकरती। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : आपकी बात आ गई है। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप चर्चा का उत्तर जारी रखें।

Chief Minister: Sir, in my long political career, at least in Himachal Pradesh Legislative Assembly, I have not witnessed such a scene as today. (Interruption) मैं जानता हूं, I had already anticipated that you will do it. अध्यक्ष महोदय, मैंने डिसक्रिमिनेशन के बारे में बात की। ...(व्यवधान)...मैं इस प्वायंट को समाप्त कर रहा हूं। इन्होंने डिसक्रिमिनेशन की बात की। इनके खून में, ज़हन में हमेशा डिसक्रिमिनेशन की बात रहती है। So far we are concerned, there is no question of discrimination. I want to repeat that we believe in one Himachal and we believe in one India. That is the issue. आप किस चीज़ में बिलीव करते हैं, यह आप जानते होंगे।

***** अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार कार्यवाही से निकाला जा चुका है।**

08.03.2017/1640/SLS-AG-2

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने राजधानी की बात की है। मुझे नहीं पता, क्योंकि यह राजधानी कोई नई तो नहीं बनी। आज से कई वर्ष पहले वहां पर हमने विधान सभा का सैशन चलाने की बात की। हमारी सरकार थी और विधान सभा का सैशन वहां पर हुआ। आपकी सरकार बनी तो आपने भी विधान सभा का सैशन धर्मशाला में किया। हमने वहां पर विधान सभा के लिए नए भवन का निर्माण किया। हमारी सरकार ने ही धर्मशाला का महत्व बढ़ाने और उस क्षेत्र को अधिमान देने के लिए शिक्षा बोर्ड का दफ्तर वहां पर भेजा। हमने ही वहां पर चीफ

इंजीनियर पी.डब्ल्यू.डी. का दफ्तर क्रिएट किया, आई.पी.एच. का चीफ इंजीनियर का दफ्तर क्रिएट किया और बिजली बोर्ड के चीफ इंजीनियर का दफ्तर वहां क्रिएट किया। किसी ने नारा दिया और कहा कि नहीं, नहीं, यह शांता कुमार की वजह से बना या फलाने की वजह से बना। यह बिल्कुल गलत है। ...(व्यवधान)...हमारे पास भी इसका रिकॉर्ड है। मैं यहां पर नोटिफिकेशन की कॉपी रख दूंगा। (Interruption) Yes, I will give it.

जारी ...गर्ग जी

08/03/2017/1645/RG/AS/1

मुख्य मंत्री ...जारी

मैं आपको नोटिफिकेशन की कॉपी रख दूंगा।

श्री रविन्द्र सिंह : आप उसकी कॉपी यहां ले कीजिए कि कौन-कौन से कार्यालय कब-कब वहां गए?

मुख्य मंत्री : ठीक है, I got that copies. मैं प्रमाणित करके कॉपी टेबल पर रख दूंगा। जो बात हुई हैं उसको झुठलाना, सच को झूठ करना और झूठ को सच करना, यह कोई राजनीति नहीं है। इसी तरह से धर्मशाला आज एक महानगर बन रहा है और आज जैसा आपमें से किसी ने कहा और सब जानते हैं कि 15 एम.एल.एज. उस जिले से है Dharamsala does not represents only district Kangra. Dharamsala was the district headquarter of the area right up to Hamirpur and Lahaul & Spiti was also the part of Kangra district. It has a historical background. It is for the many reasons and this is the most important reason that we said it that Dharamsala should be there as the second capital of Himachal Pradesh and Winter Session of the Assembly will be held there. तो यह बात है। उस जगह को इम्पॉरटेंस देने के लिए, उसको महत्व देने के लिए यह कदम उठाया गया है और इसके पीछे कोई और मोटिव नहीं है। लेकिन आज आप उसको अपोज कर रहे हैं। You are opposing, I know

मैंने जब घोषणा की कि यह प्रदेश की दूसरी राजधानी होगी, तो ऐसा लगा कि जैसे मैंने आग में घी डाला हो। एकदम से बयान आने शुरू हो गए कि यह गलत है, ऐसा कैसे हुआ? यह आपकी मानसिकता है कि हमेशा तनाव बना रहे और आप अपने आपको धर्मशाला का न्यू हिमाचल प्रदेश का चैम्पीयन समझते हैं। हम सारे हिमाचल प्रदेश का चाहे वह पुराना हो या नया हो, उसके चैम्पीयन ही नहीं हैं उसका प्रथम सेवक अपने आपको समझते हैं। This is the difference. आप क्षेत्रवार पर विश्वास करते हैं, हम यूनिटी पर विश्वास करते हैं, आप कास्टिज्म पर विश्वास करते हैं, हम वननेस के ऊपर विश्वास करते हैं, तो यह बात है। मुझे यह इसलिए कहना पड़ा कि जिन लोगों ने धर्मशाला को प्रदेश की दूसरी राजधानी बनाने का विरोध किया, उनके अंदर क्षेत्रवाद की भावना थी कि अरे, कांग्रेस सरकार बाजी मार गई और हम कैसे पीछे रह गए? बल्कि आपको तो इस काम के लिए धन्यवाद करना

08/03/2017/1645/RG/AS/2

चाहिए था, इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सही कदम उठाया है।

श्री रविन्द्र सिंह : हमने इसका स्वागत किया, आपका धन्यवाद किया। लेकिन हमारी मांग यह है जिस तरह से जम्मू-काश्मीर में सरकार 6 महीने जम्मू में और 6 महीने श्रीनगर में चलती है उसी तर्ज पर यहां भी किया जाए।

मुख्य मंत्री : नहीं, 6 महीने नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता। --(व्यवधान)--अब तुमको शर्म लग रही है कि हमने वक्त पर उसका स्वागत नहीं किया। अब 6 महीने के लिए समय बढ़ाओ, 5 महीने के लिए समय बढ़ाओ। इतने समय के लिए बढ़ाओ, तो आपको खुश करने के लिए तैयार नहीं हूं। जब वक्त आएगा, तो हम देखेंगे।--(व्यवधान)---

श्री रविन्द्र सिंह : हमारी सरकार थी, तो दो सचिवालय बनाए हैं। हमारे समय में वहां मंत्री बैठते थे। आप बताएं कि आपके कितने मंत्री बैठते हैं?

मुख्य मंत्री : हमारे मंत्री बैठते हैं।--(व्यवधान)---

श्री रविन्द्र सिंह : हम वहां बैठते थे। --(व्यवधान)---

एम.एस. द्वारा जारी

08/03/2017/1650/MS/AS/1

मुख्य मंत्री : आपने इस बात का विरोध किया है कि कांग्रेस सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर स्कूल, तहसीलें, उप-तहसीलें और कॉलेज खोले हैं। इससे आपको क्या तकलीफ है? हमने इनको जनता की इच्छाओं और मांग के मुताबिक खोला है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को जनता के नजदक ले जाने के लिए ये संस्थान खोले हैं। अगर आपमें हिम्मत है तो आप बाहर जाकर स्टेटमैंट दे दो कि ये जो तहसीलें, उप-तहसीलें और कॉलेज खोले हैं इनको बन्द कर दिया जाए। आप बाहर जाकर बोलो।। am telling you to go out and say this. अगर आपको अपने क्षेत्र में कॉलेज पसन्द नहीं है तो आप बताइए कि आपके क्षेत्र में कौन से कॉलेज को बन्द किया जाए?

श्री रविन्द्र सिंहः जो मेरे क्षेत्र में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की नोटिफिकेशन हो चुकी है उसका शिलान्यास करवाइए।

मुख्य मंत्रीः ऐसा है, मैं कुछ कह रहा हूं और आप कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले आप यह बताइए कि आपके यहां पर कौन से कॉलेज, तहसीलें, उप-तहसीलें और कौन से सब-डिवीजन बन्द करने हैं? आप बताइए? मैं दूसरे ही दिन उसकी नोटिफिकेशन इशू कर दूंगा। आप लिखकर दीजिए।। will do it. अगर आपको अपने सब-डिवीजन नहीं चाहिए तो आप लिखकर दे दीजिए । I don't want sub-division, I don't want tehsil, I don't want sub-tehsil. अध्यक्ष जी, यह कहना आसान होता है। हमने लोगों की राय पर, उनकी मांग पर और उनकी मांग का परीक्षण करने के बाद ही नये संस्थान खोले हैं। चाहे वे शिक्षण संस्थान हैं, स्वास्थ्य संस्थान हैं या अन्य संस्थान हैं। आज प्रदेश में पहले से कई गुणा अधिक हमारी डिस्पेंसरीज हैं। चाहे वे आयुर्वेदिक हैं, एलोपैथिक हैं, पी0एच0सीज0 हैं या सी0एच0सीज0 हैं। आज इतने संस्थान खोलने के बावजूद भी मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे ही कॉलेजिज के लिए भी मांग बढ़ती जा रही है। कॉलेज के लिए बहुत सी मांगें हमें नामंजूर करनी पड़ रही है क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही क्षेत्र में नजदीक में दो कॉलेज नहीं हो सकते हैं। मगर यह एजुकेशन का एक्सपैंशन है। -(व्यवधान)-

08/03/2017/1650/MS/AS/2

श्री महेन्द्र सिंहः मुख्य मंत्री जी, एक और मांग आ रही है कि जिला मण्डी में भी एक राजधानी बना दो।

मुख्य मंत्रीः क्या यह आप मजाक कर रहे हो? I reject your *Maang*. यह वहां की जनता की मांग नहीं है बल्कि यह मांग एक पॉलिटिशियन की है। यह आपकी मांग है। मैं आपकी मांग को नहीं मानता। यदि मण्डी की सारी जनता मुझसे बात करेगी तो मैं सोचूंगा। you don't represent Mandi.

श्री महेन्द्र सिंहः आपको मण्डी की जनता ने कई बार जतलाया है।

मुख्य मंत्रीः न तो मेरी आपसे ज्यादा वार्तालाप होती है। । -(व्यवधान)-

श्री सुरेश भारद्वाजः शिमला से पहले पांच देशों का राज चलता था।

मुख्य मंत्रीः पंडित जी और दूसरे लोग भी सुनिए। आज अगर हमने धर्मशाला को सैकिण्ड कैपिटल बनाया है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है, यह मुझे बताइए? आपको बड़ा दुःख हो रहा है क्योंकि आपको लगता है कि हम इस दौड़ में पीछे रह गए हैं। -(व्यवधान)- तो मैं आपसे कह रहा हूं कि I don't want hear your argument. There is no question of going back. My Government has announced that and we stand by it.

जारी श्री जे0एस0 द्वारा------

08.03.2017/1655/**जेके/डीसी**/1

मुख्य मंत्रीः----**जारी**---

इन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में धांधली होती है। मैं उस वक्त को नहीं भूला हूं जब आपकी सरकार थी। धांधलियां तो तब हुई, अब नहीं। आज लगभग 43 हजार व्यक्ति पब्लिक सर्विस कमिशन और स्टाफ सलैक्शन बोर्ड, हमीरपुर के द्वारा अभी तक चुने गए हैं।

इसी तरह से हम आगे और भर्ती कर रहे हैं क्योंकि मैं जानता हूं स्कूलों का एक्सपैंशन हुआ है, नए कॉलेज भी खुले हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा टीचर्ज की जरूरत है, बहुत ज्यादा स्टाफ की जरूरत है। हम उनको भरेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो हम बैच वाईज भी भर्ती करेंगे। मैंने शिक्षा विभाग को कहा है by end of September I want that each and every vacant post in Education Department should be filled. हम सिर्फ पब्लिक सर्विस कमिशन और स्टाफ सलैक्शन बोर्ड पर ही निर्भर नहीं रहेंगें। They have limitations, they have to follow some procedures. हम बैच वाईज उनको भरेंगे। --- (Interupttion)--- It will be batch wise and their interviews will be held in every district. ये बैच वाईज खोलेंगे। हम चाहते हैं कि अक्तूबर के महीने से पहले-पहले हर स्कूल के अन्दर जितने भी मास्टर्ज लगने हैं, कॉलेज के अन्दर जितने भी टीचर्ज लगने हैं, वे भर्ती होने चाहिए। इसी तरह से जो हमारे कर्मचारी हैं उनका भी ख्याल रखा गया है। उनका जो वेतन है, पैंशन है उसमें उनका पूरा ख्याल रखा गया है। हम चाहते हैं कि जो आऊट सोर्स कर्मचारी हैं और जो लो पेड कर्मचारी हैं उनके लिए हम कुछ करें। उसके लिए आप लोग बजट का इंतज़ार कीजिएगा।

इसी तरह से आपने ड्रग्ज के बारे में बात की । आपको तो सरकार को बधाई देनी चाहिए कि जिस तेजी के साथ, संजीदगी के साथ और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हमारी पुलिस ने और दूसरा जो अलाईड स्टाफ है, उन्होंने ड्रग माफिया का मुकाबला किया है और उनको वहां से उखाड़ा है। मैं नहीं कहता कि 100 प्रतिशत खत्म हो गया है। मगर इस वर्ष में और इससे पहले जो कदम उठाए हैं, वे सराहनीय हैं। पंजाब के बॉर्डर के साथ, पंजाब के इलाके के अन्दर जितने उन्होंने मकान बना रखे थे, वॉकिंग डिस्टैंस में वे वहां पर ड्रग रखते थे और जो वॉकिंग

08.03.2017/1655/जेके/डीसी/2

डिस्टैंस था उस मकान में और हिमाचल के टैरिटरी के अन्दर वहां से सरेआम ड्रग हिमाचल में सप्लाई किया जाता था। उन सब को तोड़ दिया गया। लोगों को अरैस्ट किया

गया और सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैं नहीं कहता हूं कि 100 प्रतिशत एलिमिनेशन हो गया है, मगर इतना बड़ा झटका लगा है कि कोई भी ड्रग वाला हिमाचल प्रदेश में आने से पहले दो दफा सोचेगा।

श्री एस0एसव0 द्वारा जारी-----

08.03.2017/1700/SS-DC/1

मुख्य मंत्री क्रमागतः

ये काम अच्छा हुआ है, इस काम को और आगे भी जारी रखने की ज़रूरत है। इसके बारे में हमें चौकस रहने की ज़रूरत है क्योंकि ड्रग सप्लाई कई जगह से होती है। पंजाब से होती रही है। हरियाणा, चंडीगढ़ से होती रही है और हिमाचल में भी कुछ लोग अफीम पैदा करते थे उनके द्वारा सप्लाई होती रही है। आज हमने किसी जगह को नज़रअंदाज नहीं किया है। भांग की खेती एक बड़े पैमाने पर अभियान के अन्तर्गत उखाड़ी गई है। कोई भी इलाका इससे वंचित नहीं रहा है और जो स्मगलर्ज़ या कैरियर्ज़ पकड़े गए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। आज भी कई लोग जेल में हैं, कईयों को सज़ाएं हुई हैं। इसलिए गवर्नमैंट ने जो यह कदम उठाया है इससे ड्रग माफिया हिमाचल में आने से पहले दो दफा सोचेगा। 100 परसैंट इलीमिनेशन हुआ है मैं ऐसी बात नहीं कह सकता। There must be still some place, जहां कोई वीक प्वाइंट हो। मगर आमतौर पर जितना कदम इस वर्ष उठाया गया, इससे पहले ड्रग माफिया से निपटने के लिए इतने विस्तार से, वैल प्लांड और इतनी ज्यादा मैनपावर को लगाकर इस पैमाने पर पहले कभी काम नहीं हुआ। --(व्यवधान)-- ठीक है, मैं हिन्दुस्तान के ड्रग माफिया की बात नहीं करता। मैं उनकी बात करता हूं जो हिमाचल में आते हैं। जो हिमाचल को सप्लाई करते हैं उनकी बात करता हूं। ड्रग माफिया तो सारे देश में है और अन्य जगह भी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां अच्छा काम हुआ है we should appreciate it. The police has done very well and the results have been positive और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्ष के अंदर और इस वर्ष के

अंदर भी उसी मुस्तैदी के साथ बल्कि उससे बढ़-चढ़कर ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी जायेगी और उनको हिमाचल से बाहर उखाड़ने की कोशिश की जायेगी। यह कोशिश निरंतर जारी रहनी चाहिए ताकि वे लोग हमारे हिमाचल में घुसकर ड्रग की सप्लाई न कर सकें। ऐसे तो इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग माफिया आता है। हमारा जो पाकिस्तान-हिन्दुस्तान का बॉर्डर है, वहां जो दीवार लगी है उसको लांघकर गुप्त तरीके से ड्रग आ रही है। गुजरात में आ रही है, जहां भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है वहां आ रही है। वहां की सरकारें भी इसके बारे में कदम उठा रही हैं।

08.03.2017/1700/SS-DC/2

जब हर सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, केन्द्र सरकार हो, मिलकर ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन कामयाबी हासिल होगी और हम इस मिनेस को हमेशा के लिए खत्म कर पायेंगे।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी, सदन का समय बढ़ाना पड़ेगा। अब इस माननीय सदन का समय 5:15 बजे तक बढ़ाया जाता है।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पी0डब्ल्यू0डी0 के बारे में भी ज़िक्र हुआ। कई मेम्बरों ने किया। मैं समझता हूं कि हमारी पी0डब्ल्यू0डी0 बहुत अच्छा काम कर रही है और इस वर्ष के अंदर पी0डब्ल्यू0डी0 ने 2000 किलोमीटर नयी मोटरेबल सड़कें स्टेट सैक्टर के अंदर बनाईं और नेशनल हाईवेज़ अलग हैं। --(व्यवधान)-- नहीं, नहीं। इस साल नहीं, यानी अभी तक हमारे कार्यकाल में बनीं। --(व्यवधान)--

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जारी श्रीमती के0एस0

08.03.2017/1705/केएस/एजी/1

प्रो0 प्रेम कुमारः मैंने चार साल की रिपोर्ट पढ़ी है और 1100 किलोमीटर बनती है। आप चैक कर लें यह 2,000 किलोमीटर नहीं है।

मुख्य मंत्रीः आपने पता नहीं, कौन सी रिपोर्ट पढ़ी है?

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः जो आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पिछले चार वर्षों में लिखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं।

Chief Minister: Listen to me. अगर मैं गलत हूं तो you can contradict it later on. 2000 kms new roads were constructed, metalled and tarred in the last four years. 4000 kms roads were upgraded. 8000 kms roads were again re-tarred. यह काम हुआ है। Many dozen new bridges were constructed. तो यह काम अच्छा हुआ है considering the fact that working season in Himachal Pradesh is limited. सर्दियों और बरसात के मौसम में काम कम होता है। वर्किंग डे कम होते हैं। उसके बावजूद मैं लोक निर्माण विभाग को इस अचीवमैंट के लिए बधाई देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये भविष्य में इससे भी ज्यादा काम करेंगें और जल्दी से जल्दी जो कार्य अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, उनको पूरा करेंगें। धन्यवाद।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, हम कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एक तो इन्होंने जो 38 लोगों ने यहां पर बोला, उनमें से किसी एक का भी कोई जवाब नहीं दिया है। टोटल जवाब गोलमोल कर दिया है जिस तरह से इनकी सरकार चलती रही है। मैं राजधानी के विषय में इनसे स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि शिमला में राजधानी अंग्रेजों के समय में भी रही, पंजाब के समय में भी रही, हिमाचल प्रदेश जब बना था, तब भी रही और जब 1966 में बाहर से जिलों का मर्जर हुआ, तब भी शिमला को राजधानी बनाया गया। सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर यहां पर है। यहां के कर्मचारियों को कैपिटल अलाऊंस भी मिलता है और हाऊस रैंट भी मिलता है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताएंगें कि जो धर्मशाला को दूसरी राजधानी घोषित किया गया

08.03.2017/1705/केएस/एजी/2

है, वहां पर भी ये सारी सुविधाएं देंगें जिस दिन से इन्होंने नोटिफिकेशन की है, उसी दिन से दे देंगें? क्या यहां से सचिवालय के कर्मचारियों को, जो राज्य स्तर के निदेशालय हैं, उन सभी को बदल कर छः महीने के लिए या आधे-आधे या पूरे ही धर्मशाला ले जाएंगें? तीसरा, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताएंगें कि हिमाचल प्रदेश पर वर्तमान में कितना कर्जा इन्होंने आज तक एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को चलाने के लिए लिया है? क्या धर्मशाला में दूसरी राजधानी चलाने के लिए और ज्यादा कर्जा हिमाचल प्रदेश की जनता पर डालना चाहेंगें जिन पर पहले ही 50 हजार प्रति व्यक्ति आज तक इन्होंने कर्जा चढ़ा दिया है? क्या ये यहां से सारी राजधानी ले जाना चाहते हैं क्योंकि इससे पहले शिमला स्मार्ट सिटी के लिए पूरी तरह से कम्पिटैंट सिटी था। पहले शिमला को स्मार्ट सिटी घोषित किया जाना था लेकिन आंकड़ों में हेराफेरी करके शिमला के 85 नम्बरों के मुकाबले इन्होंने शहरी विकास मंत्री के प्रेम में और सारे अधिकारियों से सर्कुलेशन से मीटिंग करवाकर साढ़े सत्तासी नम्बर बना दिए और धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बना दिया। क्या ये पूरे शिमला जिला को अब छोड़ देना चाहते हैं और अपना होलीलॉज भी धर्मशाला में ही बनाना चाहते हैं? क्या इसको क्लैरिफाई करेंगें?

मुख्य मंत्री श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी....

8.3.2017/1710/av/ag/1

मुख्य मंत्री : ऐसा है, पंडित जी महाराज, रोहड़ू निवासी, भमनोली के पंडित जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं (---व्यवधान---)

श्री सुरेश भारद्वाज : मुझे खशी है कि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं।

मुख्य मंत्री : मैं पूरी से नहीं जानता था मगर मैं अब आपकी मानसिकता जानने लगा हूं। मैं आपको एक शरीफ और नेक आदमी समझता था। मगर मैं यह कहना चाहता हूं (---व्यवधान---) बैठिए, बैठिए। बैठ जाइए।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं? इनका शरीफ आदमी से क्या मतलब है और आज ये मुझे शरीफ आदमी क्यों नहीं समझते हैं? मैंने कौन सी बदमाशी की है, मैंने किस की आंख फाड़ी है? (---व्यवधान---)

मुख्य मंत्री : आप अपना जवाब सुन लीजिए। (---व्यवधान---)

श्री सुरेश भारद्वाज : अगर इनकी रियासत का कोई गरीब आदमी चुनकर यहां आ जाये तो राजा को तकलीफ हो जाती है। इनका यह कहने का क्या मतलब हुआ?

मुख्य मंत्री : कोई बात नहीं। (---व्यवधान---) अरे, चुप बैठ जाइए। (---व्यवधान---) देख लेंगे, देख लेंगे। इन्होंने जो कहा है मैं उस हिसाब से कह रहा हूं कि इनकी मानसिकता खराब है। Number one - Shimla is full-fledged capital of Himachal Pradesh and will remain so. दूसरी बात यह है कि जैसे इन्होंने कहा कि शिमला को स्मार्ट सिटी का स्टेटस नहीं मिला। इसको मुख्य मंत्री नहीं बनाता। वह केंद्र सरकार का फैसला होता है तथा उनके मापदण्डों के अनुसार बनाया जाता है। मैंने महसूस किया कि अगर धर्मशाला को यह दर्जा दिया गया है तो शिमला को इससे बड़ा नहीं तो कम-से-कम धर्मशाला को जो दर्जा मिला है वह मिलना चाहिए था। मगर यह मेरा फैसला नहीं है और इसमें हमारा कोई लेना-देना नहीं है। यह मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब और एम0सी0 ने अपना केस प्रैजेंट किया। मुझे खुशी है कि शिमला का दर्जा बढ़ाने के लिए दोबारा से बातचीत हो रही है और मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। अभी तो वहां पर कोई मुलाजिम

8.3.2017/1710/av/ag/2

नहीं है मगर जब वहां पर सचिवालय जायेगा और दूसरे कार्यालय खुलेंगे तो उस समय सोचा जा सकता है। अभी इनिशियल स्टेज है और सरकार का इसके बारे में अभी कोई विचार नहीं है।

अध्यक्ष : आप एक-एक करके बोलिए तब समझ आयेगा। सारे बोलेंगे तो कैसे पता लगेगा कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। एक-एक सदस्य बोलिए। (---व्यवधान---) श्री रविन्द्र सिंह जी, आप बोलिए।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां पर हमारे 37-38 माननीय सदस्य बोले हैं और अपने विचार रखें मगर उन पर मुख्य मंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इन्होंने अपने सवा घंटे के भाषण को गोलमोल करने की कोशिश की है। यहां पर एक-एक विधायक ने जो अपने-अपने विषय उठाये उन सभी के ऊपर मुख्य मंत्री जी को जवाब देना चाहिए था। दूसरा मेरा विषय यह है कि मुख्य मंत्री जी ने हमारे माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज जी के लिए जो टिप्पणी की है कि मैं इनको शरीफ समझता था तो शरीफ का उल्टा क्या होता है? (---व्यवधान---) आपकी विधायकों को जवाब देने की मंशा नहीं है। आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं इसलिए हम इस सदन से वॉकआउट करते हैं।

(विपक्ष के सभी सदस्य वॉकआउट करके चले गए।)

श्री वर्मा द्वारा जारी

08/03/2017/1715/टी0सी0वी0/ए0एस0/1

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हरेक मेंबर कई किस्म की बात करते हैं, I can't answer to each and every point raised by all of the House, this side or that side of the House. जो मैन बातें थी, वह मैंने कही है और ऐसा ही हमेशा होता है। यहां पर चर्चा में कितने मेंबर ने हिस्सा लिया और हर मेंबर ने अलग-अलग सवाल उठाये। Chief Minister

is not expected की वो हर प्रश्न का जो उन्होनें उठायें हैं उसका उत्तर दे सके इस भाषण के अन्दर। ये राज्यपाल महोदय का अपमान है, ये उनके अभिभाषण को पास करने के बदले में वॉकआउट करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब से हमने धर्मशाला में शीतकाल में जाना शुरू किया है और जो दफ़्तर आज से पूर्व वहां पर खोले गये हैं, उनके नोटिफिकेशन की प्रति मैं सभापटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं।

तो प्रश्न यह है कि इस सदन में एकत्रित सदस्य महामहिम राज्यपाल महोदय का दिनांक 1 मार्च, 2017 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए ह्दय से आभार प्रकट करते हैं।

प्रस्ताव स्वीकार।

अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, 9 मार्च, 2017 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला- 171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 8 मार्च, 2017 **सचिव।**